THE UNION BUDGET 2018-19 — *Contd.*[+]

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट देश के सामने रखा है ...(**व्यवधान**)... यह बजट देश के किसान, देश के नौजवान और देश के हरेक नागरिक को ...(**व्यवधान**)... * देने वाला बजट है। इस बजट में इस देश के लोगों को * किया गया है। ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं पहले इस देश के किसान की बात करना चाहूंगा कि इस सरकार ने किस तरह * दिया है। सरकार ने कहा है कि हम किसान को उस की लागत का डेढ़ गुना एम.एस.पी. देंगे। ...(**व्यवधान**)... यह इन्होंने किसान को * करने के लिए किया है। महोदय, आज किसान आत्महत्या कर रहा है। ...(**व्यवधान**)... किसान अपनी उपज को मार्केट से कम दाम पर बेच रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो एम.एस.पी. का वायदा किया है, आज से दो साल पहले, इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था और कहा था कि हम एम.एस.पी. से डेढ़ गुना दे ही नहीं सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... और जब यह सरकार वर्ष 2019 में चुनाव सामने देख रही है, तो यह पलट गयी है। यह ऐसा किसानों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही है ताकि चुनाव में इन्हें फायदा हो और ये फिर से चुनाव जीत सकें। महोदय, पूरे देश में इन का विरोध हो रहा है, इसलिए इन्होंने एम.एस.पी. का वायदा किया है और वह भी एक तिकड़म है, जिसे किसान समझ न पाए, वह यह सरकार कर रही है। सर, इस के लिए तीन तरह का फॉर्मूला है – A2 actual paid out cost होती है, दूसरा है A2: +FL, that is, actual paid out cost plus imputed value of family labour और तीसरा है, जिसे लागू करना चाहिए, C2 – comprehensive cost including input, rental value of owned land and interest on value of owned capital assets, महोदय, यह सरकार किसानों को * दे रही है जबकि किसान को C2+50 per cent मिलना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस स्थिति को स्पष्ट करें कि वे किसान को क्या दे रहे हैं? डेढ़ गुना बोलने से कुछ नहीं होगा, किसान के लिए यह साफ होना चाहिए। इस देश के 70 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं और उनके साथ * यह सरकार हर चीज में * कर रही है, हर व्यक्ति के साथ * कर रही है। इन्होंने कहा कि ये किसानों के लिए 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' लाए हैं। इससे बड़ा * किसानों के साथ और कोई नहीं हो सकता है। बीमा क्या है, इन्होंने 2016-17 में 22,345 करोड़ प्रीमियम कलेक्ट किया और किसानों को कितना दिया? इन्होंने किसानों को 6,625 करोड़ दिया, तो बाकी प्रीमियम कहां गया? आपने किसानों से तो पैसा ले लिया और किसान अभी भी जो 55 फीसदी मांग रहा है, जिसके लिए प्रीमियम दिया है, जो उसको नुकसान हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। यह सारा पैसा कहां गया, किसी को कुछ पता नहीं है। इसी तरह से ये कर रहे हैं। ये 'स्वास्थ्य योजना' लेकर आये हैं, यह वही है। इसमें प्रीमियम के लिए कलेक्ट होगा, बड़ी-बड़ी इंश्योरेंस कम्पनियों को फायदा होगा और आम आदमी को पांच हजार तो क्या पांच रूपए भी नहीं मिलेंगे।

दो साल पहले इसी तरह की सरकार योजना लेकर आई थी कि ये एक लाख रूपया 'स्वास्थ्य बीमा योजना' में देंगे। उस योजना का क्या हुआ? दो साल में वह योजना कहां है? सरकार और वित्त मंत्री जी बताएं कि यह योजना कहां है? यह योजना कहीं नहीं है। यह योजना पेपर्स में आई और पेपर्स में ही खत्म हो गई। लोग उस योजना को ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं इस सरकार

+ Further discussion continued from the 8th February, 2018.

* Expunged as ordered by the Chair.

से यह कहना चाहता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि ये लोग नहीं सुनेंगे। जो बीजेपी में, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। इन लोगों में अहंकार है, तो मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश के नागरिकों से यह कहना चाहता हूं, देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं और देश के किसानों से कहना चाहता हूं कि इनको पहचानिए। मैं एक बात में माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा, लोग मुझसे मतभेद कर सकते हैं, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। मैं इस बात को सौ फीसदी स्वीकार करता हूं। महात्मा गांधी ने कहा है कि आप चाहे कोई भी काम करिए, सब बराबर हैं। आप देश के प्रधान मंत्री हो, चाहे आप स्वच्छता वाले हो, चाहे आप पकौड़ा बेचें, सभी लोग समान हैं, क्योंकि dignity of labor होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने सही कहा है, लेकिन मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब एक पकौड़ा बेचने वाला अपना पेट काटकर अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसको इंजीनियर बनाता है, उसको डॉक्टर बनाता है, उसको CA बनाता है, तब क्या वह चाहता है कि उसका बेटा भी उसकी बगल में खड़ा होकर पकौड़ा बेचे? चाय बेचने वाले का बेटा प्रधान मंत्री बन सकता है, लेकिन प्रधान मंत्री यह चाहते हैं कि पकौड़ा बेचने वाला बेटा पकौड़ा बेचने वाला ही बने। मैं जानता हूं कि प्रधान मंत्री जी एक पिता की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आदरणीय अमित जी तो जान सकते हैं। मैं माफी चाहूंगा, अमित जी तो इस देश में एक ही हैं, एक भाई शाह जी तो जान सकते हैं कि पिता की क्या पीड़ा होती है। जो आदमी अपना पेट काट कर बच्चे को पढ़ा रहा है, आज उसको क्या हो रहा है? आज जब कहीं किसी नौकरी के लिए जगह निकलती है, अगर कहीं पर किसी सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए जगह निकलती है, तो उसके लिए CA पढ़ा व्यक्ति जाता है, MBA पढ़ा व्यक्ति जाता है। जब यह बात इस देश का प्रधान मंत्री कहे कि आप पकौड़ा बेचिए, तो उस नौजवान के ऊपर क्या बीतती होगी? जो नौजवान पढ़ा-लिखा है, उसके आत्म-सम्मान का क्या होता होगा कि MBA करने के बाद उसको कहा जाए कि आप पकौड़ा बेचिए, डॉक्टरी करने के बाद उसको कहा जाए कि आप पकौड़ा बेचिए। उसके आत्म-सम्मान का क्या होगा? प्रधान मंत्री जी ने कम-से-कम उनसे यह कहा होता कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आज उनको आपका साथ चाहिए। आज आप उनको हतोत्साहित मत करिए और आप उनके आत्म-सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। अगले साल देश के 13 करोड़ नौजवान वोट देंगे और वे आप लोगों को देख रहे हैं और वे देख रहे हैं कि आप लोगों की क्या सोच है। आप लोग उस नौजवान के लिए क्या चाहते हैं, वह सब देख रहा है। आप लोगों को वह ही बताएगा कि क्या सम्मान होता है और आप इस देश की आत्मा के साथ किस तरह का खेल खेल रहे हैं। श्री अमित शाह जी ने, जब उनका पहला भाषण था, अपने उस पहले भाषण में उन्होंने कहा था कि मैंने गरीबी को पास से देखा है। आदरणीय अमित शाह जी, गरीबी को देखना नहीं है, गरीबी को महसूस कीजिए। अगर आप गरीब नहीं रहे, तो गरीब को देखिए मत, बल्कि उसकी गरीबी को महसूस कीजिए। आप गरीबी को तभी महसूस कर सकते हैं, जब उसकी जगह अपने आपको खड़ा करके देखेंगे। आपने कहा कि हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन में 6 करोड़ टॉयलेट्स बना दिए हैं और उसके लिए और पैसा दिया है। उसमें तो आपने बजट कम कर दिया है, लेकिन क्या आपने उन 6 करोड़ टॉयलेट्स को देखा है कि उनका हाल क्या है? आप एक टॉयलेट बनाने के लिए 12 हज़ार रूपये देते हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): सी.एम. रमेश जी, हो गया है, बस, अब आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: क्या 12 हज़ार रूपये में टॉयलेट बन सकता है? शौचालय बन सकता है? आप उन शौचालयों को जाकर देखिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह चाहूंगा, जो वहां — ये लोग गांव तो कम जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उन शौचालयों में जाकर एक बार अंदर खड़े होइए, दरवाजा बंद कीजिए और बस दो मिनट खड़े रहिए, आप लोगों को शौचालय समझ में आ जाएगा कि यह शौचालय क्या होता है। ...**(व्यवधान)**... क्या है, आप बताएं? उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी कुछ इशारा कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): मैं उनसे कह रहा हूं कि उन्हें ऐसे पीछे नहीं खड़े होना चाहिए। ऐसे तो वे हर वक्त पीछे आकर खड़े हो जाएंगे। सॉरी, मैं उनसे कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं।

श्री नीरज शेखर: मुझे लगा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं भी यही कहना चाहता था।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): श्री वि. विजययाई रेड्डी, आप बैठिए।

श्री नीरज शेखर: मैं यही कह रहा था कि क्या आप 12 हज़ार रूपये में शौचालय बना सकते हैं? आप इसको 6 करोड़ मत बनाइए, इसको 3 करोड़ ही बनाइए, लेकिन उसको 25 हज़ार रूपये दीजिए, ताकि उसमें कुछ काम हो सके, उसमें पानी का इंतजाम हो सके। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसमें यह हो रहा है कि वह कुछ दिनों के बाद स्टोर बन रहा है।

मैंने समाचार-पत्र में एक घटना पढ़ी कि एक व्यक्ति ने घर के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसको घर का कब्जा तो मिला नहीं, टॉयलेट का मिल गया। वह उसी में रहा है। यह वाक़या आश्चर्यचकित करने वाला है। यह सरकार लोगों को कैसे-कैसे* कर रही है। मैं यही कहना चाहता हूं। मेरे एक और साथी बोलने वाले हैं, इसलिए मै जल्दी-जल्दी, दो चार चीज़े कहना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कहना चाहता हूं। माननीय चिदम्बरम जी ने यह विषय उठाया था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब यह 140 डॉलर प्रति बैरल है, तब भी हम लोगों को 75 रूपये में मिल रहा है और आज, जब 68 डॉलर प्रति बैरल है, तब भी हम लोगों को 75 रूपये में मिल रहा है। यह कौन-सा अर्थमेटिक है? मैं यह माननीय वित्त मंत्री जी से दसवीं बार, वह भी सदन में पूछ रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इसको मार्किट से जोड़ दिया है, तो यह कौन-सा अर्थमेटिक है? मैं माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछ चुका हूं। आप इस देश की जनता को कम-से-कम यह तो बताएंगे कि यह कौन-सा अर्थमेटिक है? यह कौन-सी मार्किट वैल्युएशन है कि जब यह 140 डॉलर प्रति बैरल है, तब भी 75 रूपये में हम लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, किसान डीज़ल खरीद रहा है? आज भी वही स्थिति है। ये इसके बारे में बता दें। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, इस देश के लोग जानना चाहते हैं कि यह कैसा अर्थमेटिक है।

महोदय, मैं दूसरी बात उज्जवला योजना के बारे में कहना चाहूंगा। क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने वह बलिया से शुरू की थी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यह बड़ी अच्छी योजना

---

* Expunged as ordered by the Chair.

है। मैं मानता हूं कि कई लोगों को गैस सिलेंडर मिले हैं, लेकिन उस सिलेंडर का फायदा क्या है? माननीय वित्त मंत्री जी यह बता दें कि वह अगली बार कितनी बार रिफिल हुआ है? लोगों ने वह चूल्हा ले लिया है, वह चूल्हा भी उनको 16 सौ रूपये में मिला है, लेकिन उन लोगों को यह नहीं बताया गया कि आपको यह पैसा बाद में, हर गैस सिलेंडर के साथ धीरे-धीरे देना पड़ेगा। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए। आप लोगों को * मत कीजिए। आप 3 करोड़ से 8 करोड़ कर दीजिए, सबको गैस चूल्हा मिल जाए, हम लोग यह चाहते हैं, लेकिन यह सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। जो भी नीति बनाए, वह स्पष्ट नीति बनाए। ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): श्री नीरज शेखर जी, आपकी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए एक और सदस्य हैं।

श्री नीरज शेखर: उपसभाध्यक्ष जी, मै दो चीजें और बोलना चाहता था। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री नीरज शेखर: महोदय, मैं नेशनल हाईवे के बारे में बोलना चाहता था। मैं बार-बार सुन रहा हूं। ये पूरे देश में नेशनल हाईवे बना रहे हैं। यह 32 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 40 किलोमीटर रोज बन रहा है। हमारे यहां माननीय मंत्री, आदरणीय नितिन गडकरी जी ...(**व्यवधान**)... आज से डेढ़ साल पहले ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): बैठिएगा अभी। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर: उन्होंने नेशनल हाईवे 31 का शिलान्यास किया था, लेकिन आज डेढ़ साल गुजर चुके हैं, उस पर एक रोड़ी तक नहीं आई है, उस पर न डीपीआर हुआ है, न कुछ हुआ, न उसका अधिग्रहण किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ये सारी योजनाएं ही ऐसी हैं? माननीय नितिन गडकरी जी लखनऊ गए और वहां, उत्तर प्रदेश को 2 लाख करोड़ ...(**व्यवधान**)... 2 लाख करोड़ ...(**व्यवधान**)... तय किया गया। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): नीरज शेखर जी, तुरंत समाप्त कीजिए।

श्री नीरज शेखर: उपसभाध्यक्ष जी, मेरा आखिरी प्वाइंट है। सर, दो मिनट दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): तुरंत खत्म कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर: सर, मुझे कल नहीं बोलने दिया गया, मैं कम-से-कम ...(**व्यवधान**)... पांच ...(**व्यवधान**)... घंटे यहां बैठा रहा।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, आप घड़ी में देखिए कि आपका टाइम कितना हो गया है।

श्री नीरज शेखर: आधा घंटे था। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): आपके एक और सदस्य हैं। घड़ी की गड़बड़ी के कारण प्रॉब्लम है, इसलिए close it.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री नीरज शेखरः महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बार-बार कहते हैं कि हम 18 हजार गांवों में इसे लाये हैं। मैं इसके सही आंकड़े जानना चाहता हूं, क्योंकि यह काम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में हुआ है। जब से आपकी यह दीनदयाल उपाध्याय योजना आई है, मैं जानना चाहूंगा कि उसमें क्या काम हुआ है? ...(**व्यवधान**)... मैं बलिया जिले के बारे में जानता हूं, यहां पर कहा गया कि आप दीनदयाल उपाध्याय योजना में एस्टीमेट बनाइए। वहां चार सौ करोड़ का एस्टीमेट बना और पैसे कितने मिले? 55 करोड़ रूपए मिले। वे 55 करोड़ रूपए किस चीज पर खर्च हो रहे हैं? वे गांव वालों के घरों में मीटर लगाने के लिए खर्च हो रहे हैं। यहां गांव का मजदूर, किसान दो हजार बीस रूपए नहीं दे पा रहा है, वहां अब हर महीने उसको लगेगा, ...(**व्यवधान**)... हजार से डेढ़ हजार रूपए का मीटर लग जाएगा। सरकार लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं बताती? दीनदयाल उपाध्याय योजना में बस मीटर लग रहे हैं ...(**व्यवधान**)... ये मीटर कब तक लटके रहेंगे? इस तरह आप गरीबों और किसानों की बात करते हैं? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल)ः नीरज जी, आप समाप्त करें। मैं अगला नाम लूंगा।

श्री नीरज शेखरः अंत में, महोदय, मैंने एक प्रश्न माननीय वित्त मंत्री जी से एनपीए के बारे में पूछा था कि बड़े उद्योगपति घरानों के जो एनपीए हैं, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है? माननीय प्रधान मंत्री जी बार-बार यह कह रहे हैं कि यह यूपीए का पाप है, जो हम उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह पाप यूपीए और एनडीए में बंट जाए। मैं जानना चाहता हूं कि 2014 के बाद आपने कितने ऋण उद्योगपतियों को दिए हैं? 2014 से पहले इनके पाप और 2014 के बाद आपके पाप, ...(**व्यवधान**)... मैं चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट हो जाए। यह डिटेल माननीय वित्त मंत्री जी नहीं बताते हैं। उनको बताना चाहिए, ...(**व्यवधान**)... भई, पाप बंट जाएगा, तो पाप बिल्कुल अच्छी तरह उठा लेंगे। ...(**व्यवधान**)... जो 2014 के बाद पाप किया है, वह आपने किया है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल)ः धन्यवाद। श्री मुत्तुकरूप्पन। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए।

श्री नीरज शेखरः महोदय, हम लोगों का तीस मिनट का समय था, आपने काट कर 14 मिनट कर दिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल)ः हमने नहीं किया। यहां आपके 11 मिनट हैं और दो सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री नीरज शेखरः महोदय, ये नहीं बोल रहे हैं। मैं जनधन योजना के बारे में जानना चाहूंगा। पूरी सरकार कह रही है कि हमने 31 करोड़ जनधन में एकाउंट खोल दिए और उनमें 71 हजार करोड़ रूपए आ गए हैं। ...(**व्यवधान**)... ये रूपए लोगों ने जमा किए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 8 नवंबर, 2016 के बाद उन जनधन खातों में सरकार ने कितने रूपए डाले हैं? क्योंकि उन खातों में पंद्रह-पंद्रह लाख रूपए आने वाले थे, तो उनमें सरकार ने कितने डाले हैं? यह भी मैं जानना चाहूंगा। हमारे नेता जी बैठे हुए हैं, आदरणीय राम गोपाल यादव जी, इन्होंने हमसे कहा था कि आदर्श गांव योजना में हम लोगों ने नहीं आना है। मैं जानना चाहूंगा, हम लोग बार-बार इस बारे में पूछ रहे हैं कि प्रधान मंत्री आदर्श गांव में यह सरकार हम लोगों

को क्या दे रही है? हमें पूरे उत्तर प्रदेश में एक गांव चुनना है, ...(**व्यवधान**)... एमपीलैड तो दूसरा है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अभी मैं दूसरा नाम लूंगा, आपका बंद हो जाएगा। कृपया खत्म कीजिए।

श्री नीरज शेखर: महोदय, खत्म तो करने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): आपके पांच मिनट ज्यादा हो गए हैं, अब ठीक नहीं है। मैं अगला नाम पुकारूंगा, श्री मुत्तुकरूप्पन।

SHRI RAVI PRAKASH VERMA (Uttar Pradesh): Sir, he should be given time. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Please conclude your speech.

श्री नीरज शेखर: सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You are not concluding. ...(*Interruptions*)...

श्री नीरज शेखर: महोदय, मैं एक मिनट का समय लूंगा। मैं केंद्र सरकार से यही चाहता हूं, आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूं कि आप इस देश के न किसान को भ्रमित करिए, न नौजवान को भ्रमित करिए, न इस देश के अल्पसंख्यकों को भ्रमित करिए। इस देश में आज स्थिति यह हो गई है कि हमेशा लड़ाई का माहौल लगता है, कभी यह हो रहा है कि ट्रिपल तलाक के लिए लड़ाई हो रही है, कभी ऐसा लगता है कि हम लोग पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। इस तरह इस देश में कभी स्थिरता नहीं दिख रही है। हमेशा लगता है कि हम लोग किसी लड़ाई में रह रहे हैं, हमेशा युद्ध का माहौल सा रहता है। मैं सरकार से चाहूंगा कि लोगों के मन में शांति रहे, सद्भाव रहे, ऐसा काम सरकार करे।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, धन्यवाद।

श्री नीरज शेखर: मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Now, Shri S. Muthukaruppan.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, please give me two minutes.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अगर आप बैठना चाहेंगे, तो मैं टाइम दूंगा, नहीं तो नहीं। ...(**व्यवधान**)... Again, you should not make protest.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, the Members of Telugu Desam Party are also part of the ruling dispensation. The BJP and the Telugu Desam Party together have formed the Central Government. Their demand is that they want justice. From

[Shri V. Vijayasai Reddy]
whom are they demanding justice? ...(*Interruptions*)... They are in power in the State of Andhra Pradesh; they are in power at the Centre. From whom are they demanding justice? It is they who have to do justice for this country and for the State of Andhra Pradesh. ...(*Interruptions*)...

Sir, yesterday, hon. Chairman gave a ruling that one Cabinet Minister can give a suggestion to another Cabinet Minister. That was the ruling which was given. I would like to know from the Chairman whether there is any rule under which a Minister can give an assurance to another Minister, especially considering the fact that both of them are Ministers of State in their respective ministries.

My second point is that yesterday the Minister of State in the Ministry of Science and Technology began his speech by saying, "on behalf of the Government" and he ended his speech with a request to the Government to do justice. Is he part of the Government? If they are part of the Government, let them resign from the Government and ask for justice. First, they should resign from the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Then only, justice will be done. The justice, which they are demanding, can be done to the State of Andhra Pradesh only after they submit their resignation. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Thank you. Now, Shri S. Muthukaruppan.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu): * Hon'ble Vice Chairman Sir, I am very happy to make my speech in my mother tongue Tamil, for the first time, in this august House of historical importance.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You have four minutes.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, my Party was allotted 38 minutes. ...(*Interruptions*).. Till now, we have taken only 10 minutes. So, 28 minutes are still left. …(*Interruptions*).. Why are you restricting our time unnecessarily?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): I am telling that there are four minutes for you.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: No, Sir. It cannot be accepted. …(*Interruptions*)… Sir, 38 minutes were already allotted to the AIADMK Party. …(*Interruptions*)…

---

*English translation of the Tamil Speech.

Our senior member, Shri Balasubramoniyan spoke for only ten minutes, and, you are saying that only four minutes are there for me. …(*Interruptions*)… We have 28 minutes. …(*Interruptions*)… This is my right to speak in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): In today's three hour discussion, the AIADMK has got eight minutes' time and there are two speakers from your party. …(*Interruptions*)…

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: No, Sir. …(*Interruptions*)… AIADMK's time was 38 minutes. …(*Interruptions*)…

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, the other Member has already left. ……(*Interruptions*)…

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You can take eight minutes only if one speaker is there. …(*Interruptions*)… Please go ahead.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: This is violation of justice. …(*Interruptions*)… What is this happening? …(*Interruptions*)… Sir, 38 minutes were allotted to AIADMK Party. …(*Interruptions*)… Only our senior colleague, Shri Balasubramoniyan has spoken for ten minutes. Rest of the 28 minutes we are having. You are restricting it to four minutes, five minutes. …(*Interruptions*)…

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Please start your speech.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN:* Hon'ble Vice Chairman Sir, I am elated to make my speech in my mother tongue Tamil, for the first time, in this august House of historical importance. I am overjoyed to inform this to you. In the Budget 2018-2019, there are many welcome measures. But Tamil Nadu has been neglected in various issues. I would like to point out that sufficient fund is not allocated to Tamil Nadu. I would like to point out this briefly. As far as BJP Government is concerned, during the time of our late Chief Minister, goddess of our heart, Hon'ble Puratchithalaivi Amma, we have worked as an unwritten ally of the BJP Government. We have assisted them at many circumstances. Moreover, we have supported the BJP Government at crucial times. But, the fund that is due to be allocated to Tamil nadu, is not allocated. It is my duty to point out this, through our Hon'ble Chairman, to Hon'ble Member Mr. Amit Shah, who is the National President of Bharathiya Janata Party. Now, I would like to submit the details of Union Budget 2018-2019.

This Budget aims to strengthen the basics of New India. This Budget had paid attention to various sectors from agriculture to infrastructure. On the one hand, this Budget mentions about the health schemes to eliminate the sufferings of the poor and

*English translation of the Tamil Speech.

[Shri S. Muthukaruppan]
the middle class. On the other hand, this Budget also has included certain schemes for enhancing the income of small scale industrialists. Therefore, on behalf of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), we welcome this Budget. This Budget 2018-2019's total expenditure is more than ₹ 24.42 lakh crore. The total receipt for this year is estimated to be more than ₹ 24 lakh crore. We are proud to say that Tamil Nadu occupies the second place, in the list of highest revenue yielding States to India. But, at the same time, we are not satisfied that sufficient fund is not allocated to Tamil Nadu and the Tamil people. This entire country knows about the arduous struggle of our Hon'ble Puratchithalaivi Amma to get sufficient funds from the Centre for Tamil Nadu. It is really distressing that the same situation continues even today. It is my duty to point out this expressively to the Hon'ble Government.

For example, during the last December, 2015, Tamil Nadu experienced an unprecedented rainfall and flood. There was severe loss of materials. All the agricultural crops were destroyed. Farmers were severely affected. Hon'ble Puratchithalaivi Amma met Hon'ble Prime Minister of India twice and demanded that ₹ 25,912.45 crore has to be allocated to Tamil Nadu for undertaking relief and rehabilitation measures. But, then, the Central Committee presented a field report. One year had passed after the report was submitted. But the relief package was not given even after one year. Therefore, the Union Government had to accept the demand of Tamil Nadu Government and relief fund had to be provided immediately. I would like to submit this demand to the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Ministers.

Next, Vardah cyclone devasted Tamil Nadu in December, 2016. Thousands of trees were uprooted in coastal districts of Tamil Nadu including Chennai. Electrical poles were mangled. Business and Industry became inoperative. There was huge financial loss to Tamil Nadu and to the people of Tamil Nadu. The Government of Tamil Nadu requested the Union Government to allocate ₹ 22,573 crores for relief. But it is distressing that not even a single rupee was given to Tamil Nadu.

At the same time, due to the severe drought that affected Tamil Nadu last year, 32 districts of Tamil Nadu were announced as drought hit districts. It was announced that out of 16,682 revenue villages, 13,305 villages were drought hit. We requested that the Centre has to come forward to provide ₹ 39,565 crore as drought relief package. But the Centre did not heed to our demand. It causes agony to us.

Sir, therefore, I reitereate and request that the Union Government under the leadership of Mr. Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India, had to give due financial assistance to Tamil Nadu without further injustice and without further delay. Tamil Nadu is the state that gives maximum revenue to the Centre.

3.00 P.M.

Cauvery Delta is the life line of Tamil nadu. Farming has become very difficult there. Once upon a time, at Thanjai Delta Region, crops are threshed with the help of elephants as threshing with the assistance of cows was not enough. But today, the farmers of Thanjai Delta are in a position not to undertake agriculture.

Water is essential for agriculture. Irrigation facilities have to be given to all parts of the country. To implement this, interlinking of national rivers is a must. Hon'ble Puratchithalaivi Amma had persuaded the Centre for nationalization of all rivers and particularly for interlinking of South Indian rivers. A permanent solution to river water disputes of south India states, will be obtained only if south Indian rivers are interlinked.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Only one minute is left.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, we have 28 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): I am talking about the time that I have given. Only one minute is left.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: *As per the request of Goddess of our Heart, Hon'ble Puratchithalaivi Amma, the Union Government had to take steps to interlink south Indian rivers under South Indian River Development Project. This is the first step in protecting the welfare of Tamil Nadu farmers.

Cauvery river is the livelihood of lakhs of farmers of Tamil Nadu. The entire world knows about the legal battle waged by Hon'ble Puratchithalaivi Amma and the grand success she had achieved in obtaining Cauvery water to Tamil Nadu from the state of Karnataka. Puratchithalaiv Amma was hailed by people as the "Cauvery Mother who retrieved Cauvery" as she was responsible for notifying the final order of Cauvery Water Disputes Tribunal in the gazetteer of Government of India.

In Cauvery river water issue, as per the interim order of Cauvery Water Disputes Tribunal, Karantaka did not release the due share of Cauvery water to Tamil nadu during cropping seasons. The Supreme Court of India had ordered many times that Cauvery water had to be given to Tamil nadu and that Cauvery Management Board had to be set up immediately without further delay. But the Union Government had taken an opposite stand with regard to this issue. Tamil nadu farmers consider this as the greatest injustice done to Tamil nadu and to Tamil nadu farmers. Therefore, the Union Government had to take proper steps to implement setting up of Cauvery Management Board, as per the Supreme Court Order. The Supreme Court had already

* English translation of the Tamil Speech.

[Shri S. Muthukaruppan]
issued an order that Cauvery Management Board shoud be set up in four days. But, in the third year, Attorney General of India had filed a revision petition at the Supreme Court challenging this order. In the release of Cauvery Water, politics is being done.

Sir, I request , through the Chairman of this House, that due water from Cauvery has to be released to Tamil Nadu from Karnataka.

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): समाप्त करिए। Thank You.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: * I request the Hon'ble Members from Karnataka that lakhs of hectares of agricultural land in Delta region is drying in Tamil Nadu. Due share of Cauvery Water to Tamil Nadu should be released immediately by the Karnataka Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Thank you. समाप्त कीजिए। धन्यवाद।

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: * I request the Hon'ble Members from Congress Party as Congress is ruling the State Government of Karnataka, to release Cauvery water to Tamil Nadu.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): I will call other Member's name. Ask him to stop. It cannot go on record. Now it will not go on record. You conclude it.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, just give me one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You conclude it immediately.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: *I request the Hon'ble Members of Parliamentary Affairs to take proper steps. I once again request the Hon'ble Members here not to make politics in Cauvery issue. Tamil nadu farmers are dying. Lakhs of hectares of land in affected. I request the Hon'ble Members to support Cauvery Delta farmers, cutting across party lines. Cauvery water has to be released to Tamil Nadu immediately. I thank the Chairman for giving me this opportunity. Thank you. Vanakkam.

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): धन्यवाद। Shri Derek O'Brien, you have eight minutes.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, our opening speaker made his maiden speech. Whenever you think I am not making sense or not making an interesting point, you ask me to sit down, and I will sit down. Whenever you think so, I will sit down. I will not argue with you.

---

*English translation of the Tamil Speech.

Sir, 12 is a very important number. क्योंकि अगले साल तक, 12 ...(*Interruptions*)... I completely sympathise with the situation today in Andhra Pradesh. ...(*Interruptions*).. I completely sympathise with Andhra Pradesh. ...(*Interruptions*)... My friends, we are with you. ...(*Interruptions*)... We are with you. We know that you have been deprived. Do not deprive me by making this loud noise in my turn. We can work it out together. I have openly said that we are with you. If you still want to speak, that is your democratic right. Twelve is an important number. क्योंकि इस साल से पहले तक 12 घंटे बजट स्पीच होती थी। मेरी हिन्दी खराब है और बांग्ला ठीक है, लेकिन मैं आज हिन्दी में बोलने की ट्राई करूंगा। पहले 12 घंटे बजट स्पीच होती थी और लगभग 12 घंटे ही रेलवे बजट पर चर्चा होती थी। अब तो रेलवे बजट आउट हो गया है। मैं बजट पर कम बोलूंगा और रेलवे बजट, जिस पर पहले 12 घंटे डिसकशन होता था, मैं उसके ऊपर बोलूंगा।

महोदय, ओपनिंग बैट्समैन, अपोजिशन के श्री पी. चिदम्बरम जी से मैं एक्सपीरियंस लूंगा, क्योंकि उन्होंने 12 प्रश्न फाइनेंस मिनिस्टर से पूछे। मैं उसी सत्र को पकड़ कर 12 प्रश्न रेल मंत्री से पूछूंगा, because the Railway Minister has to answer these questions. These are hard questions. There will be no politics. There will be no rhetoric. मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने जो operating ratio publish किया है, तो उसमें operating ratio 95 per cent दिखा रहा है, लेकिन यह operating ratio गलत है, क्योंकि सुरेश प्रभु जी ने जब बजट प्रेजेंट किया था, तो उनका revenue का टारगेट ₹ 1,90,000 crore था और जब जेटली जी ने next time बजट present किया, तो ₹ 1,72,000 crore बोला है, लेकिन actual figure घट कर ₹ 1,59,000 crore हुई। तो यह गलत फिगर आ गयी थी, अभी पक्का हो गया है। My first question is this. I challenge this figure of 94 for operating ratio. The figure is in excess of 100 per cent. I am willing to be proved wrong on the floor of this House.

दूसरा प्रश्न capital expenditure के बारे में है। महोदय, expenditure दो किस्म का होता है– एक capital expenditure और दूसरा revenue expenditure. मैं एक सिम्पल उदाहरण दूंगा। हावड़ा से डानकुनी रेलवे लाइन रिपेयर होनी थी। A line has to be repaired. Then, the GM can repair the line because if he does not repair the line, there may be an accident. So, for the revenue expenditure, this money is used.

इसके आगे 5,000 करोड़ का Depreciation Reserve Fund नामक एक फंड था। वहां से यह खर्चा होता। उस 5,000 करोड़ वाले फंड के बारे में मेरा प्रश्न है कि क्यों इसे 5,000 करोड़ से घटाकर 500 करोड़ कर दिया गया? Why has the Depreciation Reserve Fund been reduced from ₹ 5,000 crore to ₹ 500 crore? Chances of accidents are there. But, now, you have to get it approved from Delhi. This is a serious issue. Let me know. They may be using the Sanraksha Account of ₹ 20,000 crore there. I don't know. I am asking this question. Please answer this question.

मेरा तीसरा प्रश्न वर्ष 2000 से 2014 तक रेलवे के CAGR (Compounded Annual Growth Rate) के बारे में है। यह साल 2014 में 6 प्रतिशत था। मैंने कैलकुलेट किया, तो यह CAGR

[Shri Derek O'Brien]

(Compounded Annual Growth Rate) लास्ट साढ़े तीन साल में घट कर अब 2 per cent हो गया। तो यह 2 per cent क्यों हुआ, आप यह हम लोगों को बताइए, हम लोग सुनेंगे।

मेरा चौथा प्रश्न है कि people always say here that all Rail Budgets would be political, that they would make political statements. It may be so. The BJP came and told us that it is not; you merge the two Budgets and there would be no politics. लेकिन यह पोलिटिक्स तो होनी है। जब पोलिटिक्स कर रहे हैं, तो कम से कम बता दीजिए कि पोलिटिक्स कर रहे हैं। आप यह देख लीजिए कि उत्तराखंड का budget allotment extra 170 per cent है। Rajasthan is 30 per cent plus over last year. यह गुजरात का देखिए। ठीक है, गुजरात को हमेशा मिलता है। यह 20 per cent है। We are happy. मध्य प्रदेश का 20 per cent है। अब Opposition-ruled States का देखिए। मैं तीन States के बारे में बताऊंगा– Delhi, Kerala and West Bengal. It is not plus, not zero; it is minus 40 per cent, minus 23 per cent and minus 40 per cent. क्यों? यह मैं पोलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं solid numbers से दे रहा हूं। मैं बैठ कर आंसर भी सुनूंगा।

Sir, then, I come to my fifth question. इतना डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवे-रेलवे कहा जा रहा है, तो इसमें मेरी तीन फिगर्स हैं। आपने एक साल में 800 किलोमीटर new railway lines का promise किया, लेकिन आपने कितना पूरा किया-400 किलोमीटर। Gauge conversion के बारे में आपने 900 किलोमीटर का प्रॉमिस किया, लेकिन आपने 550 किलोमीटर पूरा किया और doubling के बारे में आपने 1,800 किलोमीटर पूरा किया और doubling के बारे में आपने 1,800 किलोमीटर का प्रॉमिस किया, लेकिन आपने 900 किलोमीटर पूरा किया। तो यह 50 per cent का shortfall क्यों हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं।

Next is my sixth question. Is the Railway on the Union List or is it on the State List or is it on the Concurrent List? यह तो 7th Class में Civics पढ़ने वाला कोई बच्चा भी बता देगा कि it is on the Union List. My sixth question is: Why then is the Railway asking the State Governments to bear the cost of infrastructure? What happens to the North-East States? What happens to the poort States? यह 'फेंकू फेडरलिज्म' नहीं चलेगा। यह नहीं चलेगा, because simple point is that the State Governments must not bear. It is a Central subject. Next you will ask the Bengal Government to provide you for the Defence Budget also.

सर, मेरा सातवां प्रश्न बुलेट ट्रेन्स के बारे में है। All of us want technology. हम सब को बुलेट ट्रेन्स चाहिए। मुम्बई से अहमदाबाद नहीं चाहिए, लेकिन अमित भाई हैं, इसलिए he will be happy that it is from Mumbai to Ahmedabad. It does not make us so happy but it does not matter. Someone is happy. That's good. But where is the point in respect of the Bullet Train? We want the Bullet Train. Why are we opposed to the Bullet Train? We are not opposed to the Bullet Train. We are opposed to the alternative. To build one kilometre of Bullet Train, 180 करोड़ रूपये लगते हैं, ये conservative estimates हैं। जबकि dedicated freight corridor बनाने के लिए, जिसके जरिए आलू जाएगा,

सब्जी जाएगी, चीज़ें जाएंगी, लगभग 23 करोड़ रूपए लगते हैं। आप बताइए कि यह डिसीज़न क्यों लिया to make the bullet train first and not take up the dedicated freight corridor. You might tell me because Japan gave a loan to us. We can have another debate on how bad that loan was.

मेरा प्रश्न संख्या 8 है about policy. हमारी पार्टी तृणमूल की clear policy है। Railway में social responsibility, commercial viability – ये दोनों साथ चलते हैं। इस बारे में आपकी policy क्या है, वह बताइए, क्योंकि पूरे बंगाल में और यह सिर्फ बंगाल ही नहीं, हर स्टेट ने चिट्ठी लिखी है and said that they would stop eight Railway routes in Bengal. Why, because they are not profitable routes. Please look through. All the other MPs check your own States. My direct question is this. What is the policy of this Government on commercial viability? Will they not take into account social responsibility?

Sir, my ninth question is this. Everyone is talking about jobs.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You have only two minutes. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, if you ask me to sit down, I will sit down now. ...(*Interruptions*)... Because I have some points. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Yes, go on. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: We are waiting. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, this is very unfair. ...(*Interruptions*)... So many Members are waiting since yesterday. ...(*Interruptions*)... You just cannot curtail the time like that. ...(*Interruptions*)... We are prepared to sit late like yesterday. ...(*Interruptions*)... Kindly do not curtail the time. ...(*Interruptions*)...

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Others are waiting. ...(*Interruptions*)... Let the debate go on. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Yes, we will go on. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: All of us are waiting. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: We will wait till 10 o'clock. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Yes, we would like to wait. ...(*Interruptions*)... Do not curtail the time. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am in my flow. ...(*Interruptions*)... Sir, my ninth question is about safety. We are talking about jobs. Everyone wants jobs. Why are

[Shri Derek O'Brien]
the Railway Minister, the Finance Minister, the Pradhan Mantri not trying to generate jobs? Sir, 1,25,000 safety jobs are vacant in the Indian Railways. ...(*Interruptions*)... उन्हें तो कम-से-कम भर दो, as 1,25,000 jobs are vacant.

My tenth question is about Swachh Bharat. It is a good idea. In Bengal, we call it something else but it is doing very, very well. It is the best in the whole country. If you like Swachh Bharat so much, Mamata Di had given a Vision 2020 document. She wanted bio-toilets. My direct question to the Railway Minister, the Finance Minister and the Prime Minister is this. In your reply, please tell us how many bio-toilets in the Indian Railways you have started and in the next three years, that is, 2022 when you will finish because everything is for 2022.

Sir, my eleventh question to the Railway Minister, the Finance Minister and the Prime Minister is this. When you give zero allocation to a project, does that mean the project is over? We need to know that because there are many projects across the States which have zero allocation.

Sir, my last point is twelfth point. Then, I have one more point and then I am done. ...(*Interruptions*)... We are all with you with Andhra Pradesh. You have to move now from that side. Come over to this side soon. You will be better but we will talk ...(*Interruptions*)... I should not ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Your time is going by.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we have done some study for Bengal but Bengal is only one State. I would request all the hon. MPs, senior to me also, to study not the figure which has been given to you कि कितना मिला, percentage of total project cost जो है, उसकी तुलना में क्या मिला, because that is where all the jugglery is happening. In Bengal, you might say, 'Oh! You have got ₹ 4,500 crores or ₹ 5,000 crores this year.' In is only eleven per cent of the total allocation. I would request all the States not to be cheated by this *feku* federalism. You have to look at the percentage. The way this is happening, on this transport, I would say one line, "Please do not do to the Air India, what you have already done to the Indian Railways." Otherwise 5-7 साल बाद, again we will be discussing Air India, which is a great treasure of this country. Do not sell Air India. Do not sell it, you must improve it.

Sir, my last point, before I end, is this. We told you about demonetization, we warned you about GST. You were sitting there – not you Sir – the BJP was sitting there. They opposed GST. They came here and they are for GST. That is okay. We are always in the middle; that is why, we are consistent. The serious point on GST, Sir, is this. The Trinamool has always been for GST right from our manifesto in

2004 but here are the three points on the GST and, then, I conclude. We told you in July not to implement GST but *jabardasti* you wanted to do GST. You did the GST. Now, what is the situation? These are three crucial numbers on GST after my twelfth question. The first number; we have the Finance Minister – I have left the Railway Minister alone, let him go into his homework and come back through the Finance Minister and answer— and there are three questions to the Finance Minister. You kept a provision of ₹ 55,000 crores of money to be compensated to the States and you can allow 10 per cent this way or that way. Now, here is the bad number. आपने बजट में 55,000 करोड़ रूपये का प्रोविज़न रखा है। अगर छः महीने में compensation की figure ₹ 40,000 crores plus हो गयी, तो मेरा असान-सा prediction यह है कि next छः महीने में वह 40,000 और 40,000 मिला कर 80,000 करोड़ हो जाएगा, लेकिन आपने बजट में केवल 55,000 करोड़ का प्रोविज़न रखा है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि बाकी के 25,000 करोड़ आप कहां से नोट छाप कर लाएंगे? ...(**समय की घंटी**)... Right.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, समाप्त कीजिए।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, there are two more points on GST. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Please finish. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, there are two more points on GST. ...(*Interruptions*)... I am looking for answers. I am not doing any political speech but I am making a... ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Yes, you are making genuine points.

SHRI DEREK O'BRIEN: Now, the next point is on e-way bill. सर, e-way bill का concept क्या है? Truck, when it goes into the State, it should have the e-way bill and drive through the whole State, no checkpoint. बंगाल में कोई चेक प्वाइंट नहीं है, because 100 per cent ...(*Interruptions*)... I will send you because you have lots of answers to do. बंगाल में कोई चेक प्वाइंट नहीं है, क्योंकि वहां 100 परसेंट e-governance होने के कारण 100 परसेंट e-way bill जाता है। It is self-declared. In Bengal, it is self-declared. Now, all the truck operators are getting very upset because the e-way bill concept it not working. The only way to do this is by following the full e-way system. ...(*Interruptions*)... I end by giving you figures on GST. जीएसटी, जितना हायर नम्बर रहेगा, उतना खराब और जितना लोअर नम्बर होगा, उतना अच्छा। तो loss due to GST, हमारे बंगाल में lowest loss 580 करोड़ है, जबकि गुजरात का loss 1,100 करोड़, बिहार का loss 1,000 करोड़ और कर्नाटक का loss 2,000 करोड़ है। So, the system is not ready for GST. I have asked the Finance Minister and the Prime Minister, with the help of the Railway Minister, to answer my twelve questions and I have given you some points. ...(*Time Bell rings*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)... Now, please finish it ...(*Interruptions*)... No, it is way too much ...(*Time Bell rings*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: I am finishing. ...(*Interruptions*)... My last thought is, we were told by this BJP Government that they were elected four years ago and for 55 years, the Congress Party didn't do anything and that is why, they got elected. We use to say the same thing in West Bengal. For 34 years, the CPM didn't do anything and that is why, they got elected. Okay, they will elect you once. For 2016, when we got re-elected, we got re-elected on our work. You have to, if you want the people to believe you. For the first time, it is easy but you have to show development, real development and get re-elected on your work.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, धन्यवाद। अब आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री देरेक ओब्राईम: धन्यवाद, सर।

रेल मंत्री (श्री पीयूष गोयल): सर, बाकी तो इन्होंने काफी चीज़ें कहीं, लेकिन जनता को गुमराह करने की ...(**व्यवधान**)... कोशिश हो रही है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Don't interfere. ...(*Interruptions*)... He is not yielding also. ...(*Interruptions*)... आप बाद में बोलिए। ...(**व्यवधान**)... You speak after him. ...(*Interruptions*)... Yes, silence please. ...(*Interruptions*)... वे खड़े हैं। उनके बैठने के बाद intervene कर सकते हैं, बीच मे नहीं कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I only have one request.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: I have raised twelve questions. At the right time, I am willing to listen, even wait till 11'o clock in the night, for the answers. I have not done any politics. I have asked twelve questions, answer my twelve questions, answer Shri Chidambaram's twelve questions. ...(*Interruptions*)... That will be twenty four questions, a lot of homework to be done. आप आंसर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): धन्यवाद। ठीक है, अब आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री पीयूष गोयल: सर, हर बात का जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक स्पेसिफिक इश्यू, जिसमें लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में मैंने सोचा कि वह जरूर बता दूं। इन्होंने यह एक विषय उठाया कि वेस्ट बंगाल में कोई आठ ट्रेनें बन्द कर दी गई हैं। यह विषय उठाया गया है और ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): उन्होंने नहीं बोला है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DEREK O'BRIEN: I did not say. ...(*Interruptions*)... I did not say. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): No, no. Sit down. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री पीयूष गोयलः मैं यह विषय खत्म तो कर दूं। यह पब्लिक एकाउंट्स कमेटी जो मेरी बनाई हुई नहीं है, यह एक पार्लियामेंट की कमेटी है। इस कमेटी ने इन लाइनों को non-viable पाया और चूंकि इस कमेटी ने एक रिपोर्ट में इन लाइनों को non-viable कहा, तो लोकल जनरल मैनेजर, ने उसकी जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को देकर कहा कि इन रूटों में ट्रेन संचालन से हो रहे नुकसान में राज्य सरकार कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करे तो उन ट्रेनों को चलाने में सुविधा होगी? यह परम्परा कोई मैंने या इस सरकार ने शुरू नहीं की। माननीया ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थीं, तब भी ऐसी चिट्ठियां इश्यू की गई हैं। यह एक प्रक्रिया है पार्लियामेंट की, जो पी.ए.सी. की रिपोर्ट के ऊपर जनरल मैनेजर इश्यू करता है और उसके ऊपर मेरे colleague मनोज सिन्हा जी ने वहां जाकर आश्वस्त किया कि कोई ट्रेन बंद नहीं हो रही, तो बिना बात के इश्यू उठाकर कोई लाभ नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, धन्यवाद। Now, I have an announcement to make.

Hon. Members, on 7th February, Shri Derek O'Brien Member had raised an issue of not showing on Rajya Sabha T.V. first four to six minutes of his speech in Rajya Sabha on the Motion of Thanks on the President's Address and demanded that the matter be inquired into. He was supported by some other Members and the Leader of the Opposition. The Chair assured the agitating Members that the matter will be inquired into. Accordingly, a preliminary inquiry was conducted and it was found that there was a break in the live transmission of the Rajya Sabha from ...(*Interruptions*)... 1314 hours to 1318 hours–four minutes, when Shri Derek O'brien was speaking due to power failure. After the transmission resumed, the incident was regretted by the Rajya Sabha T.V. through a scroll. It was also flashed that the entire speech of Shri Derek O'Brien would be telecast in the evening at 2015 hours. Accordingly, the entire speech of Shri Derek O'Brien was telecast on the Rajya Sabha T.V. at 2015 hours. Hon. Chairman has, however, ordered a detailed inquiry into the matter.

Now, Shri Narendra Kumar Swain; not present. Shri C.P. Narayanan. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI C. P. NARAYANAN: Sir, I want to speak only on four points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You have four minutes.

SHRI C. P. NARAYANAN (Kerala): Sir, in the Centrally-sponsored schemes, the Central Government's share has been reduced and the State Governments are given the burden. ...(*Interruptions*)... Every State is being burdened with, whether it is education, health or other areas. This is one point that I want to mark. The second point is, for SC/ST, we used to allot from the Budget an amount proportional to their population in the country. Now, when the Five Year Plan has gone, NITI

[Shri C. P. Narayanan]
Aayog has brought a different scheme and because of that, every year, the allocation for SC/ST is going down very steeply affecting various programmes, which have to be implemented in their favour. My third point is regarding education and health. We claim that we are a country which has got the maximum number of young population. This is an advantage for us. But unless we educate them, feed them and keep them in good health this youth will become a burden on us. This is what is happening. The Right to Education Act, which is being implemented since a decade, has become very ineffective because every year budget allocation for the education is proportionately decreasing. Because of that, our claim that we can develop our youth as our major source of income, major source of wealth of the country in the coming decades has become a complete failure.

Regarding agriculture, my esteemed colleagues have spoken. Even though the Budget allocation is more than ₹ 13 lakh crores, actually it is ₹ 2.38 lakh crores only. More than ₹ 11.25 lakh crores are in the form of loans only. This amount has not been reflected in the Budget. It is the money given by the various banks but it is shown as given in the budget to the people. It is happening. Actually, the allocation for agriculture in the Budget is getting decreased year after. Because of these reasons, the farmers' suicides are increasing in various parts of the country. Unless we correct these mistakes our future will be very bleak. So, I think, a complete reversal of the policies of the Government regarding the Budget allocation is necessary. With these words, I conclude my speech. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): धन्यवाद। श्रीमती वंदना चव्हाण।

You have got three minutes, but I will give you five minutes.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Thank you so much, Sir. the senior Members have already made very eloquent points on economics, agriculture, railways, health plan, etc. Sir, with the limited time available, I will constrain myself only to dedicate my intervention for the children of the country, who are important stakeholders of India. Sir, this is for five reasons; one is the children under the age of 18 constitute 40 per cent of our population. They are voiceless. They are the hope of tomorrow. Last but not the least, I feel, it would be a befitting thing to do for all of us here on the 50th Anniversary of the Convention of Child Rights to which India is a signatory. In the Budget, there is always a hope that 6 per cent of the GDP is used for the education sector. However, it never happens. In spite of the reduced meager outlay, the Government has made some very welcome steps. But there are also some announcements which have been made which put us to doubt whether these will really see the light of the day. At the outset, I would like

to congratulate the Government for having taken steps to treat education holistically without segmentation from pre-nursery to class two. Sir, during the discussion on the National Education Policy, the Nationalist Congress Party was very emphatic that the Right to Education should have a backward and forward extension; backward from 0 to 6 because that is when the brain really develops, and later from 14 to later, we are all grassroot workers, we have realized that when the girl child finishes her primary education, 7th standard, most of the time, in the Government schools, she is married off. Once she is married off we know that she becomes a mother, and the child is malnourished, she becomes anaemic, and then, the entire family is pushed into impoverishment. Personally for me, the merging of primary and secondary education is one of the biggest highlights of the budget and, therefore, I would like to congratulate the Government. But it is worrying to see that though this holistic approach has been taken, there are different outlays for Sarva Shiksha Abhiyan and Rashtriya Madyamik Shiksha Abhiyan. Actually, if the intention of the Government was to merge the two, then the Budget provisions should have been together.

Secondly, the Government has announced the Eklavya Model Residential School. Surprisingly, they are not able to find the budgetary allocation in the school education budget. The Model Schools would see the light of day in 2022. As somebody has said before, whatever is not to be done is projected to be done in 2022. So, we really don't know whether it would see the light of day. On the one hand, the Budget talks about setting up of this chain of schools; on the other side, it cuts allocations of Kendriya Vidyalayas and Jawahar Navodaya Vidyalayas. In fact, as far as the higher education space is concerned, the total budgetary allocation for IITs has been decreased from ₹ 8,244 crores to ₹ 6,326 crores in 2018-19. There is a cut in the allocations for IIMs and the UGC. Education spending of the present Government in terms of total share of Central Budget has come down in the last four years. In 2015-16, it was 5.44 per cent; it came down to 4.68, then to 3.71 and now, this year, to 3.48 per cent, which is very, very alarming.

Then, Sir, the Government has laid stress on the use of technology in schools, leading us from blackboards to digital boards. It is, indeed, a welcome step. But if we do a reality check, the study reveals that only 62 per cent of all schools have electricity connections; 24 per cent have functional computers and nine per cent have an electricity connection and functional computers. Sir, one wonders how the operation of digital boards would take off. Even here, the School Education Budget document makes no mention of how this would be funded. In fact, it would be interesting to note that the budget for Digital India, e-learning, has come down from ₹ 518 crores to ₹ 456 crores.

Sir, I wish to say that while pushing technology, we have to realize that we cannot

[Shrimati Vandana Chavan]
take the place of teachers who are in flesh and blood. On the one side, we see the use of technology and, on the other we see that today one million teachers' posts are lying vacant, nine lakh in elementary school and one lakh in secondary schools.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You have one minute left.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Teachers' training programmes have not taken off. Therefore, this needs to be looked into. We talk about inclusive education but, unfortunately, our teachers have not been trained to identify the disabled, children with learning disabilities and so on.

Sir, if you keep looking, I really feel under pressure. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): No, no. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Also, Sir, it is very important that we have to be aware and sensitive about children's safety and the provisions of POCSO. Today, there are so many offences which are taking place against children, and it is very important that teachers know about provisions of the POCSO.

Sir, I would not touch upon health because I know I am running out of time, but here too, there is something that we really need to do because the budgetary allocation for health is merely five per cent higher than the earlier year.

I want to touch upon protection of children from abuse. This is very important. Sir, India is witness to increasing cruelty, abuse and violence against children. We know that the allocation for the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), which is mandated to investigate into instances of physical and psychological abuse, has been slashed...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): The time allotted to you is over.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Just one minute, Sir. Their Budget has been slashed down to 32 per cent.

Sir, I would just touch upon two points. Sir, the situation in the Observation Homes is very poor. They need our attention. I think the whole House has to join and make sure that the situation of the Observation Homes improves.

Climate change is one last issue which I feel has not been addressed by the Finance Minister. The Government should have made provisions because these children are the citizens of tomorrow and they need to live healthy lives. Thank you very much.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): धन्यवाद, वंदना जी।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज एक सदस्य बीमार हो चुके हैं। जो माननीय सदस्य खड़े हैं, उनमें से एक महिला सदस्य भी हैं, ऐसे तो ये बीमार हो जाएंगी, आप इस पर कोई decision लीजिए। यह अच्छा नहीं लगता है, आप इस समय चेयर पर बैठे हुए हैं और इस तरह से अन्य सदस्य खड़े रहें। ठीक है, उनकी अपनी पीड़ा है, आप उनके स्टेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो उनके साथ ...**(व्यवधान)**... आप कुछ भी करिए। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): मैंने रमेश जी से कहा है कि कम से कम बहन जी बैठ तो जाएं। मैंने उनको बैठने के लिए कहा है। मैंने यह भी कहा है कि खड़ा रहना ठीक नहीं है और आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: लेकिन ऐसे अगर कोई बात हो गई, तो जिन्दगी में इसका दोष आपके ऊपर जाएगा, क्योंकि चेयर पर आप बैठे हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): हां, ठीक है।

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आप अपने ऊपर दोष क्यों ले रहे हैं? आप इसका कोई समाधान निकालिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): श्री राम कुमार कश्यप आपके पास बोलने के लिए तीन मिनट का समय है।

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक फरवरी को बजट प्रस्तुत करना था, उससे एक दिन पहले मैं विचार कर रहा था कि वित्त मंत्री जी बजट में क्या लाने वाले हैं। मेरे मन में अचानक विचार आया कि कई सालों से एम.पीज. के वेतन का मामला अटका पड़ा था, मैंने मन बना रखा था कि अबकी बार एम.पीज. के वेतन और भत्तों के बारे में, मैं सदन में मांग रखूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले ही एम.पीज. के वेतन और भत्तों का प्रावधान कर दिया है और इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को सैल्यूट कर दिया है, यह इसलिए नहीं कि उन्होंने वेतन और भत्तों का प्रोविजन किया है, बल्कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से प्रोविजन किया है कि हर पांच साल बाद एम.पीज़ की सैलरीज़ रिवाइज़ हो जाएगी। वह तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि इतना एम.पीज़. का वेतन होगा, इतना उनका भत्ता होगा, जैसे कि राष्ट्रपति जी के बारे में किया है, परन्तु वित्त मंत्री जी ऐसी घोषणा करते, तो हमारे मीडिया के जो साथी है, वे उसको इतना उछाल देते, वे मोटे-मोटे अक्षरों में लिख देते कि एम.पीज़. ने अपना वेतन बढ़ा लिया और किसी को कुछ नहीं दिया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के निर्माण में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। यह किसानों की ही मेहनत है, जिसके कारण आज हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हैं, परन्तु खुद किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी है, क्योंकि आज खेती करना घाटे का सौदा हो गया है। बीज महंगा हो गया है, खाद महंगी हो गयी है, डीजल महंगा हो गया है और यहां तो बेमौसम बरसात से फसल खराब हो जाती है, इससे भी किसान की दयनीय स्थिति हो जाती है। किसान

[श्री राम कुमार कश्यप]

को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है, इसलिए भी उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। वैसे तो माननीय वित्त मंत्री जी ने किसानों की खुशहाली के लिए, उनको राहत देने के लिए कई घोषणाएं की हैं, उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि सरकार ने किसानों की उत्पादन लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का वायदा किया है। यह जो वायदा किया है, आने वाली गर्मियों में जो फसलें आएंगी, जो खरीफ की फसल है, उसके लिए वायदा किया है। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जो समर्थन मूल्य है, जो सर्दियों की फसलें हैं, जो रबी की फसलें हैं, उनको समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम तो पहले ही कर दिया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि हमारी जो सर्दियों की फसलें हैं, क्या उनको भी डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दे दिया गया है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में धान का समर्थन मूल्य क्या होगा, जैसे पिछले साल धान का समर्थन मूल्य 1,590 रूपये प्रति क्विंटल रेट था, अगर पिछले साल की ही लागत को मान लिया जाए, तो अब आने वाले समय में जो डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का वायदा किया गया है, वह कितना हो जाएगा? जैसा कि भूपेंद्र यादव जी कहा कि जो भूमिहीन किसान खेत को ठेके पर लेकर, लीज़ पर लेकर खेती करते हैं, उनको 30,000 से लेकर 50,000 तक में ठेके पर लेना पड़ता है, उनको भी समस्या आती है। इस बार यह प्रावधान किया गया है कि उनको सस्ते ऋण की सुविधा मिलेगी, यह सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, क्या भूमिहीन किसानों को, लीज़ पर खेती करते हैं, उनको भी उसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड मिलेंगे?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं। हरियाणा में जो एसएलवाई है, उसकी बड़ी समस्या है। आप जानते हैं कि फसल के उत्पादन के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। अगर फसल को समय से पानी नहीं मिलेगा, तो फसल पैदा नहीं हो सकती है। हरियाणा को एसएलवाई का पानी नहीं मिलने से किसान परेशान हैं, एसएलवाई का पानी दक्षिण हरियाणा के किसानों को नहीं मिल रहा है। हरियाणा में लगातार भूजल का स्तर गिरने से पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है, जो गेहूं एवं धान के मामले में पंजाब के बाद सबसे बड़ा योगदान कर रहा है। लेकिन पानी की विकट समस्या के कारण हरियाणा का किसान स्वयं को लाचार महसूस कर रहा है। एसएलवाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी पंजाब हरियाणा के कि का पानी नहीं दे रहा है। अतः मेरी इस मामले में केंद्र सरकार से अपील है कि वह इस समस्या का हल निकाल कर हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाने का काम करें ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, आप समाप्त करिए।

श्री राम कुमार कश्यप: ताकि हरियाणा के किसानों को खेती के सिंचाई के लिए पानी मिल सके। महोदय, एक मिनट और लूंगा। महोदय, वित्त मंत्री जी ने 600 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की घोषणा की है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और चूंकि मैं कुरुक्षेत्र, हरियाणा से आता हूं, उनसे मांग करता हूं कि कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुविधा दी जाए क्योंकि कुरुक्षेत्र एक धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है। यहां पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। यहां पर ब्रह्म सरोवर है, जोकि एशिया का सबसे बड़ा तालाब है और यहां सूर्य ग्रहण के समय लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): धन्यवाद।

श्री राम कुमार कश्यप: सर, अंत में एक कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा–

"पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को,
उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कोरे नहीं होते।
ख्वाहिश बस इतनी सी है कि लोग मेरे लफ्जों को समझें,
आरजू यह नहीं कि लोग वाह-वाह करें।"

धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): श्री डी. राजा। आपके लिए 3 मिनट का समय है।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, if you do not want me to speak, I will not speak. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभाध्यक्ष जी...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): आप बैठिए।

SHRI D. RAJA: You take the sense of the House. ...(*Interruptions*)... You take the sense of the House. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, मैं आंध्र प्रदेश के agitated Members की बात कर रहा हूं। सर, जब आपने यह परंपरा बनायी है कि आप disturbed House में बहस करा रहे हैं, तो कम-से-कम इन्हें कुर्सी allow करा कर नई परंपरा शुरू कर दीजिए।

SHRI D. RAJA: You take the sense of the House. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, बैठिए। श्री डी. राजा जी, बोलिए।

SHRI D. RAJA: Thank you, Sir. Before I speak on the Budget, I would like to make it very clear that my party expressed its solidarity with the people of Andhra Pradesh. Politically, morally I am obliged, I am committed to support the demand of the people of Andhra Pradesh. Sir, the Prime Minister made a speech in this House and he has admitted that the Government is a continuing one. If that is so, the present Government should honour the promises, assurances given by the previous Government, given by the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, at the time of bifurcation of Andhra Pradesh, now the newly-emerged State of Andhra Pradesh. So, I express my solidarity; I give my support. Sir, coming to the Budget, this Budget is the reflection of Government's thinking, how the Government is going to generate revenue, how the Government is going to distribute, redistribute the wealth that is being created in this country. Sir, I find this Government suffers from ideological,

[Shri D. Raja]

philosophical bankruptcy and it suffers from ideological, philosophical hypocrisy. Why and how, I give the reasons. Sir, this is the Economic Survey given by the Government. Page 10 of the Economic Survey talks about IT. Now the IT sector is confronting governance challenges as its model of providing low cost programming for foreign clients comes under threat from rapid technological change. If they have stopped there, I have no problem, but, they go beyond that. So, one might say that India has moved from crony socialism to stigmatized capitalism. What is crony socialism, Sir? What is stigmatized capitalism? Does the Government have any understanding of it? This is why I am saying that you are suffering from ideological bankruptcy; you are suffering from ideological hypocrisy. ...(*Interruptions*)... That is what I am saying. If you talk about stigmatized capitalism, what do you mean by stigmatized capitalism? It is you who are building crony capitalism, corporate capitalism in this country. That is what your Budget reflects. ...(*Interruptions*)... You listen to me. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Mr. Raja, you talk to me ...(*Interruptions*)... Don't tell them.

SHRI D. RAJA: Okay. This is my first observation about this Budget. What is the revenue generation? What is the attempt by this Government for revenue generation? That is the primary objective of Budget. Budget is meant for revenue generation. What is the Government's approach? The Government says—corporate tax will be reduced to 25 per cent for companies which have a total turnover of ₹ 250 crores.' It means, by this, the revenue foregone is ₹ 7,000 crores. It does not end there. Revenue foregone means, it is a profit to the corporate houses. Sir, there are companies and industries, that got benefitted by the corporate income tax, excise duty and customs duty, which do not invest in labour intensive or job creating activities, but still the Government continues to dole them out of concessions. Sir, this is despite the fact, there is no reduction in corporate income tax or excise duty or customs duty. So, the revenue foregone would be definitely more than ₹ 2,45,000 crores. This goes to corporate houses as concessions. If you want to challenge me, you challenge in Parliament or outside Parliament. If you want to challenge, we will challenge each other and this is what you are doing. Revenue foregone means what? You are doling out concessions to the corporate houses and you are making them move further. Sir, this is my first accusation. This is the wrong number one this Government is committing. The former Finance Minister, Shri Chidambaram talked about triple *jhumlas*. I am talking triple wrongs. The first wrong is... ...(*Interruptions*)... This is what I am saying.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Rajaji, only six persons are there. You have got three minutes. Already five minutes are over.

SHRI D. RAJA: Yes, Sir, we will extend. Take the sense of the House if you are so keen. Since yesterday we have been waiting.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): It is true, but I am telling you your time.

SHRI D. RAJA: I agree, Sir. I respect the Chair. You are very seasoned, senior Parliament Member. That is why I am asking. If I don't speak sense, you tell me; I will sit down.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You complete in two minutes.

SHRI D. RAJA: Sir, the second blunder I consider is, for revenue generation, this Government talks about disinvestment of public sector undertakings. Already the Finance Minister has pointed out 24 public sector undertakings. Sir, it means privatization. You talk about developing infrastructure, but you are talking about privatization of Railways, many key operations of Railways will be privatized under PPP model and you are talking about privatization of Air India and Air India can emerge as one of the best airlines in the world. It has expertise. It has experienced manpower and it has infrastructure, but why do you want to sell Air India which is the pride of the nation. It is a national air carrier and you want to sell it off and you want to break it into four and you want to sell it one by one. What is this approach? That is where I think this Government's approach is very flawed. ...(*Interruptions*)...

You talk to the Chair. If you have any point, talk to the Chair. I am addressing the House.

श्री तपन कुमार सेन (पश्चिमी बंगाल): आपने घाटा देखा है, हिसाब किया? ...(**व्यवधान**)... किसको घाटा बोलते हैं, कुछ समझते हैं? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): आपस में बात नहीं करनी है, इनको बोलने दीजिए।

SHRI D. RAJA: Sir, I am not talking about infrastructure only. What is the Government going to do with Railways, Air India, Defence and other infrastructure? I want to ask you about FDI in Defence production. How does it strengthen the national sovereignty? I am asking you about FDI. What about the Indian corporate houses? They are allowed to go out and invest wherever they can for their profit. But, you are begging before foreigners to come and make in India. You are pleading

[Shri D. Raja]

with other foreign companies, that too in Defence production! You are closing down all our Ordinance factories! You are closing down all our Defence units! And, you are inviting FDI into our Defence production! Is it alright? I am asking the Government. Sir, it just does not stop there. You are privatizing education! You are privatizing healthcare! What is the National Health Protection Scheme you are talking about? Is it not to help foreign and private insurance companies? You are not investing enough money on public health and on public education. What is the condition of our schools? What have you allocated for these in this Budget? You think it over. I am asking the hon. Finance Minister. What is the allocation in the Budget for education as a whole? It has gone down. And, what is the allocation for school education? What is the allocation for higher education? What is the allocation for public health? I am asking you. ...(*Time-bell rings*)... We are talking about our people becoming poorer and poorer because they have to spend more on education and healthcare. Is this what we are talking about?

Sir, finally, I wish to speak about the youth of this country. The Government talks about employment. As per the ILO Report, 77 per cent of workers in India will have vulnerable jobs by 2019; I am not talking about 2020 or 2022 which the Government talks about. I am talking about the next year — 2019. Sir, 77 per cent of workers in India will have vulnerable jobs. The Report further says that 18.9 million people will be unemployed by 2019. Added to that, if 77 per cent workers have vulnerable jobs, it would be an alarming situation. Do you understand the gravity of the situation? It is not just unemployment; it is also a question of under-employment. This Budget did not address these issues!

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): धन्यवाद।

SHRI D. RAJA: I come to economic inequality. The hon. Prime Minister went to Davos to address the World Economic Forum. I felt happy. Sir, the Indian Prime Minister, for the first time, went to the World Economic Forum and addressed it. I felt happy. I have no problem with that. But, the problem here is this. The annual Oxfam Survey released recently. What it says? This is what the Government should understand. It says that richest 1 per cent cornered 73 per cent of wealth generated in this country. Why this inequality? Why is this economic inequality?

THE VICE-CHIRMAN (SHRI BASAVARAJ PATIL): Okay, Mr. Raja. Please, conclude. I have extended your time thrice.

SHRI D. RAJA: Sir, I will finish. Oxfam India CEO, Ms. Nisha Agrawal, says that it is alarming that the benefits of economic growth continue to concentrate in fewer hands. She also said that the billionaire boom is not a sign of a thriving

economy but a symptom of a failing economic system. Those working hard, growing food for the nation, building infrastructure, working in factories are struggling to fund their children's education, buy medicines for family members and manage two meals a day. The growing divide undermines democracy and promotes corruption and cronyism. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): धन्यवाद डी. राजा जी।

SHRI D. RAJA: Sir, this is what the Budget is all about.

Finally, I wish to speak about SC/ST. Allocation to SC/ST is not as per the directives of the erstwhile Planning Commission and the accepted norm. On the one hand, the Government claims that it is spending more on SC/ST, but, on the other, allocation to Scheduled Caste Component Plan and the Sub-Plan is very meager. And, there is no law and there is no directive from the Government to provide them adequate money which they need. This is what I am asking. This Budget is not a growth-oriented Budget. This Budget is a failure. This Budget is anti-poor. It does not help India to move forward and progress. This is my observation. Let the hon. Finance Minister reply. I will ask the hon. Finance Minister what he is going to say on all these issues. Thank you.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहली बात तो यह है कि बजट भाषण के सारे प्वॉइंट्स तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा में ही डिस्कस हो गए हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो बातें नहीं थीं, जैसे किसानों के लिए जो एक योजना घोषित हुई थी और दूसरी हेल्थ स्कीम की योजना थी, ये दोनों बातें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं थीं, बजट में थीं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा में इन बातों पर बहस हो गई और प्रधान मंत्री जी ने भी उनका जवाब दे दिया। इसलिए ये योजनाएं मिक्स, गड्डमगड्ड हो गईं। इन दोनों पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलें, क्या न बोलें!

महोदय, सबसे पहले मैं भी उन्हीं मुद्दों को उठाना चाहूंगा, जो चिदम्बरम जी, जयराम रमेश जी और दूसरे बाकी सदस्यों ने उठाए। आज की तारीख में किसान की हालत बहुत खराब है, आप कुछ भी कहें। आप कितना भी कहें कि यह कर दिया, वह कर दिया, लेकिन हालत यह है कि न तो किसान को उसकी उपज की कीमत मिल रही है, न उसको खाद-बीज उचित कीमत पर मिल रहा है और न उसकी एग्रीकल्चर से कमाई हो पा रही है। उसके लिए जो प्रभावकारी उपाय हैं — वे प्रभावकारी उपाय, जैसे खाद की कीमत को सस्ता करना, बीज की कीमत को सस्ता करना, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना, उस तरफ इस बजट में कोई एलोकेशन नहीं है। इन्होंने जो कहा है कि हम डेढ़ गुना कर देंगे, उसकी लागत के ऊपर उसको पचास प्रतिशत देंगे, तो सवाल जो उठाया था, उसको मैं आम आदमी की भाषा में कहता हूँ कि उसकी लागत कौन तय करेगा? लागत तो ऑफीसर्स तय करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स तय करेंगे, सरकार तय करेगी और वे कह देंगे कि आपकी लागत तो चार रुपए है, तो किसान कैसे बताएगा कि नहीं, साहब, लागत चार रुपए नहीं बल्कि दस रुपए है! आप तो चार रुपए के हिसाब से बढ़ा कर छह रुपए दे देंगे, जबकि

[श्री राजीव शुक्ल]

उसकी एक्चुअली लागत तो आठ से दस रुपए के बीच में आएगी, तो वह कैसे दिखाएगा? यह एक बहुत बड़ा* है, जिसको वित्त मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि जो लागत है, उसका बेस प्वॉइंट क्या होगा, किस आधार पर उसका मूलभूत आधार बनेगा, यह तय होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप सीधी घोषणा कर दो, जो आपके लिए बहुत आसान है कि जो मनमोहन सिंह जी की सरकार समर्थन मूल्य दे रही थी, वही हम देंगे। उससे किसान खुश हो जाएगा। ...(**व्यवधान**)... आप ऐसा करने से बच रहे हैं, ऐसा करने से आप डर रहे हैं। यूपीए सरकार ने जो समर्थन मूल्य तय किया था, अगर आप कहेंगे कि वह हम करेंगे, तो आपकी भी वाहवाही हो जाएगी। इसमें कौनसी इज्जत घट जाएगी? ...(**व्यवधान**)... यह घोषणा आप वित्त मंत्री जी से करवा दें, क्योंकि आपका जो यह कृषि का है, मैं तो योजना आयोग में रहा हूँ, जो पहले 2.38 परसेंट था, वह 2.36 परसेंट होकर बजट में कम हो गया है, तो आप कहां से करेंगे? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): शुक्ल जी, आप ऐसा बोलिए कि यह सरकार कहां से करेगी! आप करके बोलेंगे, तो लगेगा कि आप उधर बात कर रहे हैं।

श्री राजीव शुक्ल: महोदय, आपकी तरफ देखकर बोलूंगा। चार प्रतिशत जो ग्रोथ होनी थी, वह तो सपना हो गया। एग्रीकल्चर की ग्रोथ तीन प्रतिशत से नीचे की हो गई है, जिसको बढ़ाने का काम सरकार को करना चाहिए।

महोदय, हेल्थ स्कीम की योजना बहुत अच्छी योजना है। यदि यह सच में लागू हो जाए, तो उसका बहुत फायदा मिलेगा। ...(**व्यवधान**)... आप बोलो, लेकिन यहां न तो अमित शाह जी बैठे हैं, न मोदी जी हैं, कोई मंत्री नहीं बनाएगा, क्यों अपना टाइम बरबाद कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... आप मुझे चुपचाप सुन लीजिए। जब वे हों, तो बोलो, हम भी आपकी मदद करेंगे। अभी दोनों यहां नहीं हैं, न दोनों टीवी देख रहे हैं, इसलिए क्यों अपना गला खराब कर रहे हो? ख्वामख्वाह में टोरेक्स, कोरेक्स खानी पड़ेगी। इसलिए अभी आराम से बैठो। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): राजीव शुक्ल जी, अभी आपका एक मिनट है।

श्री राजीव शुक्ल: नहीं, एक मिनट कैसे हो सकता है? महोदय, तीन मिनट को तेरह मिनट। हमारा तो बहुत टाइम है, उसमें हमारा पंद्रह मिनट लिखा हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अभी आपका एक मिनट है।

श्री राजीव शुक्ल: राजा जी को तीन मिनट के तेरह मिनट दे दिए। मेरा जो पंद्रह मिनट है, उसके पैंतालीस मिनट होने चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): आप राजा जी से कम्पेयर मत कीजिए।

श्री राजीव शुक्ल: कम्पेयर क्यों न करें? ऐसा मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट में तो हमारी बात ही नहीं हो पाएगी। फिर हम भाषण देने के लिए क्यों खड़े हुए हैं? हमारा कांग्रेस पार्टी का टाइम बहुत बाकी है। आप देखिए, 31 मिनट बाकी हैं। आप क्या बात कर रहे हैं?

---

*Expunged as ordered by the Chair.

4.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): आपके सात सदस्य बोलने को बाकी हैं।

श्री राजीव शुक्ल: महोदय, इस तरह तो सारा टाइम बरबाद हो रहा है। तो यह जो स्वास्थ्य योजना है, एक अच्छी स्कीम है, लेकिन इसमें समस्या यह है कि इसका फायदा कहीं नर्सिंग होम्स न ले लें, कहीं डॉक्टर्स न ले लें, क्योंकि इसमें प्राइवेट नर्सिंग होम मिला हुआ है। या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए होता कि उनको वह पैसा जाएगा, तो काम हो सकता था। इसमें प्राइवेट नर्सिंग होम्स फर्जी बिल्स लगाएंगे और इसका पूरा फायदा बीमा कंपनियों से मिल कर लेंगे। इसलिए इसमें भी प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है। यदि संभव हो, तो इस पैसे को सीधे उसके खाते में ट्रांसफर किया जाए, जिससे उसका फायदा होगा, वर्ना क्या होगा कि दस करोड़ लोगों को अगर एक लाख रुपए भी देने पड़े तो दस लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन चाहिए। वह कहां से आएगा? इसलिए मुझे इसमें भी संदेह लग रहा है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में सरकार की घोषणा थी कि तीन परसेंट से ऊपर कभी नहीं जाने देंगे, जो इस बार 3.5 परसेंट बजट में दिखाया गया है, इसके बारे में वित्त मंत्री जी कुछ स्पष्टीकरण दें, तो अच्छा रहेगा।

महोदय, महंगाई का जहां तक सवाल है, सभी यह सवाल पूछ रहे हैं, जैसा नीरज जी ने और सभी ने पूछा, कि विश्व बाजार में जो पेट्रोल और डीजल का दाम गिरा, उसका फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर, आज की तारीख में इस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 64 रुपए प्रति लीटर है। इससे महंगाई रुक ही नहीं सकती, क्योंकि इसका सीधा असर महँगाई पर पड़ता है। इसके लिए सरकार ने इतने दिनों में कुछ न कुछ किया, लेकिन अब consumer को कितना फायदा pass on होता है, वित्त मंत्री जी को यह बताने की कृपा जरूर करनी चाहिए।

सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि exports क्यों down हो रहे हैं? अभी दावोस में भी प्राइम मिनिस्टर ने promise किया, लेकिन इसके बाद भी हमारा export 30 मिलियन से 23 मिलियन तक आ गया। यह क्यों down हो रहा है? इसकी वजह से बहुत समस्या आएगी। इसलिए इस तरफ भी सरकार को देखना चाहिए।

सर, एक बात, जो हमने बीच में वित्त मंत्री जी से पूछी थी कि फिक्की के सम्मेलन में Morgan Stanley ने कहा था कि 6 हजार entrepreneurs बाहर चले गए, यहां से परेशान होकर, क्योंकि उनको इतना तंग किया जा रहा है, विभाग के अधिकारीगण उनके पीछे इतना पड़े हैं, इतने notices दिए जा रहे हैं कि इसकी वजह से वे चले गए। अगर entrepreneurs बाहर चले जाएंगे, तो नौकरियां कौन देगा? रोजगार तो सीधे-सीधे उनसे जुड़ा है, गवर्नमेंट तो दे नहीं सकती। इसलिए private entrepreneurs में जो डर या भय है और वे बाहर जा रहे हैं, तो रोजगार कौन देगा, इसके लिए भी कदम उठाने चाहिए।

यह सही है कि Corporate Sector के 250 करोड़ तक के turnover पर 25 परसेंट टैक्स कर दिया है, जो अच्छी चीज है, लेकिन अब जो cess लगाया गया है, उसका कितना impact आएगा, अगर इस मामले में भी वित्त मंत्री जी स्थिति स्पष्ट कर सकें, तो बहुत अच्छा है। ...**(समय की घंटी)**...

[श्री राजीव शुक्ल]

सर, GST को लेकर एक समस्या यह आ रही है कि लोगों को कर्ज लेकर GST अदा करना पड़ रहा है। अगर आप इसका कुछ निदान निकालें कि किस तरह से जो व्यापारी और दुकानदार हैं, अगर उनको समय-सीमा की कुछ ऐसी सुविधा हो, ताकि उनको वह दिक्कत न हो, तभी मुझे लगता है कि सुधार हो सकता है और GST को लोग स्वीकार कर लेंगे, वरना अगर बैंक से कर्ज लेकर GST देना पड़ा, तो लोगों को बड़ी दिक्कत आएगी।

सर, आज एक बड़ी अच्छी चीज हुई है, हम तो इसकी तारीफ करेंगे। यह Money Bill के जरिए हुई, लेकिन चूँकि वह वित्त से सम्बन्धित है, इसलिए मैं इसका ज़िक्र कर रहा हूँ कि judiciary की बात सुन कर और उनकी मांगों को मान कर जजों की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। हाई कोर्ट तक के जजों की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। चलो, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं कि यह अच्छी चीज है। अब उनकी तनख्वाह तो 2.5 लाख कर दी गई है, लेकिन आप judicial reforms तो लाइए। हर चीज में reforms हो रहे हैं, क्रिकेट में हो रहे हैं, हॉकी में हो रहे हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और सबमें reforms हो रहे हैं, लेकिन judiciary में कोई reform ही नहीं हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): राजीव शुक्ल जी, आप समाप्त कीजिए। अब अगला नाम आएगा।

श्री राजीव शुक्ल: देखिए, 3 मिनट वाले को आपने 13 मिनट दिए, तो आपको मेरे साथ क्या problem है?

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अभी आपके 7 और लोगों को बोलना है।

श्री राजीव शुक्ल: नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी और बोलूँगा।

मैं कहना चाहता हूँ कि आप judiciary के लिए कोई reform ही नहीं रखते हैं, आप कोई बात ही नहीं करते हैं, सरकार भी नहीं करती है। एक NJAC बना, उसके बाद उसमें कोई प्रगति नहीं है। अगर इसके बारे में भी मंत्री जी स्पष्टीकरण दें, तो बहुत अच्छा होगा।

अब मैं एक मिनट समय रेलवे पर लूँगा, क्योंकि इसमें रेलवे का बजट मिला दिया गया है और इससे रेलवे पर चर्चा होनी बंद हो गई है। अब कोई रेलवे की बात ही नहीं करता, बजट में इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। रेलवे का जो बजट है, मुझे लगता है कि लोग उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि पहले दिन उसका सूचकांक 5 परसेंट गिर गया। इसकी operational cost 95 प्रतिशत बताई गई है। इसका मतलब है कि रेलवे में सुधार करने के लिए, infrastructure बनाने के लिए और बाकी काम करने के लिए सिर्फ 5 परसेंट का cushion है। यह कैसे हो पाएगा, क्योंकि हाल यह है कि सारी रेलों का refurbishment करना है और नई रेल लाइनें बिछानी हैं। इसके लिए पैसा कहां से आएगा? Quality services provide करने के लिए पैसा नहीं है। अभी Civil Aviation का data आया है कि यह almost बराबर हो रहा है, air passengers और railway passengers में थोड़ा ही अंतर रह गया है। लोग अब जहाज से चलना ज्यादा prefer कर रहे हैं, क्योंकि उनको रेलवे में सुविधा नहीं मिल पा रही है, पैसा ज्यादा देना पड़ता है, टाइम की बर्बादी भी बहुत हो रही है और समय से trains भी नहीं चल पाती हैं। इसलिए यह जो अंतर पहले बहुत होता था, अब कम होता जा रहा है। अभी 400 जहाज और order हुए हैं। अगर वे

आ गए, तो रेलवे बहुत बुरी स्थिति में फंस जाएगी, क्योंकि लोग जहाज से जाना ज्यादा prefer करेंगे। मान्यवर, खाना ट्रेन के अन्दर भी खराब है और प्लेटफॉर्म का भी खराब है। पीयूष गोयल जी काफी मेहनती मंत्री हैं और सुधार में लगे रहते हैं, लेकिन ये बुनियादी चीजें हैं, policy की चीजें हैं। इनके लिए प्रावधान चाहिए, पैसा चाहिए। वे कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है। अगर पैसे की कमी नहीं है, तो सुविधाएं ठीक क्यों नहीं हो पा रही हैं? Freight भी गिर गया है। रेलवे की journey तो इतनी अच्छी होती है कि विदेश में इससे कितना फायदा हो रहा है। शहर का जो सेंटर होता है, वहां रेलवे स्टेशन होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं, आराम से जाएं, उनको कोई दिक्कत न आए। ...(**समय की घंटी**)... लेकिन इसके बाद भी रेलवे का profit क्यों गिरता जा रहा है और passengers कम क्यों होते चले जा रहे हैं? रेलवे सुरक्षा के लिए काकोदकर कमिटी की जो recommendations थीं, उनके लिए जो बजट का प्रावधान करना चाहिए था, वह प्रावधान अभी तक इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए उनको इसके लिए प्रावधान करना चाहिए।

सर, अभी मेरे पास बहुत points हैं, लेकिन आप कहते हैं कि दबाव और pressure है, तो मैं क्या बताऊं, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ और इसलिए मुझे अपनी बात समाप्त करनी पड़ रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): श्री संजय सेठ। आपके पास 2-3 मिनट का समय है।

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, यह जो बजट है, यह बहुत ही निराशाजनक दिख रहा है, क्योंकि आम जनता को इस बजट से बहुत उम्मीदें थीं। इस बजट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है, वह है दस करोड़ लोगों के लिए पांच लाख रुपये का बीमा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसको दो भागों में बांट दिया। इसमें पहला था स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को अपने नज़दीक ही स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और दूसरा था ...(**व्यवधान**)...

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): वाइस चेयरमैन साहब, कल तक बजट पर चर्चा के लिए छः घंटे बचे थे, लेकिन पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने unilaterally उसको घटा कर तीन घंटे कर दिया। मैंने सुबह भी कहा था कि अगर पार्टीज़ का समय काटना है, तो दूसरी पार्टीज़ का समय मत काटो। इसकी वजह से सारा टाइम-टेबल गड़बड़ हो गया है। जहां हमने एक-एक मेम्बर को बोलने के लिए 10-10 या 15-15 मिनट रखे थे, अब वे तीन मिनट में कन्वर्ट हो गए हैं।

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : وائس چیئرمین صاحب، کل تک بجٹ پر چرچا کے لئے چھہ گھنٹے بچے تھے، لیکن اب پارلیمنٹری افیئرس منسٹر صاحب نے اس کو unilaterally چھہ گھنٹے کر دیا۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ اگر پارٹیز کا وقت کاٹنا ہے، تو دوسری پارٹریز کا وقت مت کاٹئے۔ اس کی وجہ سے سارا ٹائم ٹیبل گڑبڑ ہو گیا ہے۔ جہاں ہم نے ایک ایک ممبر کو بولنے کے لئے دس-دس یا پندرہ-پندرہ منٹ رکھے تھے، اب وہ تین منٹ میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔

† Transliteration in Urdu script.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अब जैसा है, ठीक है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: जब सदन बड़े आराम से और शांति से चल रहा था, ऐसे में अगर सदन दो घंटे और चल जाता, तो क्या फिक्र थी? आज के लिए हमारे पास छः घंटे बचे थे, उस पर आपने एकदम slab लगा दिया और पूरे तीन घंटे कम कर दिए। कल सदन तकरीबन 6-7 घंटे चला था, इसलिए आज छः घंटे और बाकी थे। इसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो गया है।

†**جناب غلام نبی آزاد :** جب سدن بڑے آرام سے اور شانتی سے چل رہا تھا، ایسے میں اگر دو گھنٹے اور چلا جاتا، تو کیا فکر تھی؟ آج کے لئے ہمارے چھہ گھنٹے بچے تھے، لیکن اس پر آپ نے ایکدم slab لگا دیا اور پورے تین گھنٹے کم کر دئے۔ کل سدن تقریبا چھہ-سات گھنٹے چلا تھا، اس لئے آج چھہ گھنٹے اور باقی تھے۔ اب اس کی وجہ سے پورا گڑبڑ ہو گیا ہے۔

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अब जो हो गया, ठीक है। संजय जी, आप आगे बोलिए।

श्री संजय सेठ: माननीय मंत्री जी ने इस बजट को दो भागों में बांटा है, जिसमें एक भाग स्वास्थ्य के लिए है। इसमें पहला है, स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ावा देना, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नज़दीकी केंद्रों में उपलब्ध हों। दूसरा है, 10 करोड़ गरीब लोगों को पांच लाख रुपये के बीमे की सुविधा देना। मैं दूसरे बिंदु के ऊपर बोलना चाहता हूं, जो बहुत ही प्रचारित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। महोदय, अगर इसके आंकड़े देखे जाएं, तो इस साल स्वास्थ्य के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है, वह 52,800 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले साल इसके लिए 51,580 करोड़ रुपये का बजट था, यानी इस बजट में केवल 1,250 करोड़ रुपये ही बढ़ाए गए हैं।

दूसरी तरफ एजुकेशन सेस के नाम पर जो तीन प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर अब 4 प्रतिशत कर दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है, 'हेल्थ एंड एजुकेशन सेस'। इसका मतलब तो यह है कि आप जनता से एक प्रतिशत लेंगे और फिर उसी चीज़ को गरीबों में बांटेंगे। इस सरकार ने अपनी तरफ से इसमें कोई कांट्रिब्यूशन नहीं दिया है, जनता से वसूल करके जनता को ही वापस करने की बात है और वह भी किसी हालत में पूरा नहीं हो सकता है।

तीसरा, इसमें डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर्स बनाने के लिए कहा गया है, जिसके लिए 1,200 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं, यानी एक सेंटर बनाने के लिए केवल 80,000 रुपये एलोकेट हुए हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अभी जो सेंटर्स चल रहे हैं, उन सारे के सारे सेंटर्स में न तो उचित रख-रखाव है, न उनमें कर्मचारी हैं और न ही मेडिकल का सामान है। उन सारे सेंटर्स को छोड़कर अब ये नये सेंटर्स बनाए जाने की बात कही जा रही है। इसमें मेरा यह कहना है कि जो सेंटर्स पहले से चल रहे हैं, उन्हीं को आप ठीक कराएं और उन्हीं पर पैसा लगाएं। नई चीज़ करके क्या फायदा होगा? ...(**व्यवधान**)...

महोदय, अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में दुर्घटना हुई और वहां एक साथ सैकड़ों

† Transliteration in Urdu script.

बच्चे मर गए। वहां पर ऑक्सीज़न की कमी है, साथ ही पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए इस तरह की चीज़ों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाए इसके कि आप लुभावनी चीज़ें दिखाएं और उनको पूरा भी न कर सकें। दो साल पहले के बजट में भी इसी तरह का एक प्रोविज़न था, जिसमें उन्होंने एक लाख रुपये का बीमा करने की बात कही थी, लेकिन आज तक 30,000 रुपये के बीमे से ऊपर नहीं दिया जा रहा है।

तीसरा, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में यहां तक कहा कि एक करोड़ मकानों में से 93 लाख मकान बन चुके हैं, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि इनके पास ये आंकड़े आ कहां से रहे हैं? इस संबंध में लोक सभा में जब एक सवाल किया गया था, तो उसके जवाब में इन्होंने बताया कि अभी तक केवल 21 लाख मकान बने हैं। महोदय, इस तरीके से बताया जा रहा है कि 93 लाख मकान बन चुके हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अभी तक केवल 21 लाख मकान ही बने हैं। ये सारी चीजें असत्य हैं। इसमें कुछ नहीं है और जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है।

महोदय, दूसरी बात इन्होंने अपने बजट भाषण में रीयल एस्टेट के प्वॉइंट में यह बताई कि जमीन के दाम सर्कल रेट के हिसाब से होंगे। उसमें अगर इन्कम टैक्स में 5 परसेंट का डिफरेंस होगा, तो वह मान लिया जाएगा। अगर दिल्ली को देखें, तो यहां जमीनों के दाम बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन सर्कल रेट बहुत ज्यादा है। अगर किसी भी शहर का सवेक्षण कराएं, तो यही हाल मिलेगा। अब गरीब आदमी या कोई भी आदमी मकान खरीदे, तो उसके लिए स्टाम्प-ड्यूटी ज्यादा दे, उसके बाद इन्कम टैक्स भी ज्यादा दे, तो यह ठीक नहीं है।

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय सेठ: इसलिए इसमें कोई प्रोविज़न ऐसा होना चाहिए था कि उसका एक सर्वे करा के उसे 5 से 10 परसेंट कर दिया जाए, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Thank you. Now, Shri N. Gokulakrishnan; you have only two minutes to speak.

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बजट पर चर्चा चल रही है और न वित्त मंत्री हैं, न राज्य मंत्री (वित्त) उपस्थित हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयल: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यहां राज्य मंत्री (वित्त) उपस्थित हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है। वित्त राज्य मंत्री उपस्थित हैं। ...(**व्यवधान**)... अच्छा, आपस में बात मत कीजिए। बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Naqviji, please, no cross-talk. ...(*Interruptions*)... Jairamji, no cross-talk please. You are one of the best parliamentarians.

SHRI N. GOKULAKRISHNAN (Puducherry): Hon. Vice-Chairman, Sir, due to paucity of time, I would cut down all my points on the General Budget and come straightaway to the issues concerning Puducherry.

[Shri N. Gokulakrishnan]

Sir, talking about grant of Central assistance to States and Union Territories, a share of the total tax collected at the Centre is given to the State Governments based on the Finance Commission's recommendations. In the case of Union Territories without Legislatures, the entire budget requirement is met by the Government of India after taking all receipts from the Union Territories. In the case of Union Territories with a Legislature, like Puducherry, normally the entire gap between their budgetary requirement and their resources is met by the Government of India all along.

Sir, the Union Territory of Puducherry has implemented the Seventh Central Pay Commission recommendations and has requested the Government of India for additional funds to the tune of ₹ 750 crores. But, so far, the Government of India has not given even a single rupee to Puducherry for implementing the recommendations of the Seventh Central Pay Commission. The Central assistance allocated to the Union Territory of Puducherry for the current financial year is ₹ 1,476 crores; for the previous year it was ₹ 1,411 crores. But, in recent years, this has been stopped and instead, Central assistance with a four per cent increase over that of the previous year has been fixed.

Sir, the Union Territory's resources have been affected considerably by various factors like GST, ban on bar licence on highways and ban in the real estate sector. On the one hand, expenditure has increased due to the implementation of the Seventh Pay Commission recommendations and, on the other hand the income has come down. Thus, the Union Territory of Puducherry is not able to carry out development programmes since the entire receipts are being used for committed expenditure like salaries, pension, payment of interest and repayment of loan. I appeal to the hon. Finance Minister to increase the share of Central assistance to the Union Territory of Puducherry at least by 20 per cent every year.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Please conclude now.

SHRI N. GOKULAKRISHNAN: Sir, I would take just one more minute.

Sir, I wish to invite the kind attention of the hon. Union Railway Minister to a long-pending demand of the Union Territory of Puducherry for a railway link from Tindivanam to Cuddalore *via* Puducherry. A lot of commuters visit places of pilgrimage like Karaikkal, Nagoor and Velankanni from Chennai. Connecting Tindivanam and Cuddalore through a railway link would lessen their travel time. Sir, I appeal to the hon. Union Railway Minister to look into this long-pending demand for immediate consideration. Similarly, I appeal to link Peralam with Karaikal, which is also a long-pending demand. In fact, I raised this matter and discussed in detail about the

viability when I attended the Railway Committee meeting organized by the General Manager of South Zone of Railways at Madurai last month. With this, I conclude my speech and I welcome the welfare schemes announced by the hon. Finance Minister and I also appeal to him to consider my demands favourably. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, धन्यवाद। श्री नरेश गुजराल जी, आपके तीन मिनट हैं।

SHRI NARESH GUJRAL: No, Sir. I am the leader of my group. We have 18 Members. I must have 10 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Your Party has ten minutes in total and there are three Members to speak. ...(*Interruptions*)...

SHRI NARESH GUJRAL: I am sorry, Sir, I won't speak; somebody else to speak. ...(*Interruptions*)...

श्री राजीव शुक्ल: सर, यह बहुत गलत है। ...(**व्यवधान**)... *

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... नरेश गुजराल जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... शुक्ल जी, आप अपनी जगह पर जाइए। ...(**व्यवधान**)... Shuklaji, please go to your seat. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल: * ...(**व्यवधान**)... * ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल: * ...(**व्यवधान**)... *

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): आप सब लोग बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... You sit down. ...(*Interruptions*)... I will take care. ...(*Interruptions*)... आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... नरेश गुजराल जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... टाइम वेस्ट जायेगा, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... गुजराल जी, बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, first of all, I would like to start by expressing my sympathies with my follow Members who are here. Commitments were made to Andhra Pradesh in this House which, unfortunately, collectively have not been kept and I feel sorry that their demands are not being met and I hope that the hon. Finance Minister will look at their demands favourably.

Sir, having said that, I feel that this is the most challenging Budget for the hon. Finance Minister since this Government came to power. Why is it challenging? It is because oil prices have hardened and are today in the vicinity of 65 to 70 dollars a barrel. For four years, you had the cushion of soft oil prices with which

---

* Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Naresh Gujral]
you could pursue giving money to the social sector. Secondly, Sir, there is an acute farm distress in the country. Thirdly, there is an under-utilised capacity in manufacturing and the power sectors which are not creating fresh jobs. At the same time, he has to maintain fiscal discipline because the country wants to send the message to international investors that we are fiscally responsible so that FDI keeps coming to India. Having said that, I congratulate the Finance Minister that he has taken a holistic view by pumping in money to the rural sector, and I call it a paradigm shift in the way we look at agriculture and agriculturists in this country. Sir, it was very strange that despite the fact that 65 per cent of India's population was dependent on the farm, 49 per cent of the jobs were created in the agriculture sector. Yet, we were short-changing our farmer by not giving him adequate prices for his produce. What were we doing? We were saying, let's not give him a high price because that will create inflation. So, the poor farmer was suffering. Every time international prices went up, we would put a ban on export because again we wanted to protect a constituency in India which was the urban constituency and the farm sector kept suffering. So, I congratulate the Finance Minister that he has said and kept the promise that the farmer will get 150 per cent of his cost which means cost plus fifty per cent. Now, Mr. Chidambaram, Mr. Neeraj Shekhar and many others have raised a question about formula. Is it A2 plus FL or C2? Sir, I am not getting into any formulas. Yesterday, one of the Congress Members, Mr. Chidambaram probably, said that in their tenure they doubled the prices of the farm sector in ten years. Neerajji, that works out to six per cent compounded per annum. This is what the farmer was getting when the inflation rate was in double digits. So, every year, the poor farmer was forced to commit suicide. Thank God, now the Finance Minister has said that the farmer will get just deal. So, by not getting into the details of which formula it is, I will only urge the Finance Minister that the next crop is coming in two months. We have raised the hopes of the farmer of this country. They are expecting a new deal, a big deal. Please, do not let down the farmer of India because if you do, you will see the kind of despair, suicides and frustration that this country has never seen before. So, as I said, I am not getting into the formula, but I do hope that the farmer will finally get a proper deal. Sir, secondly, how does a farmer get so poor and eventually commit suicide when he is so frustrated? Number one, he does not get adequate price for his produce. Number two, the healthcare cost. Somebody falls ill in his family, he begs, borrows at high interest rate and then gets the patient treated. And, third is marriage expenses. This Budget has taken care of the first two. Adequate farm prices and be making sure that the poor in this country will be treated by the Government up to 5 lakhs per family which I think is a phenomenal announcement. But, again, he must be

honoured in letter and spirit. Only then will the poor of this country feel satisfied. And, I would also urge the Prime Minister the way he has carried the campaign of 'Swachh Bharat', I hope something is done that we curtail expenses on marriages in this country and some kind of a social campaign needs to be unleashed because that will help the farmer.

Sir, having said that, jobs have to be created. Now, the Finance Minister has said, we will pump money into the farm sector. Six lakh crore is going into the infrastructure sector, he is making sure that the textile sector, which is the second largest generator of jobs after the farming sector, will get its due and jobs will be created there. And also he has tweaked the labour laws; till now, it was that you could hire but not fire, but by giving fixed term contracts, this will ensure that industry starts to hire more people. Sir, I am an optimist. The way the BJP, the NDA has followed economic policies, I am convinced that we will see double digit growth very soon and the proof of that is the way FDI is coming into India. They are not fools. They know that this country will have the market, this country is growing and this country is following the right economic policies and that is why they are coming to India. And, this is very important, Sir, because our domestic rate of savings is now stagnant at 29 per cent for a very long time. We need the FDI investment. This year it is about 60 billion dollars and I think it will increase as our market becomes better. Because what happens is when there is a demand, only then factory starts working into full capacity. And this is what this Finance Minister is doing. He is creating the demand. And this will set in motion a virtuous cycle. When factories start working to full capacity, they will have to hire more people; when more people are hired, that will create more demand and when there is more demand, only then private sector investment will start coming in and I have no doubt in my mind that the NDA will ensure that this economy gets regenerated. This Budget has given it a kick-start and I am convinced that going forward, this country will soon see double-digit growth and I congratulate the Finance Minister for that. Thank you very much, Sir.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, before I talk, I am distraught for the simple reason, we seems to have thrown to the winds the very rules of this House. And now the Chairman comes and says that if anybody is standing in the Well, it means disorder of the House and it cannot be tolerated. Yet, we allowed. Then we seems to have forgotten the political idiom when we talk. That is also something which has really hurt most of us, being in this House or outside in other Legislatures. But, the question today is about the Budget. I am very much interested in talking about the Budget, but what has really provoked me most is the action of

[Dr. K. Keshava Rao]

my friends from Andhra, for whom we have all expressed sympathies. In fact, I was the first man, when a Private Member Bill was taken up here, who spoke here and went in their support, if not rescue. It is Mr. Jairam, who wrote this Bill. I really sympathies with that one man, who could neither become friends with us nor with them, wrote the rules and also the law objectively. He was the most harassed man in those fifteen days, and I said this here in this House earlier.

Today, the Prime Minister goes on record to say on the floor of the House that bifurcation was done unscientifically. I don't understand it because I know very little English. I have not still understood as to what exactly he means by unscientific bifurcation of a State. I can understand my friend, who was with me, who is now the Chief Minister of Andhra today. He was with me as a junior Minister when I was a Cabinet Minister. He seems to know more about language, as Mr. Chidambaram was saying that we have added new words to the English language, like *jumlas*, etc. Now, tell me, what exactly do we want? We are all for it. That is one. But now, what are they trying to say about Telangana? I think, my sister, Renukaji, will excuse me when I say this. I am with them, as far as their demand is concerned. If they want the implementation of the Andhra Pradesh Re-organization Act, I had No objection to it. Earlier also, I had said this to Mr. Jairam Ramesh, who is very much here, who is the author of the Act. But, today, while agreeing with them, when they say that something wrong had been done in the Act, I would like to say that they should understand that the Parliament has not done anything wrong. They are casting aspersions on the Parliament which has passed this Act. Have they ever thought about this aspect? Only because we are keeping quiet, only because all Members are supporting them, do they think what they are doing is good for the Parliament? This Parliament has passed this Act, not one House, but both the Houses - the Lok Sabha and the Rajya Sabha. After that, we had discussions for fifteen days about framing the rules. The very Member, who is sitting here, had called them for framing rules. They got all that they wanted. Today, most of the Members are here. I don't want to repeat this. We have been exploited for sixty years. We did not bother much because all that we wanted was a State. Now, it is a reality. But today, if there is any work at all, in my Telangana, it is not me who does it; it is you who are giving the contracts there; it is you who are purchasing all the land there; it is you who were purchasing, only the day before yesterday, all the plots there. I have never complained about it. But, today, you come and find fault. We did not have water. Mr. Vice-Chairman, Sir, you are aware. When you went out from Telangana to become part of Karnataka, we did not have any fight at all. The Prime Minister came and said yesterday in Lok Sabha that when they had carved

out three States, there were no problem. Sir, we were divided. My own State was divided into three parts. There was no hue and cry. A part went to Maharashtra. A part went to Karnataka. Nothing happened because we all are hard-working people not vested groups. One was not exploiter; one was not the sufferer. Forget about that now, I am trying to close that chapter. But, the other question today is: there are two rivers. They flow only from Telangana. Two-third of these rivers flows in Telangana. Total Krishna – Godavery catchment is in Telangana. Eighty-three per cent catchment is in Telangana. But only eighteen per cent of its is used here. When the earlier Government had constituted a Committee, we fought and got whatever we could, but we thought that we would discuss it later right here on the floor of Rajya Sabha. The present Chairman of Rajya Sabha, Shri Venkaiah Naidu, who was then an opposition Member, asked for a few concessions to Andhra. He asked for seven concessions. The Prime Minister of the day agreed to that. First, he said that he would look into them, and then he agreed to them, and a Cabinet Note was also prepared. Nobody objected to it. But what is that we are asking now? Please, think again. I am not opposing you. You should get more. What is wrong if the Centre gives you more money? What is wrong if the Centre gives you ten industries more? Get more but don't grouse over the others. Do not have grievance against others. If something is not given to you, fight for it. But did not forget, we are still subject to exploitation, which I was subjected to twenty years back. This thing should be kept in mind by all the people. I know, you have been rich; there is nothing wrong in that, but do not eploit. And, if there is a chance, we will also try to come up, the way we are doing.

Yesterday, the Minister replying for a question said – I am asking all my other Members to know – we all know that none of you were also objecting to it. But let it not be felt as if they have been denied and the other man is getting it. Sir, according to the statement given by the Finance Minister yesterday, the break-up of the moneys released to Andhra Pradesh is ₹ 4,400 crore in 2014-15; ₹ 2,000 crore in 2015-16; ₹ 4,500 crore in 2016-17; ₹ 2,500 crores in 2017-18, and the total is something like ₹ 13,000 crore. All right. This must be understand out because not a single paisa except ₹ 2,000 crore came to Telangana. All that Mr. Jairam Ramesh said in those days was – 'equality'. Whatever it is, ''if we are getting AIIMS, you are getting it. If we are getting IIM, you are getting IIM. If we are getting the university, you will get the tribal university''. Did not you say that? You set up thirteen institutions. Did you give me one? You gave them three. We kept quiet. We thought we will have to fight. We don't go with the begging bowls to those people as long as people are with us. What is the question today? That is why, when the Government came or even the Chairman came and said about 2,000 crore

[Dr. K. Keshava Rao]

of rupees, I said, "hell with this; who are you to give." It is my money. I give ₹ 30,000 crore every year to the Central pool. Nobody is giving me something out of charity. This should be understood. Yesterday, when the Prime Minister came and said, हमने तो तीन स्टेट किया, कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने तो तीन स्टेट करवा लिए, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, केशव राव जी।

डा. के. केशव राव: नहीं साहब, जरा सुनिए। मैं कभी इस चीज को लाता ही नहीं था, मैं उनका साथी हूं। कल रात रमेश साहब मेरे पास आए थे और मुझसे बोले थे कि साहब, हम यह रेज़ कर रहे हैं। मैंने कहा रेज़ करिए। But do not try to act like that बिकॉज़ किस तरीके से हम रूल करते हैं, आपको मालूम है। हमारी पॉपुलेरिटी पर एक अंगुली भी मत उठाइए। आपने 5 मर्तबा कंटेस्ट किया, डिपॉज़िट लूज़ कर दिया, वह भी याद रखेंगे। कल कंटेस्ट करेंगे तो डिपोजिट लूज़ कर देंगे, वह भी याद रखेंगे। जो भी हो, चाहे आप हों या आपके दोस्त हों, जब डिपॉज़िट आएगा तो हम छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ देंगे, क्लोज कर लेंगे, अगर डिपॉज़िट आ गया। तो ठीक है, वह बात नहीं बोल रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): धन्यवाद।

डा. के. केशव राव: मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। नीरज जी, मैं तो ओपन कर रहा हूं, हर वक्त तो वही बोलता हूं न। उनके प्रेजिडेंट आएं तो भी हम लोग बोलेंगे। ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? ज़रा कंटेस्ट करने के लिए बताइए, वह बतला देते हैं। वह नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूं। We are with you but this is something else. How can you be allowed to stand there? One of my friends asked for a chair for you to sit. All that we wish is to ask the Finance Minister, ask the Government to sort out these issues. If all of us feel that something wrong has been done to Andhra, if we feel that something has gone wrong, let the Government sit and sort it out. You have not done that during those 12 days when the Reorganisation Act was passed. Within 12 days, they completed the rules. We thought that if something is still left, we will sort it out.

So, here is a question of money. They say that they have already given you 12,000 or 13,000 crores of rupees. If more needs to be given, let them give it but let them not do this. यह मैच फिक्सिंग को आप लोग बस करो। नहीं तो एक आदमी को आप रूम से निकाल देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, एक आदमी को कुर्सी देते हैं और बोलते हैं क्या हो रहा है यह? मज़ाक हो रहा है इस पार्लियामेंट का? अब तेलंगाना के बारे में बताइए। हम लोगों ने क्या नहीं किया? हमने आपसे नहीं पूछा है। आपने आज तक इस बजट में एक भी चीज तेलंगाना के बारे में नहीं कहा। महोदय, आप जानते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। चूंकि आप तेलंगाना जानते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। हम इंडिया की one of the biggest irrigation projects, Kaleshwaram, build कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... बाद में पूछा कि कुछ पैसे दे देते

तो अच्छा होता। जरूर यह तो नेशनल प्रोजेक्ट है, एक मॉडल है, शायद मेरा इतना अच्छा हिन्दी नहीं है, उनकी हिन्दी अच्छी होगी। शायद उनकी हिन्दी मेरे जैसी नहीं होगी, उनकी हिन्दी अच्छी होगी, जिसे मैं नहीं समझ सकता हूं, वह अलग बात है। उन्होंने कह दिया कि यह मॉडल बन जाएगा। हमने बाद में उनसे कहा कि आप दस हज़ार करोड़ रुपए दे दीजिए, लेकिन आज तक हमें एक पैसा नहीं दिया गया। हमारे पास पहले पानी नहीं था, आप इस संबंध में जानते हैं क्योंकि आपके पास पानी नहीं पहुंचना था, पानी के बिना तो कोई स्टेट नहीं चल सकती तो हमने क्या किया – हमने पहली मर्तबा lift irrigation से ...(**समय की घंटी**)... महोदय, एक मिनट। Lift irrigation से one crore acres of land we have covered. We have already covered three projects. Within three months we have completed the project in Bhadrachalam. Like that be, we are trying to do it. आपने अपने दिल में रख लिया है कि ये तो अपने नहीं हैं, चलिए, हम लड़ लेंगे। हम लोग लड़ेंगे भी – आप उसकी फिक्र मत कीजिए।

अब मैं आपके बजट की बात करता हूं। आपके बजट में 10 ट्रेन के लिए हम लोग इतने साल से पूछ रहे हैं। चालीस साल से हम लोग काज़ीपेट में कोच फैक्टरी की मांग कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में तीन मर्तबा फाइनेंस मिनिस्टर साहब बोले, no, no, this time we are going to give you AIIMS. उन्होंने announce किया, on the floor of the House. But no AIIMS. वह हवा में आ रहा होगा या शायद लॉरी में आ रहा होगा, लेकिन वह एम्स बहुत जल्दी आएगा। महोदय, उन्होंने हमें दो रेल लाइन्स दीं, एक-एक बोल देता हूं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): केशव राव जी, अब समाप्त कीजिए।

डा. के. केशव रावः महोदय, मैं लास्ट में एक सबसे बड़ी चीज़ बोलना चाहता हूं। आप एक्ट छोड़ दीजिए, बातें छोड़ दीजिए, promises छोड़ दीजिए, वहां पर जो तारीफें करते हैं, हर सेंट्रल मिनिस्टर तेलंगाना आकर कहता है कि इतना बड़ा हमने सोचा ही नहीं। आप उसे भी छोड़ दीजिए। Constitution में लिखा हुआ है कि every State shall have one High Court. वहां पर आज तक हाई कोर्ट नहीं आया है। At some place, you start giving it. But in our case, no sympathy has ever come from you. आप इस बारे में सोचना शुरू कीजिए, वहां हाई कोर्ट दीजिए। वहां पर कौन suffer कर रहा है – हम लोग suffer कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। तो कुछ भी हो ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, केशव राव जी, धन्यवाद। श्री शमशेर सिंह मन्हास।

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, it is there in the Act and the Government has delayed ...(*Interruptions*)... This is completely inexcusable. ...(*Interruptions*)...

डा. के. केशव रावः महोदय, मैं एक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं तो Constitution की बात कर रहा हूं। Constitutional provision होने पर भी आप नहीं करते तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी?

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, केशव राव जी, धन्यवाद।

डा. के. केशव राव: महोदय, मैं इतना कहते हुए, अगर आपने मुझे चांस दिया तो मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूं, मुझे यह issue join करना था, वरना as far as the Budget is concerned, सब लोगों ने डिटेल में बातें कह दी हैं, उस संबंध में मैं बात नहीं करना चाहता हूं। आप कुछ बोल रहे हैं। ये economic stability की बात कर रहे हैं। उन्होंने 12 सवाल पूछ लिए हैं, हमारे देरेक साहब ने दस सवाल पूछ लिए हैं, मैं उन questions को छोड़कर दूसरे questions आपसे पूछना चाहता हूं। आप macro stability, fiscal consolidation और slippages की बात कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है? On the other side, I don't know whether there is any economist, but I can ask Mr. Jairam Ramesh or Gujralji. Tell me what this slippage means. It means nothing but increase in the deficit, simple economics. Or it means increase in inflation, simple economics. Is it not true? Now, the second question is, गुजराल जी ने कहा कि यह बहुत difficult challenge है, सख्त challenge है। It is true because post demonetization, you had your problems. But what did you do to ...(*Interruptions*)... In the demonetization, ...(*Interruptions*)... आपको टाइम अभी दिखाई देता है साहब। **...(व्यवधान)...** आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब आपको सिर्फ टाइम ही दिखाई दे रहा है। अब आपको टाइम बराबर दिखेगा। महोदय, मैं आपके थ्रू मंत्री जी से पूछता हूं कि you got funds after demonetization. It must go to Jan Dhan account holders or whatever it is. We thought it would go because the economic prudence suggests that. ...(*Time-bell rings*)... But what did we do? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Keshava Raoji, please conclude it within one minute.

DR. K. KESHAVA RAO: Anyhow, I would not say everything is wrong in this Budget because I am not going to join issue with them, nor am I trying to make a point there. इसमें one-upmanship नहीं है। There are fundamental difficulties which are overlooking those things. There were twelve questions from there and ten questions from here. A few of them you might answer well, a few of them you will ...(*Interruptions*)... वह आप देखिए, वरना the big opportunity that you got is missed. I would say in the Budget, you had a good opportunity, which you have missed.

श्री शमशेर सिंह मन्हास (जम्मू और कश्मीर): आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, कल से मैं इस बजट पर चर्चा सुन रहा था। बजट पर चर्चा सुनते-सुनते कुछ महानुभावों ने इसको questionnaire बना दिया। किसी ने 12 प्रश्न पूछे, किसी ने 14 प्रश्न पूछे, किसी ने 8 प्रश्न पूछे। इसका मतबल यह है कि हम इतने सक्षम हैं कि हमसे आप कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि हम कुछ अच्छा करें। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं और आजादी के उपरान्त 55 वर्ष तक कांग्रेस ने, जिसमें से 40 वर्ष एक ही वंश ने राज किया है और 15 वर्ष उनके जो बाकी साथी थे, उन्होंने किया है। ये कुल मिलाकर 15-16 हजार दिन बनते हैं।

मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वह प्रदेश जम्मू-कश्मीर बड़ा संवेदनशील है। हमारे LOP साहब, यहां पर होते, हमारे आज़ाद साहब यहां पर होते, तो मैं उनसे पूछता कि वे कौन सी जगह से आते हैं, किस प्रकार का वह जंगल है और वहां कौन-कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं? आज अगर देखा जाए तो वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर सड़क नहीं है, बाकी की बात तो आप छोड़ दीजिए। यहां तक कि वहां पर बच्चों के रहने के लिए जगह तक नहीं है। उनके पास एक ही कमरा है और वह भी पूरा लकड़ी का बना हुआ, जिसमें पूरा परिवार रहता है। वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो वे पिछले 60 सालों से मूलभूत सुविधाओं से क्यों वंचित हैं? 55 वर्ष राज करने के उपरान्त क्या कांग्रेस ने उस दिशा में विचार नहीं किया? आज़ाद साहब वहां के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर आज तक जो कुछ होना चाहिए था वह क्यों नहीं हुआ? आज तक भी वहां सड़क नहीं है। मैंने वहां एक गांव adopt किया है, जिसे आदर्श गांव में रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24 किलोमीटर steep चढ़ाई है, जो आप 10 घंटों में भी नहीं चढ़ सकते हो। आज भी सड़क के नाम पर पगडंडी है, जंगल से आते हुए किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। आप dispensary को छोड़िए, स्कूल को छोड़िए, वैटरनेरी हॉस्पिटल को छोड़िए यहां तक कि वहां पर पंचायत घर तक नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर लोग रहते होंगे? जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्होंने अपना मकान बनाया हुआ है, पक्की छतों के निर्माण की बात तो आप छोड़ दीजिए, उनके बारे में कौन सोचेगा और कौन विचार करेगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब तक दूर-दराज कंदराओं में बैठे हुए व्यक्ति को, हर प्रकार की सुविधाएं न मिल जाएं, तब तक हमको कार्य करना पड़ेगा। हम उसी राह पर चल पड़े हैं और उसी राह को आज हम देख रहे हैं। इस प्रकार से जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, हमारी सरकार उन योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। जिस प्रकार का 55 वर्ष तक आपका राज रहा और 15 वर्ष एक ही वंश का राज रहा है, पिछले 70 सालों में वहां पर क्या हुआ है? मैं अपने प्रदेश की बात कह रहा हूं और मैं उससे बाहर नहीं जाना चाहता हूं, अगर मैं पूरे देश की बात करना चाहूंगा, तो पूरा देश इसी हालत से गुजर रहा है। चाहे आदिवासी क्षेत्र रहा हो, चाहे नार्थ-ईस्ट रीजन रहा हो, चाहे तमिलनाडु का क्षेत्र रहा हो, पूरे देश में सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। वहां पर वे सुविधाएं कौन पहुंचाएगा? वहां पर कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? जो लोग वहां पर रहते हैं क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? क्या वे लोग नहीं चाहते हैं कि उनको भी सुविधाएं मिले? वे भी BA कर सकें, MBA सकें, Medical College में पढ़ने जा सकें? वहां पर तो एक छोटा सा स्कूल तक नहीं है, तो वे क्या पढ़ पाएंगे? इसलिए इन सब चीजों के लिए, छोटी-छोटी बातों के लिए, आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार का बजट पेश किया है, उस राह पर चलने का प्रयास किया है और ईमानदारी से किया है जिससे कि यह देश आगे बढ़ सके। उन लोगों में यह कैसे विचार हो सकता है? उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हमारे 40 प्रतिशत लोग बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, करीब 10 करोड़ परिवार आते हैं, 50 करोड़ की आबादी आती है, जिनके लिए कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य के माध्यम से अगर देखा जाए, तो किसी को किडनी फेल्योर होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है और किसी को दूसरी बीमारी लगती है, इनके इलाज पर बड़े-बड़े खचे आते हैं। जो लोग कंदराओं में रहते हैं, उनके पास जीवन यापन के लिए साधन नहीं हैं, तो वे लोग कहां से चार लाख रुपये, पांच लाख रुपये इलाज करवाने के लिए देंगे, स्वास्थ्य को ठीक

[श्री शमशेर सिंह मन्हास]

करवाने के लिए देंगे, वे कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक करवाने के लिए जाएंगे, वे कैसे आपरेशन करवाने के लिए जा पाएंगे? इसीलिए सरकार की ओर से उनके लिए पांच लाख के स्वास्थ्य बीमा की योजना बनायी गयी है, जो कंदराओं में रहते हैं। हम तो केवल सोचते हैं, विचार करते हैं और विचारों को क्रियान्वित भी करना पड़ेगा। इन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, वे पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। बंधुओ, जिस प्रकार से पहाड़ों पर किसानी होती है, आपने देखा होगा कि वहां पर ट्रेक्टर नहीं चलता है, वहां पर हल से जुताई नहीं हो सकती, वहां पर सिर्फ कुदाल से कुदाली करानी पड़ती है और धीरे-धीरे वहां पर किसान अपनी खेती-बाड़ी प्रारम्भ करते हैं– चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, वह कुदाल लेकर सुबह से शाम तक कुदाली करता है, फिर चार-चार, पांच-पांच महीने बाद एक फसल पैदा होती है। वहां पर सात महीने तो बर्फ रहती है, इसलिए वहां पर ज्यादा कुछ नहीं होता है। वहां पर एक कमरे के अंदर लोग अपना जीवनयापन करते हैं। इस प्रकार के लोगों के बारे में बात होनी चाहिए, उनके जीवनयापन के लिए आज तक क्यों कुछ नहीं हुआ, 70 साल में भी लोग वहां पर ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनके बारे में पहले से क्यों नहीं सोचा गया? हम हवाई जहाज की यात्रा तो कर सकते हैं, ऊपर से हेलिकॉप्टर के माध्यम से भाषण देने के लिए जा सकते हैं, अपने लिए वोट मांगने के लिए जा सकते हैं, किन्तु बंधुओ, उनके बारे में ईमानदारी से सोचा जाए और उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएं।

वहां पर पशु रखे जाते हैं और पशुओं के लिए वैटरनरी अस्पताल होने चाहिए, लेकिन वहां तो वैटरनरी डिस्पेंसरी तक नहीं है। अभी मैंने जिस गांव को गोद लिया है, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिस गांव को लिया है, उसमें अभी विकास का काम शुरू करवाया है। वह काम भी तीन वर्षों के बाद पूरा होगा, फिर वहां पर लोग आसानी से जा सकेंगे। इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में केवल हम क्वेश्चनेयर ही नहीं बनाएं, पूछताछ न करें, बल्कि मैं कहता हूं कि आपने हम पर उम्मीदें लगायी हैं और हम आपकी उम्मीदों पर पूरे खरे उतरेंगे। आने वाले समय में हम इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे किसान का मामला होगा, चाहे पढ़े-लिखे नौजवानों का मामला होगा और हम बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वहां पर किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से 1400 करोड़ रुपया दिया गया, जिससे कि वहां पर अच्छी तरह से फूड प्रोसेसिंग हो सके। इससे पहले इसके लिए 200 करोड़, 250 करोड़ रुपये देते थे और वह जाता कहां था ? आप जानते हैं कि अगर पिछले घोटालों को निकाला जाए, तो पूरे 12 लाख करोड़ रुपये का घोटाला था। वह पैसा कहां गया? अगर वह पैसा देश के विकास में लगता, उन कंदराओं में लगता, तो अपने देश का अच्छा विकास होता। आज यह देश सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। यह सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार की राह दिखाई गई है, उस राह को हमें देखना होगा, उस राह पर हमें चलना होगा। अगर हम ईमानदारी से इस राह पर चलेंगे, तो पूरा देश आगे बढ़ेगा।

दूसरा, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत वहां पर इस प्रकार से योजनाएं बनायी गयी हैं कि बॉर्डर पर रहने वाले बंधुओं को सुविधाएं मिल सकें। पिछले दिनों में उनको केवल गोली

मिलती थी, जिसके कारण वे वहां से उजड़कर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पीछे आते थे और उनको बसाने में 10-15 वर्ष लग जाते थे। आज जैसे ही वे बंधु बॉर्डर एरिया से वहां पर आते हैं, उसी दिन से उनके लिए मकानों का किस प्रकार से निर्माण हो सके, किस प्रकार से उनको बसाया जाए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। ये सारी योजनाएं कौन बना रहा है, किसके अंतर्गत बन रही हैं? अगर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत इस प्रकार की योजना न बने, तो वे बंधु उजड़कर रह जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो कश्मीर में 1990 से आज तक किस प्रकार के हालात बने हुए हैं, किस प्रकार का वातावरण बना हुआ था? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे साथ श्रीनगर में आइए, मैं पूरा कश्मीर घुमाकर लाता हूं, आपको बिल्कुल सुरक्षित और आराम से सारे टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाकर लाऊंगा। इस प्रकार का वातावरण किस ने खड़ा किया? यह हमारी सरकार ने किया है। हमारे गृह मंत्री ने किया है। महोदय, इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। अगर इस प्रकार की बातों को लेकर हमें केवल questionnaire प्राप्त करना है, हमें पूछताछ करनी है, हमें नुक्ताचीनी करनी है, टीका-टिप्पणी करनी है, तो आप टीका-टिप्पणी करते रहिए, लेकिन हम वहां आगे बढ़कर लोगों की सेवा करते रहेंगे क्योंकि लोगों की सेवा करना हमारा कर्त्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। यह देश मेरी मां है और मैं इस का पुत्र हूं और पुत्र होने के नाते मैं हमेशा मां की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, धन्यवाद।

श्रीमती रेणुका चौधरी (आंध्र प्रदेश): महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया है। आप जानते हैं कि जब देश में बजट पेश किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि उस पर देश के मशहूर Economists बैठकर सोचते हैं, वे आंकड़े और दिशा जरूर बनाकर देते हैं, मगर भारतवासी और मेरे जैसी गृहस्थ महिला भी बजट की ओर देखती है कि हमारी जिंदगी पर इस का आने वाले साल में क्या असर पड़ने वाला है? हम कहां पैसे की बचत करें? वह कैसे परिवार की प्रोग्रेस देखे, बच्चों को कैसे शिक्षित बनाए और अगर एक सामान्य किसान का परिवार है, तो उसे कई बातों को सोचना पड़ता है। इसलिए जब बजट पेश होता है, तो सिर्फ बातों से हवा महल की तरह बात करेंगे, तो कुछ नहीं मिलता है।

महोदय, ये मेरे colleagues यहां इतनी देर से खड़े हैं, ये इतने दिनों से आवाज उठा रहे हैं और हमारे respected colleague Dr. K. Keshava Rao जी बहुत गर्म होकर बोले हैं। वास्तव में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हमारे जुड़वां बच्चे थे, लेकिन आज एक तेलुगू दूसरे तेलुगू से लड़ रहा है, खून बह रहा है, वहां नदी-तालाब सूख गए हैं। एक नया राज्य बनना था, मगर हुआ क्या? अगर कोई फैसला इस घर में होता है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसे निभाया जाएगा? अगर सरकार बदल जाती है तो क्या वायदा निभाया नहीं जाता है? Why has Andhra Pradesh not been given their status as a special category status? Why have they not been given? इन को मना करने का क्या कारण है आपके पास? You had said that you will allocate funds. What is the percentage that you have actually allocated? Do you know what is happening in Telangana as well? Under PMGSY, you have given us tokenism. हम tribal welfare development के लिए जरूर budget heads के नीचे गए हैं। मेरा जिला खम्मम है, जहां तेलंगाना में सब से ज्यादा tribals रहते हैं। हमारे तंडागुडम में, हमने

[श्रीमती रेणुका चौधरी]

जो उसे नाम दिया है, वहां हमें चलने का अधिकार नहीं है। वहां हमारे घरों से सड़क तक पहुंचने में तीन-तीन दिन लगते हैं। महोदय, यह बहुत बेरहम सरकार है और ये सिर्फ दिखाने के लिए बजट में बड़ी-बड़ी बातें बोलती है। वास्तव में हो क्या रहा है? आपने किसानों को बहुत उम्मीद दिलायी कि आप किसान का बजट पेश कर रहे हैं। हमने भी सोचा कि शायद ऐसा होगा। मैं आपकी मजबूरी समझती हूं। आज आप को देश भर के किसानों की आह लग रही है। यह बात आपको समझ आ गयी है और अगले साल चुनाव होंगे, इसलिए आप जल्दबाजी में किसान का बजट लेकर आए। इस में आपने उन्हें कितने पैसे दिए हैं? What is your overall percentage that you have increased in the allocation? यह मुझे समझाइए। आप एम.एस.पी. देंगे। आप समझते हैं कि एम.एस.पी. क्या चीज है? आप और आप के बाबू लोग ए.सी. कमरों में बैठकर, जिन्होंने कभी जमीन को जोता नहीं, जब आपने कभी देखा ही नहीं, वह तकलीफ आपको महसूस ही नहीं हुई जब हम खेत में खड़े रहते हैं और हमारी फसल सूख जाती है या bumper crop लेकर हम मार्केट चले जाते हैं और अच्छा rate रेट नहीं मिलता है, तो क्या आप जानते हैं कि वह तकलीफ कैसी है? क्या आप जानते हैं कि जो हम महिला किसान होती हैं, तो हमने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है, ताकि हमारी फसल अच्छी पैदा हो? ...(**व्यवधान**)... हमें समझ में आ गया कि आपको जानकारी नहीं है। आपके सवालों से समझ में आ जाता है कि आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। आप और ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए मैं कहती हूं कि आप सोच-समझकर कदम उठाएं। किसान का आक्रोश खत्म होने वाला नहीं है, यह तो शुरुआत है, मेरे भाई! हम इलेक्शन तक देखते रहेंगे कि MSP क्या है और किसान का ABC क्या है, आपको समझ में आएगा। आप कह रहे हैं कि हम इसको extension of MSP देते जा रहे हैं बाकी crops के लिए, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला नीति आयोग करेगा मगर यह नहीं कहा गया कि इसका खर्चा और कर्जा कहां से आएगा। इसके लिए कोई Budget allocation ही नहीं है और Ministry of Agriculture and Farmers Welfare के लिए कोई allocation नहीं है, तो फिर आप Revised Estimate में क्या लेकर आए हैं? मुझे यह बात समझ में आ रही है, लेकिन इन नए राज करने वालों की समझ में नहीं आ रही है। आपके यहां तो कह देते हैं कि लाल किले से भी लोग बोलते हैं, मगर होता क्या है कि घूम-फिर कर आप राज्य सरकारों के ऊपर खर्चा डाल देते हैं और हमारी राज्य सरकारें यह खर्चा उठा नहीं सकती हैं। मगर आप ड्रामा तो बहुत अच्छा करते हैं। आप देखते रहिए, आज के दिन जब किसान मार्केट चला जाता है, तो क्या आप उसको ...(**व्यवधान**)... आप मेरी बात विनम्रता से सुनिए। आपको सच सुनने का हौसला भी रखना चाहिए, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। मैं जानती हूं कि कभी-कभी यह सच चुभ जाता है। ...(**व्यवधान**)... आपने हाउस में आकर कह दिया, We are forced to bring up the price of farmers. महोदय, आज कम से कम यह सरकार किसानों के बारे में बोल रही है और ये कम से कम उनका नाम तो ले रहे हैं। पहले तो यह भी नहीं होता था। But, what are the outlays for the market intervention and price support scheme? जो बहुत जरूरी है। ये क्या करें, उसमें गिरावट है। From ₹ 950 crores of Revised Estimate of last year to 200 करोड़। आप हमें 200 करोड़ में किसान का भविष्य दिखा रहे हैं, वाह रे वाह! यह मुझे समझ में नहीं आया। आपने जो यह NPA write-off industry के लिए दिया है, इससे किसी की एक दमड़ी की भी नौकरी नहीं लगी। जब आपने industry में relief दिया है, तो हमारे किसानों को कर्जे में relief नहीं देंगे? किसान की debt relief के लिए आपने आज

5.00 P.M.

तक दो कौड़ी भी नहीं दी है। हमारे किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। आज मुझे यह कहते हुए ज्यादा दुख हो रहा है कि मेरे क्षेत्र खम्मम में भी एक किसान ने आत्महत्या की है। उसने दो बोर वैल खोदे, लेकिन उनमें से एक बूंद पानी भी नहीं निकाला। हम वहां कपास bumper crop उगाते हैं, पैडी उगाते हैं और मिर्च उगाते हैं। एक बार कर्जे के रूट पर चले गए, तो किसान को कोई यू टर्न नहीं मिलता है। इन tenant farmers की क्या हालत है? आप लोगों ने कभी जमीन कोल पर ली है, क्योंकि हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि अपनी जमीन रहे। जब हम कोल पर जमीन लेते हैं और फसल बोते समय नुकसान हो जाता है, मैंने अपने बजट में बड़े गौर से देखा है, इनके लिए एक भी लफ्ज़ नहीं है, एक सोच नहीं है और एक विचार नहीं है कि कोलदार का क्या हाल होगा? ...(**समय की घंटी**)... महोदय, माफ कीजिए। आप मेरी तरफ देखकर घंटी मत बजाइए। आप देखिए कि सूइसाइड करने वालों में तेलंगाना और ओडिशा में जितने भी कोलदार tenant farmers हैं, इनके लिए तो कोई सहूलियत नहीं है और इनके लिए इस बजट में कोई सपोर्ट भी नहीं है। महिला किसान का – वैसे तो इस हाउस में हमने महिला की गरिमा और मर्यादा देख ली है, मगर क्या आप जानते हैं कि महिला किसान के हालात कैसे होते हैं? There is no gender-desegregated land record. क्या कोई एग्रीकल्चरल क्रेडिट मिल रहा है? जब कभी नेचुरल डिजास्टर हो जाती है तो क्या हमें SHG loans की कोई छूट मिलती है? आपके बैंक्स वसूली तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आप यह बताइए कि आपने आज के दिन में एग्रीकल्चरल क्रेडिट में कितना खर्च किया है? आपके बैंक्स हमारे गरीब किसान के घर से, जब उसके घर पर कुछ और नहीं बचा होता तो उसके घर की चौखट तक लेकर चले जाते हैं। उसके बाद बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री वाले लोग अपनी Mercedes-Benz में देश भर में घूमते हैं। क्या आपको पता है कि मर्सिडीज़ लग्ज़री कार की ईएमआई ट्रैक्टर की ईएमआई से सस्ती है? ट्रैक्टर का क्या दाम है और क्या क्वालिटी है? क्या आपने कभी चलाकर देखा है? आज के दिन देखें, तो ट्रैक्टर का वजन कम हो गया है। ...(**समय की घंटी**)... जब हम खेत जोतने जाते हैं तो हमारा ट्रैक्टर उठ जाता है, क्योंकि उसके गेज में कमी आ गई है। आप देखिए कि आपने महिला किसान को कुछ नहीं दिया है। landless women, especially, Dalit women, expansion of higher maternity and ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Renukaji, I have given double time to you. Please conclude. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती रेणुका चौधरीः उपसभाध्यक्ष जी, बस एक मिनट। मैं कनक्लूड कर रही हूं। अब मैं स्वास्थ्य के बारे में क्या बताऊं? सरकार तो तंदुरुस्त लगती है, मगर पीछे से कुछ कहने के लिए तो आपने कुछ कह दिया है कि देश भर में इतने सारे इंश्यारेंस होंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि यह होने वाली बात नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): होगा, होगा।

श्रीमती रेणुका चौधरीः आप बोलिए, लेकिन हमें झूठी उम्मीदें मत दीजिए, क्योंकि हम अपने मदों से आटे के डिब्बे में छिपाकर, दमड़ी-दमड़ी जोड़कर पैसों की जो बचत करते हैं, हम वह पैसा भी यह सोचकर खर्च कर लेंगे कि सरकार हमारा सहारा बनेगी। महोदय, यह होने वाली बात नहीं है। आप मुझे सारी स्कीम्स के आंकड़े दें। आपने घंटी बजा दी है, इसलिए मैं मजबूर हूं

[श्रीमती रेणुका चौधरी]

कि मैं इस पर संक्षेप में बोलूं, पर आप मुझे बताइए कि PMRPRY, इस स्कीम के अंदर आपने एक पैसा allocate नहीं किया। "प्रधान मंत्री राष्ट्रीय पकौड़ा योजना" में कहीं भी एक पैसा नहीं दिया है ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखरः मुझे ऑब्जेक्शन है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रेणुका चौधरीः महोदय, मुझे skill development पर यह कहना था कि हमें इस head के नीचे कहीं भी कुछ पैसे नहीं मिले, मगर this is the crucial part. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Renukaji, please conclude.

श्रीमती रेणुका चौधरीः महोदय ...(**व्यवधान**)... Sir, I am concluding. ...(*Interruptions*)... इसका फिस्कल टारगेट ...(**व्यवधान**)... 3.2 परसेंट से उतर गया है। You have failed to deliver on the 3.2 per cent target for next year's balance. उस तरफ से अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि हमने Food Park दिया। क्या आपको food processing पर जानकारी है कि उन दिए हुए 42 Food Parks में से 4 चलते हैं, वे भी लंगड़ाते-लंगड़ाते। आपके आंकड़े देने से तो वे चार भी नहीं चल रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): रेणुका जी, मैं दूसरे सदस्य का नाम ले लूंगा, आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती रेणुका चौधरीः सर, एक मेन मुद्दा है। महिलाओ के निर्भया फंड में भी कटौती हो गई। निर्भया फंड में भी कटौती हो गई, हालांकि निर्भया क्या है? एक औरत के साथ बलात्कार होने के बाद उसको कुछ सहूलियत और छूट देने के लिए कुछ व्यवस्था रखते हैं, मगर मैं सोचती हूं कि इस निर्भया फंड को हटा ही दें, क्योंकि बलात्कार की शिकार महिला की मर्यादा का सवाल है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): मैं अगला नाम बोलता हूं, श्री अनिल देसाई।

श्रीमती रेणुका चौधरीः * और गृह मंत्री, जिनको हमारी रक्षा करनी चाहिए, जिन्हें कानून बनाना चाहिए, वे भी ट्वीट करते हैं। अगर इस हाउस में ये हालात हैं, तो सड़क पर ...(**व्यवधान**)... क्या इशारा ...(**व्यवधान**)... हो गया है? आप किस बात पर बोल रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... आप महिला सुरक्षा के लिए क्या कहते हैं? ...(**व्यवधान**)... महिलाओं के लिए ...(**व्यवधान**)... क्या करते हैं? ...(**व्यवधान**)... आप आंकड़े देते जाते हैं ...(**व्यवधान**)... आंकड़े दिखाते हैं। ...(**व्यवधान**)... महोदय, इन आंकड़ों से कुछ नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)... आपका इरादा होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... महिलाओं की मर्यादा होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... अगर आप यह नहीं दे सकते हैं, तो * से इस बजट का ड्रामा मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): माननीय सदस्या ने माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए जो बात बोली है ...(**व्यवधान**)... वह unparliamentary है। ...(**व्यवधान**)...

---

*Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): जो अनपार्लियामेंटरी शब्द हैं, मैं उन्हें निकाल दूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: उनके लिए जिस तरह की भाषा बोली गई है, उसको expunge किया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): expunge किया जाएगा। श्री तिरुचि शिवा, आप बोलिए।

श्रीमती रेणुका चौधरी: उपसभापति जी ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): देशखए, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... I will remove. I will expunge that thing from the topic. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: ये किस तरह की भाषा बोल रही हैं? ...(**व्यवधान**)... अगर इनको आईना दिखाया जाएगा ...(**व्यवधान**)... तो उस आईने में ...(**व्यवधान**)... अगर आपकी कांग्रेस का ...(**व्यवधान**)... है तो हम क्या कर सकते हैं? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): श्री तिरुचि शिवा जी, आप बोलिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You sit down. ...(*Interruptions*)... If it is unparliamentary, it will be removed. ...(*Interruptions*)... Sit down. If it is unparliamentary, it will be removed. ...(*Interruptions*)... Sit down. देखिए, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: महोदय, ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। ...(**व्यवधान**)... किस तरीके से ये बोल रहे हैं। अगर इनको आईना दिखाया जाएगा, तो उस आईने में ...(**व्यवधान**)... तो हम क्या कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am happy and proud to participate in this debate as a representative of the DMK Party which has been a pioneer in social justice. Not only that, we have been a forerunner in implementing the social welfare schemes, first ever in the country which has been taken as a cue by the Union Government in this Budget. Sir, the Health Insurance Scheme, the Maternity Benefit Scheme, the Farmers' Market, the LPG connections to the poor have all been implemented first ever in Tamil Nadu. So also in the Budget, the Government has assured that in the year 2022, whole of India and the rural parts will be electrified. Sir, way back in 1972 itself, 50 years before when our leader, Dr. Kalaignar was the Chief Minister, all the rural villages in Tamil Nadu had been electrified. So, Sir, I am very happy that we have been pioneer and forerunner in implementing the welfare schemes. The second is we are also happy that regional parties have become the guiding force to the national parties whenever they brought such schemes.

[Shri Tiruchi Siva]

Sir, I would like to thank the Finance Minister on this occasion, before going to the bitter part of my speech, that he has reduced the GST for the food products in the hotels from 18 per cent to 5 per cent, which has been represented by us, and he has agreed to that. We are thankful to him for that. So also, he has exempted tractors from commercial vehicles and retained them as agricultural part. The third is, Sir, today, we have received a letter from the Finance Minister that the proposal for borewells, which are used for the irrigation purposes, to be exempted from the GST, is to be placed before the GST Council which is to sit next time.

I come to the main part of the Budget Speech. The Economic Survey has stated that the major part of our economy is decided by the informal sector, that is, 87 per cent. Out of the 87 per cent, only 12 per cent of the firms are registered under the GST but do not provide social security. Less than 0.1 per cent provide social security but are not registered under the GST. Sir, the Government when it assured that the workforce in the formal sector will be given adequate benefits, equal to the informal sector, I would like to say that because of demonetisation the social security scheme in the informal sector has suffered a lot. Sir, in the Budget, the Finance Minister has said, time and again, that the demonetisation has done good for the country. Yesterday, my good colleague, Shri Bhupender Yadav, spoke also said that they have shelled out the black money. It is very surprising. Sir, I would like to say that when demonetisation was announced on 16th November, 2016, the total amount of SBN, that is, Specified Bank Notes, of ₹ 1000 and ₹ 500 denominations was valued at ₹ 15.4 lakh crore, that is, 86.9 per cent of the total value of the currency in the circulation. Later the Annual Report of the RBI stated that subject to future corrections based on verification process when completed, the estimated value of SBN, Specified Bank Notes received as on 30th June, 2017, that is, within six months after the demonetisation was announced, ₹ 15.28 lakh crore, which constitutes 98.96 per cent of the currency. So, twelve lakh worth of currency has not come into the mainstream. I have little knowledge about it. I would like the Government to clarify and enlighten me from where it has shelled out the black money. If the total amount of money in circulation was only 15.4 lakh crores of rupees, and the money that has been deposited back is ₹ 15.28 lakh crores, from where does this black money come? Nothing has been shown. So is the case with the fake currency. The fake currency was supposed to be only forty-three…

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Sivaji, your five minutes are over. I request you to conclude.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, we have been waiting. One or two Members from the 'Others' category are not present. I just want a little time more.

Our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, had already speculated and stated that the GDP growth rate would decline by two per cent. It was very vivid and clear in the 4th quarter of 2016-17, when the GDP had declined from 7% to 6.1%. Also, unemployment would be increasing.

Sir, the third very important issue is the condition of our agriculture. The Government has assured that in the year 2022 the income of farmers would double, and that the MSP would be 150 % more or so. But, first, I would like to ask whether it is an Annual Plan or a Five-Year Plan. The Budget is considered to be an Annual Plan. But all those announcements are about a further period of not just one or two years, but about a period of five years. Sir, let me say that we should not basically forget that India is an agricultural country. And agricultural land has been declining year after year. We should also recollect that during the economic recession, which started from US and spread to the whole of Europe, India had not been affected, and this was mainly for two reasons. One was that the agricultural sector was sound; we were not in food deficit; the second was the public sector undertakings. And now you do not care for both these things! If, at all, you say that fiscal deficit has been brought under control, it is mainly because of, one, the slide in oil prices and, two, by way of disinvestment of even profit-making PSUs. Sir, steel plants are making profits. BHEL is making profit. They are all in Navaratna and Maharatna categories. But they are all being disinvested. One can understand if you are disinvesting some loss-making PSUs; but you are disinvesting even profit making PSUs, and with that money, you are balancing fiscal deficit and saying that you are capable of running the Government with some economic wisdom. No, Sir! I am very sorry to say, Sir, that statistics show that agricultural land has been reduced by 3.16 million hectares. Agricultural land has been diverted from 'agricultural use' to 'non-agricultural use'.

Sir, population has been increasing. Food requirement has been increasing. But agricultural land has been decreasing. Farmers are on the streets. When they were there at the Jantar Mantar, no one took care of them. They have been committing suicides; no one is taking care of them. During the demonetisation period, people died at the gates of banks; pensioners suffered without getting money from the banks; women who had saved some money without the knowledge of their men at homes, suffered. So, the farmers are not being taken care of, but, still, you are assuring that they would be safe! When agricultural land has been shrinking, when farmers are on the streets, and when they are committing suicides, how are you going to save the agricultural sector in this country? It is the largest employment-provider.

Now, some announcements have been made in the Budget...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Please conclude in one minute.

SHRI TIRUCHI SIVA: I would just conclude. What are the allocations? What is the increase and what is the decrease? The decrease is very much to be seen and felt, and the increase is not sufficient when compared to the required level.

Let me talk about the rural electrification scheme. What is that Pradhan Mantri…? I don't know because it is in Hindi. The amount allotted is ₹ 3,500 crores, whereas the amount that should have been allocated should have been ₹ 8,720 crores; so, it is 59 per cent less than what was required. So also on the Scheduled Castes Sub-Plan, it was recommended that ₹ 86,796 crore be allocated but only ₹ 56,719 crore has been allocated. I should say that only by looking at the announcements made by the Finance Minister and his statistics, one may assume that a little increase of money has been there but it is not to the required level.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): धन्यवाद, शिवा जी, आपके 10 मिनट हो गए हैं। I have given you double the time. Please conclude. I will have to call other names also.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, kindly extend the time. If you insist, I am prepared to sit down right now. ...(*Interruptions*)... Kindly permit me to speak for a few more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Kindly conclude in two minutes.

SHRI TIRUCHI SIVA: The demand of the Ministry of Human Resource Development was ₹ 55,000 crore. The amount allocated is ₹ 26,129 crore. Already there are nine lakh vacancies of teachers across the country. HRD is the most important portfolio of the Department in this country. It had demanded for ₹ 55,000 crore and the allocated money was 52 per cent less than the amount that should have been allocated. Sir, these are the issues that we have to focus. On these issues, you have to consider very seriously. The Budget which is being focused as pro-poor is not so. All those welfare schemes which you have given in the Budget, I would say that there are too many promises but there is not even a smallest, single guarantee as to how they would be implemented. What are the resources? How will it be done? They are only announcements on paper. At the very beginning itself I had said that we wanted to appreciate. But demonetisation has not benefited the country; the GST has taken the country to a very bad level. So many sectors are suffering because of shortcomings in the GST implementation. The Council is sitting again and again to reconsider GST rates. Above all these things, the agricultural sector is neglected, the educational sector is neglected, the employment issue has not been

tackled to the level it should have been tackled, but the Government says that one who is wearing a *hawai chappal* too can fly in the aircraft. But I am sorry to say that he may even fly with a *hawai chappal*, but he will not be able to fly with a bare body and an empty stomach.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Now Dr. Vikas Mahatme ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवालः उपसभाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी का रिप्लाई 5.00 बजे होना था और हम लोगों की 7.00 बजे की फ्लाइट है। या तो आप पहले वाली परम्परा को फॉलो कीजिए कि सब लोग बोल लें और रिप्लाई न हो, ताकि हम लोग भी जाएं। अगर रिप्लाई होना है, तो कितने बजे होना है? आज लास्ट डे है, लोक सभा एड्जर्न हो चुकी है, आप यहां बैठे हैं और हाउस को 10.00 बजे तक चलाने के मूड में हैं। हम लोग कोई 10.00 बजे तक थोड़े ही बैठे रहेंगे। हमें अपने क्षेत्र में वापस जाना है। हम परमानेंट राज्य सभा वाले नहीं हैं, हमें अपने-अपने क्षेत्रों में वापस जाना होता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका जवाब दें।

श्री विजय गोयलः महोदय, सदन सदस्यों की राय से चलता है और आज यही राय बनी थी कि तीन घंटे में हम इस चर्चा को समाप्त कर लेंगे, इसलिए मेरी पार्टी की तरफ से हमने चार वक्ताओं के नाम विद्ड्रॉ कर लिए थे, क्योंकि मुख्य वक्ता के माध्यम से सारी बातें आ जाती हैं। अगर दूसरी पार्टीज़ भी ऐसा कर सकें और खास तौर से मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन करूंगा कि अगर वे ऐसा कर सकें, तो कर लें और अगर नहीं कर सकें, तो अपनी बात को थोड़े शब्दों के अंदर रखें, ऐसा मेरा अनुरोध है। ऐसे में वित्त मंत्री जी जल्दी जवाब दे पाएंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः आप वित्त मंत्री का रिप्लाई करवाइए, क्योंकि बातें तो वही रिपीट हो रही हैं।

श्री विजय गोयलः यह बात आप उधर समझाइए न। ...(**व्यवधान**)...

श्री भूपेंद्र यादव (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष जी, आप समय तय कीजिए। ...(**व्यवधान**)... सब मेम्बर्स के लिए निश्चित समय तय होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Why are they insulting by asking us not to speak? ...(*Interruptions*)...

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रिपुन बोरा (असम): यह सही बात नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयलः प्रमोद जी, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट के लिए आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... प्रमोद जी, एक मिनट बैठिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): आनंद भास्कर रापोलू जी, वे बोल रहे हैं, अभी आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप भी नाम आएगा।

श्री विजय गोयलः उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन सदस्यों के लिए है। जैसी आपकी राय बनेगी, वैसा करेंगे। अगर वित्त मंत्री सायंकाल 6.00 बजे जवाब दें, तो इसके लिए आप सब लोग एग्री करें, तभी ऐसा हो सकता है और उसी के हिसाब से समय का आवंटन कर लें, क्योंकि इसमें सभी सदस्यों का सहयोग चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारीः माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और वरिष्ठ वक्ता रह गए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी insist करती है कि हम बोलेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): आप लोग बोलिए, लेकिन जितना टाइम दिया है, उतने टाइम में बोलिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारीः माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति पूरा आदर व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि जितने टाइम में और लोग बोले हैं और जितना टाइम आपने और सभी माननीय सदस्यों को दिया है, उसी रेश्यो में हमारे वक्ता भी टाइम लेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): डा. विकास महात्मे।

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): महोदय, यह बजट मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि इस बार के बजट में सारे भारतवासियों को भरोसा और विश्वास हुआ है कि अब भारत आगे बढ़ सकता है। थोड़े ही सालों में भारत एक विकसित देश बनने वाला है। चूंकि मैं डाक्टर हूं और मेडिकल फेकल्टी से आता हूं, इसलिए मैं ज्यादातर 'आयुष्मान भारत' के बारे में बताना चाहूंगा।

महोदय, 'आयुष्मान भारत' पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी सबसे बड़ी स्कीम है, जिसके माध्यम से देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है। अमेरिका में जैसे 'ओबामा केयर" को जाना जाता है, वैसे ही मुझे लगता है कि यह योजना सोशल मीडिया पर 'नमो केयर' कर के जानी जा रही है। इसी प्रकार से आगे भी इसकी पहचान होगी। मैं बताना चाहता हूं कि इस पर विपक्ष ने काफी सवाल उठाए थे। श्री जयराम रमेश जी का इसके बारे में कहना था कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए न कि केवल 50 करोड़ लोगों को ही इसका लाभ मिले। मुझे भी लगता है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत तो कुछ लोगों से ही हो सकती है। जैसे अभी 50 करोड़ लोगों से इसकी शुरुआत हो रही है, वैसे ही बचे हुए 70 करोड़ लोगों को हम कुछ ही साल में यह सुविधा दे पाएंगे। इस प्रकार देखें, तो इस देश में यूनिवर्षल हेल्थ केयर लाने के बारे में इस सरकार ने और हमने सबसे पहले कदम उठाया है।

महोदय, जैसा कहा गया कि इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर की भी आवश्यकता है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मैं आपके जरिए सदन और देशवासियों को बताना चाहूंगा कि यह सरकार देश में लगभग डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर्स खोल रही है। इससे मुझे लगता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर भी उसमें आने वाली है। इन वेलनैस हेल्थ सेंटर्स के जरिए हम प्राइमरी हेल्थ केयर का समाधान पूरी तरह से करेंगे। इस प्रकार से इन सेंटर्स के जरिए हम प्राइमरी हेल्थ केयर के साधन जनता तक पहुंचाएंगे।

महोदय, देश के लोगों और विपक्ष को भी लग रहा है कि इस योजना से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होगा। मुझे भी इसका डर है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश में गवर्नमेंट की चार इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो ये इंश्योरेंस ले सकती हैं और इसका

इम्प्लीमेंटेशन पूरे भारत में कर सकती हैं। इसलिए मेरा कहना है कि यदि इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन सरकार की इन चार कंपनियों के माध्यम से होता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। यह परेशानी शायद अमेरिका में हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष में नहीं होगी।

महोदय, काफी लोगों का यह सवाल भी था कि इस योजना से प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स को लाभ होगा, लेकिन मुझे बताइए कि प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स के बगैर, भारत में हेल्थ के बारे में एक भी स्कीम को सक्सेफुल तरीके से नहीं चला सकते हैं, क्योंकि भारत में आज जो भी डाक्टर्स हैं, उनमें से 80 प्रतिशत डाक्टर्स प्राइवेट हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। देश में जो भी हेल्थ सर्विसेस प्रोवाइड होती हैं, वे केवल 20 प्रतिशत ही सरकारी क्षेत्र में दी जाती हैं, बाकी प्राइवेट क्षेत्र में दी जाती हैं। इस प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि हम जो काम 70 साल में नहीं कर सके, वह एक ही साल में नहीं हो पाएगा, इसलिए प्राइवेट डाक्टर्स की हैल्प लेना बहुत ही जरूरी है।

महोदय, श्री जयराम रमेश जी ने यह भी कहा था कि out of pocket expenses का क्या होगा और वे काफी ज्यादा होते हैं? मैं भी उनसे सहमत हूं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि out of pocket expenses दवाओं और investigations पर ज्यादा होता है। Out of pocket expenses जो दवाओं पर खर्चा होता है, उसके लिए सरकार की तरफ से जन-औषधि योजना बाजार में लाई गई है। उससे आज 70 से 80 प्रतिशत दवाओं की कीमत कम हो गई है और मुझे लगता है कि उससे out of pocket expenses कम हो जाएंगे। वैसे ही इन्वेस्टिगेशंस तभी ज्यादा होते हैं, जब मरीज भर्ती होता है। इसके लिए जो भी टॉप अप या खर्चा लगता है, वह स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और एक अच्छी बात जो है, मुझे लगता है कि हम इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। वह यह है कि हमें पता है कि भारतवर्ष में सभी डॉक्टर्स माने जाते हैं, world over माने जाते हैं और बाहर के देशों से भी बहुत सारे लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारतवर्ष में आते हैं। वैसे ही नर्सेज़ की बहुत डिमांड है। ...(**समय की घंटी**)... बाहर के देशों में भी भारतीय नर्सेज़ की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अभी जब इतनी बड़ी स्कीम 'आयुष्मान भारत' आयेगी, 'नमो केयर' आयेगी, तो काफी मात्रा में पैरा मेडिकल्स लगेंगे। हम स्किल सेंटर्स के जरिए ये पैरा मेडिकल्स भी बहुत अच्छे से तैयार कर पायेंगे। यह बहुत जरूरी है कि हमारे जो 10वीं-12वीं पास लड़के हैं, youths हैं, उनको हम इसमें समाविष्ट कर लेंगे और इसमें उनको जॉब्स की अपॉर्च्युनिटी है। मुझे लगता है कि हेल्थ केयर में इनके जरिए सब लोगों तक, 50 करोड़ लोगों तक पहुँचने के लिए, एक जो जॉब का प्रश्न है, यह उसे अपने आप ही हल करने वाली स्कीम होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि हम इसे जान लें।

काफी बार यह कहा जाता है कि यह जो बात है, यह भी एक जुमला है, क्योंकि इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। ...(**व्यवधान**)... लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके पहले कांग्रेस का भी एक नारा था– 'गरीबी हटाओ'। क्या वह जुमला नहीं था? क्या आज तक गरीबी हटाई गयी है? उन्होंने इलेक्शन के वक्त उस जुमले का कई बार उपयोग भी किया है। मुझे लगता है कि इसे जुमला नहीं कहा जाए, क्योंकि यह जो 'नमो केयर' है, यह भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यह भारतवासियों के लिए अच्छा रहेगा और गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। ...(**समय की घंटी**)... वैसे ही जब हम गांव की मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना चाहिए और पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा आवंटन किया गया है। जैसे इसके पहले भी अटल जी की सरकार में 'प्रधान मंत्री

[डा. विकास महात्मे]

ग्रामीण सड़क योजना' से काफी लाभ हुआ था, वैसे ही माननीय नितिन गडकरी जी के जरिए गांव को शहर से जोड़ने का काम बहुत अच्छे ढंग से हो पायेगा। मैं सभी को यह बताना चाहूंगा कि नितिन गडकरी के यहां उन्होंने एक पोस्टर लगाया है, जिसमें यह लिखा है कि ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): श्री महात्मे जी, समाप्त कीजिए।

DR. VIKAS MAHATME: "American roads are good not because America is rich. But America is rich because American roads are good." So, we need good roads in villages also. इसके जरिए जो भी अनाज है, उसे मार्केट तक पहुँचाने के लिए यहां रोड्स बहुत जरूरी हैं और यहां के रोड्स की वजह से रोजगार भी उपलब्ध हो सकता है। मुझे यह लगता है कि असंगठित क्षेत्र में रोड्स के लिए लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वैसे ही बहुत जरूरी है कि आईटी सेक्टर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। ...(**समय की घंटी**)... मुझे यदि एक किलो चावल फ्लिपकार्ट या एमेज़ॉन के जरिए ऑनलाइन परचेज़ करना है, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि वह कितने दिन में कहां आयेगा, कितने बजे मेरे घर पहुँचेगा, यह सब मुझे पता चलता है और कौन से गोडाउन से निकलेगा, कौन सी गाड़ी से आयेगा, यह भी मैं ऑनलाइन देख सकता हूं। लेकिन आज यदि किसान को अपना अनाज बेचना है, तो उसके लिए यह बहुत मुश्किल है कि मार्केट कहां है, वहां तक वह कैसे पहुँचाए और कहां वह गोदाम में रखे। तो यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम जो रोबस्ट आईटी फ्रेमवर्क उनको दे रहे हैं, हम साथ में सॉफ्टवेयर्स भी देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब मार्केट में कठिनाई नहीं होगी और हम जो उनकी आय दोगुनी करना चाहते हैं, उसके लिए यह बहुत बड़ा कदम है। ...(**समय की घंटी**)...

मुझे पता है कि समय की बहुत कमी है। काफी मुद्दे हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जो बजट है, यह सभी भारतवासियों का हौसला बढ़ाने वाला है। हम नये भारत, नयी दिशा के लिए जा रहे हैं और हम एक नये भारत का निर्माण करेंगे, ऐसा विश्वास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री राज बब्बर (उत्तराखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर होने वाली महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का समय दिया। सारे सदन की भावना सुनने के बाद, मुझे लगा कि हमारे विद्वान साथियों ने लगभग सभी बिन्दुओं को सदन में रख दिया है। इसलिए मैं अपनी बात को सिर्फ दो ही विषयों तक सीमित रखूंगा और बहुत ज्यादा गम्भीर बातें करने की बजाए सिर्फ हल्की-सी बात ही करूंगा।

बजट में आई गिनतियों पर यहां काफी चर्चा हुई और गिनतियां बताई गईं। मैं गिनतियों से ही आरम्भ करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह बजट आम जनता के साथ एक खूबसूरत छलावा है। यह बजट देश के अरबों देशवासियों के लिए नहीं है, बल्कि अरबपतियों के लिए है। इससे देश के जनमानस को आंकड़ों के हेरफेर में उलझाया जा रहा है। इस बिन्दु पर चर्चा करने से पहले, मैं कहना चाहता हूं कि – '*सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम*'। चाणक्य ने कहा है कि सत्य से भागने से कुछ नहीं होगा। सत्य ही पृथ्वी को संतुलित रखता है।

महोदय, 2014 में चुनाव से पहले आंकड़ों और data की भाषा नहीं बोली जाती थी। आपने 450

से ज्यादा मीटिंग्स की होंगी और जो शब्द बार-बार बोले जाते थे, वे थे – jobs, बेरोज़गारी, यूथ, हर साल 2 करोड़ बेरोज़गारों को नौकरियां, किसानों की बदहाली, सेना के जवानों की शहादत का बदला, काला धन, हर नागरिक के account में 15 लाख रुपए आदि-आदि।

महोदय, इस बजट में चार बार गिनने के बाद, समझ में आया कि कुल 18,000 शब्द हैं और इन 18,000 शब्दों में job शब्द सिर्फ 6 बार आया है। इससे आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए कितना संजीदा मौजूदा बजट है। मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, हमारे सभी साथियों ने, सभी विद्वानों ने इन्हें समझाने की कोशिश की है – अगर समझ में आ जाए तो। एक यूथ शब्द है, जिसे इन्होंने लाइन में लगा दिया। यूथ शब्द पूरे बजट में सिर्फ तीन बार आया है। रोज़गार के अवसरों के लिए कोई नया विचार नहीं है, सिर्फ स्टार्टअप्स, स्टैंडअप्स हैं – जिनकी सफलता संदिग्ध है। आप 55 सालों की कांग्रेस की सरकार की स्थिति की बात करना छोड़ दें, सिर्फ उनकी चर्चा करें, जो वायदे आपने जनता से किए थे। आपने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी। डिटेल आपको बता दी गई है। अब EPF का data गिनाया जा रहा है। जान-बूझकर उलझाए हुए आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। अपनी ही सरकार की लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़े आप देख लीजिए, जो चिल्ला-चिल्लाकर कहते हैं कि पिछले चार सालों में जहां 8 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थीं, वहां मात्र 4-5 लाख नौकरियां मिली हैं। हालात सुधर सकें, इसके लिए बजट में कोई नई योजना नहीं है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री तिरुची शिवा)** *पीठासीन हुए*]

आदमी को जीवनयापन करने के लिए, जिन्दा रहने के लिए, खाने के लिए data नहीं आटा चाहिए। बेरोज़गार नौजवान, जिसकी परिभाषा हमारे एक आदरणीय साथी ने दी है, jobs का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देश के बेरोज़गार नौजवान को regular रोज़गार चाहिए लेकिन यहां से regular भाषण मिलता है। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, दुर्भाग्य है कि इस देश के नौजवानों को नफरत की अफीम पिलाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस हकीकत से ये वाकिफ न हों। ये अच्छी तरह, भली-भांति परिचित हैं और जानते हैं, लेकिन अपनी असफलता, गवर्नेंस की चुनौतियों से भागते हुए नौकरी नहीं दे पाने की वजह से, ये उसकी भरपाई करते हैं और नौजवानों के हाथ में डंडे देते हैं। कल हमारे साथी ने बोला कि बांस फाइबर में आता है। इनके लिए वह फाइबर में नहीं आता है, डंडों के लिए आता है, इसलिए उसमें छूट देकर उसे घास में लाने का काम किया है। आपकी बातों में आकर युवा आज की तारीख में न तो समाज के काम आ रहा है और न ही अपने परिवार के काम आ रहा है। वह सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो चुका है। यूपी के कासगंज के चंदन की मौत की वजह ही यही है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस दिन झण्डारोहण हो और झण्डा फहराने की बहस के अंदर नौजवान की जान चली जाए, इसके सवालों के जवाब इनको देना होगा। इसका कारण यह है कि नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वह एक आक्रोश में निकला हुआ है। महोदय, नौजवानों के बारे में बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में कह दिया गया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा।

महोदय, अब रहा किसान, तो किसान को भी इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्ष 2014 में इनका घोषणा पत्र निकला था, जिसके पन्ना नम्बर-44

[श्री राज बब्बर]
के ऊपर इन्होंने उस वक्त किसान की लागत का डेढ़ गुना देने का वादा किया था। चार साल बीत जाने के बाद, अब इनको किसानों की याद आई है। वह भी न आती, लेकिन गुजरात का चुनाव और राजस्थान के उप-चुनाव के अंदर जब किसान की नाराजगी खुल कर वोटों के रूप में सामने आई, तब बात इनकी समझ में आई। यही वजह है कि इन्होंने इस बार अपने बजट में फार्मर का नाम, किसान का नाम 30 बार किया है। शायद यही वजह हो सकती है कि 18,000 शब्दों वाले बजट में इन्होंने 30 बार किसान का नाम लिया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत): पिछली बार रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ...(**व्यवधान**)...

श्री राज बब्बर: आप पढ़ लेते, तो शायद समझ में आ जाता कि तब भी कुछ नहीं दिया और आज भी कुछ नहीं दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... किसान भोला जरूर है ...(**व्यवधान**)... हमने बहुत समझाया ...(**व्यवधान**)... किसान भोला जरूर है, लेकिन...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Raj Babbarji, please conclude.

श्री राज बब्बर: सर, अगर आप कहेंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन, मुझे केवल दो प्वाइंट कहने हैं, मैं उनको कहूंगा और बैठ जाऊंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने खुद ही अपना सब कुछ कम कर दिया है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... मगर, किसान से समझदार कोई दूसरी कौम हमारे देश में नहीं है। उसे बताने की जरूरत नहीं है, वह समझ गया है कि यह आंकड़ों की बाजीगरी है और बहुत सारे साथी उनके यहां भी समझते हैं कि जब वे अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि आखिर ये आंकड़ों की बाजीगरी का मुकाबला कैसे करेंगे? अगर ईमानदारी होती, तो बजट में किसान की लागत को तय करने का जो फॉर्मूला है, उसमें ये बदलाव नहीं करते। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। लागत में बीज, खाद, फैमिली लेबर को तो शामिल रखा है, लेकिन...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Raj Babbarji, four more Members have to speak. Kindly make it fast.

श्री राज बब्बर: लेकिन, जमीन के रेंट के बारे में कोई बात नहीं की है। जमीन का रेंट नहीं है। क्या किसान बिना खेत के खेती करेगा? किसान के पास अगर जमीन नहीं होगी, तो वह खेती किसमें करेगा? इन लोगों ने फैमिली लेबर को तो include किया है, लेकिन किसान को झांसा देना, वह आपकी फसल बीमा योजना में पहले ही बहुत झांसे खा चुका है। उस बेचारे को इतना झांसा मिला कि उसकी रकम, उसके पैसे उसके एकाउंट में से अपने आप फसल बीमा के लिए कटते गए, लेकिन उसको वह नहीं मिला। ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude.

श्री राज बब्बर: मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां से 73 सांसद आते हैं और मुझे खुशी होगी कि उन सांसदों के बीच मैं एक बार तीन सवाल करना चाहता हूं। उनकी जानिब से कि इस सरकार ने अपना ही वादा पूरा करने में चार साल क्यों लगाए हैं, क्या वह इसका जवाब किसान को देगी? उन चार सालों में आपका दिया हुआ वादा लागू करने की वजह से किसान को जो

नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई उसको मिलेगी? तीसरा, इन चार सालों में कम से कम, जो लोगों का अनुमान है और जो साथियों ने बताया है कि अगर उनको लागू कर दिया गया होता, तो किसानों की जेब में 1 लाख करोड़ रुपये जाते।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude, Raj Babbarji.

श्री राज बब्बरः इन बातों का जवाब अपनी बजट स्पीच में देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। महोदय, वैसे तो जुमलेबाजी की जुगलबंदी है यहां। प्रधान मंत्री कोई जुमला कसते हैं, अध्यक्ष महोदय बताते हैं कि वह 15 लाख वाली बात जुमला था। अभी यहां आए तो प्रधान मंत्री जी इम्प्लीमेंटेशन जी.एस.टी. के लिए कुछ फाल्टी बता रहे हैं और यहां अध्यक्ष जी आकर कह रहे हैं कि लाज़वाब जी.एस.टी. है, कमाल की जी.एस.टी. है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Kindly conclude please.

श्री राज बब्बरः सब कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं भी कहता हूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन यह तो ये लोग भी मानेंगे कि अटल जी से बेहतर नहीं बोलते। अगर मैं गलत कह रहा हूं और अगर आपको लगता है कि अटल जी से बेहतर बोलते हैं तो बता दीजिए, मुझे टोक दीजिएगा। मैं यह मानता हूं कि अटल जी से बेहतर नहीं बोलते।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): There are four more speakers from your party. Please conclude.

श्री राज बब्बरः अटल जी की सरकार 2004 के अंदर थी। फिर यूपीए की सरकार आई और इसलिए इस बार इस बात को ध्यान रख लें कि बोलने से सरकारें नहीं बनतीं और चलने से पहले एक बार कह देता हूं,

"कैसी मशाल लेके चली तीरगी में आप,
जो रोशनी थी, वो भी सलामत न रही।"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you very much. Now, Shri V. Vijayasai Reddy. I hope you will stick to the time limit.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of my party, YSR Congress Party, and my Party President, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, I thank you for having given me the opportunity. Sir, there is a great amount of injustice that has been meted out to the State of Andhra Pradesh in this Budget and also in the commitments that had been made in the Reorganisation Act. The first and the foremost thing is the Special Category Status which had been assured by none other than the then Prime Minister of this country, in 2014. Sir, I would like to bring to your notice that the Special Category Status for the Residuary State of Andhra Pradesh is a lifeline and there cannot be any substitute for the Special Category Status. A special package is no alternative for Special Category Status. Therefore, unless and until Special Category Status is granted to the Residuary State of

[Shri V. Vijayasai Reddy]

Andhra Pradesh, it can't develop equally with the other States. It has already been left as agrarian State, and, in future also it will continue to be an agrarian State, if Special Category Status is not granted.

Sir, the next point is railway zone. There, the Railway Minister, yesterday or day-before-yesterday came to the floor, and, then, misled the House. I have no hesitation in saying that the Railway Minister has misled the House. The Act does not contemplate consultation with the other parties. The Act has, specifically, provided that a railway zone would be created/constituted. When the Act is so specific, why is the Government delaying constitution of a separate railway zone? Now, the Railway Minister says that he has to consult the other States and he has also to consult the other stakeholders. Why is it? So, that is one of the provisions that has been incorporated and that has to be implemented. The Integrated Steel Plant at Kadappa, a port at Dugarajapatnam, Vizag Petrochemical Complex, Vizag Chennai Industrial Corridor and Metro Rail at Visakhapatnam and Vijayawada — these are all important issues. Apart from this, in Schedule XIII, there is a list of 11 Central institutions, out of which 9 have been established only in temporary premises and adequate allocations in the last four Budgets have not been made. Therefore, I request the Government of India to address this issue. ...(*Time-bell rings*)... Sir, how many minutes left now?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You have two more minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I will address only two important issues. First is farmers' distress. Sir, agriculture accounts for 16 per cent of India's GDP, and 49 per cent of India's employment comes from the agricultural activities. Sir, the National Sample Survey, 2013 Report shows that 51.9 per cent of the farm households in India are indebted. So, this indebtedness by the farmers is to be addressed by the Government of India. Insofar as Minimum Support Price is concerned, many Members have spoken about that. I will only say one thing. The Finance Minister while presenting the Budget of 2017 had categorically stated that he will ensure that the farmers' income would be doubled in next five years by 2022. Therefore, if at all this is addressed and this can be accomplished, the farmers across the country would be delighted and they will remember the Ruling Party – whichever Party does it – forever.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: One more minute. Sir, I am not touching upon the Minimum Support Price. It is only the cost of production. What is the cost? Even the Finance Minister, when he stated in his Budget Speech that he is increasing the

Minimum Support Price by 150 per cent of the cost, has not defined what is that cost. I want to know whether it is A2 or A2+FL or C2. What is that? That has to be spelt out by the hon. Finance Minister. Sir, there are last two issues which are very important issues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): How many last issues?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Two issues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, one is about the farmer producer companies. To the best of my knowledge, any income from agriculture is exempted from the tax under Section 2, Sub-section (1) of the Income Tax Act. It is undoubtedly a happy thing that the Finance Minister has pointed out that a number of farmer producer companies have been set up in India and these companies are basically set up by the group of farmers. Now whether they constitute partnership firm or company or they do it individually, it doesn't make any difference. Agricultural income is an agricultural income which is exempted from tax. ...(*Time-bell rings*)... Sir, the Finance Minister has exempted this income by these farming companies with a rider, with a sunset clause in the proposal. Why is this sunset clause? The sunset clause says that the income of the farmer producer companies is exempted only for a period of five years. Why five years? When agricultural income is totally exempted from the tax, why five years' tax holiday with a sunset clause? Therefore, I hope the Finance Minister will positively consider exempting it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: One more point, Sir. Secondly, even these farmer companies have to pay dividend distribution tax which is totally unreasonable and unwarranted for India's condition.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Yes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: One last point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): How many last points? ...(*Interruptions*)... Please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: This is very important. Sir, the CAG Report, the Comptroller and Auditor General Report, on Government accounting found that the Government has deferred the payments amounting to more than ₹ 1.87 lakh crores in 2015-16. I request the hon. Finance Minister to address this issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you Mr. Vijayasai Reddy. Now Prof. Rajeev Gowda.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir.

Sir, I want to actually start my speech on the Budget by congratulating the Government and the Finance Minister on funding Suburban Rail Service for Bangalore City. This is something that the Karnataka Government has been very proactive about. As an activist, I have been fighting for this for many years. Across party lines, we are in unity in terms of support for the suburban rail. It will go a long way in clearing the traffic challenges that Bangalore city faces. ...(*Interruptions*)...

I also want to congratulate the Government for adopting many of the innovative programmes set up by the Government of Karnataka under Shri Siddaramaiah. In this Budget announcement, there were multiple such examples. For example, the Electronic National Agricultural Market place is a national application of our Rashtriya e-market place. The Programme to lend and rent out farmer equipment is the national equivalent of the Krishi Yantra Yojana of Karnataka Government. The solar pumps initiative is a replica of the Surya Raitha programme of the Karnataka Government, and the programme for pregnant and lactating women is a national application of the very successful and impactful Mathru Purna Scheme, which would go a long way in addressing the health of women and children and in addressing issues of low birth rate, and bring down infant mortality, maternal mortality, stunting, etc.

Sir, after complimenting the Government, let me now focus on points where I need to show the Budget and this Government are falling short of our expectations of any good Government. First of all, there is an extraordinarily excessive reliance on cesses. The real problem with this is, a cess is supposed to be earmarked for a particular purpose, but already we have seen, in recent times, that the Coal Cess that was supposed to go to the National Clean Energy Fund instead is being used to compensate States for GST losses. What is the logic for that and how can you say that this is a cess that was targeted for a particular reason when you are directing it somewhere else? The problem with cesses is that like indirect taxes they are regressive, and they hurt the poor more than they hurt the rich.

Sir, the total cess collection from this Government is expected to be three lakh crore rupees. Compare that with the capital expenditure for the financial year, 2018-19, which is also three lakh crore rupees. It appears as if this Government is not going to raise revenues other than through such iniquitous methods such as cesses. This brings me to the education cess. Here again, there is going to be uncertainty on how much is actually going to be raised further, in States, you find that cesses

are being allocated for funding programmes which absolutely need targeted revenue allocated to them.

Sir, I am also outraged by one move of this Finance Minister, where he has played a game, a sleight of hand, on the front of petrol and diesel excise duties. When the Centre collects Excise Duty on petrol and diesel, it becomes part of the divisible pool and 42 per cent goes to States. What has this Government done? It has cut Excise Duty by six rupees per litre with an additional two rupees per litre—cut on excise on diesel and petrol, and to balance this cut and to ensure that the Centre's revenues do not come down, they have imposed an eight rupees per litre Road and Infrastructure Cess. As I mentioned, the cess monies will go only to the Central Government and the States are shafted. Now, how much is this loss? I did a little quick calculation. If you look at the receipt budget... ...(*Time-bell rings*)...

Sir, this is important stuff. This is for your State and mine and every one else. Our money is being taken away. Let us pay attention.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Okay.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA: So, basically, if they are aiming to raise ₹ 1.13 lakh crore in this year from this item, well, at eight rupees per litre it is about 14,125 crore litres. 42 per cent of the two rupees per litre would be 84 paise. If you multiply that, States together lose ₹ 11,885 crore. For what – just so that the Centre can take away money that should have come to each of our States. This is outrageous and I demand that the Finance Minister makes a change in this provision before the Budget or the Finance and Appropriation Bills are actually passed.

Sir, like Mr. Vijayasai Reddy, I have two-three last points to make. So, give me two-three minutes more.

Sir, education is my pet subject. That is my old profession. This Budget has seen the lowest allocation to education as a proportion of the total Budget in the last eight years. That is shameful. UPA had an average of 4.5 per cent of the Budget and NDA is averaging only 3.6 per cent. What are they trying to do to the people of India? They promised in their manifesto six per cent of GDP on education. Instead we see 3.4 per cent of GDP allocated this year. And, this also means that there is another cess there. They have pooled the education and health cess together and there is no clarity on how much would go to health and how much would go to education. We don't know that. There are other programmes – one lakh crore rupees allocated for Revitalizing Infrastructure and Systems in Education and there again, there is no roadmap on how it is going to be expended.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA: No, Sir. There are two or three more urgent issues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You already said you have two or three more issues when I last told you.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA: Sir, if you are a little patient, you would find that this is most important.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): We are patient, but please conclude.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA: Sir, you know when the ship is sinking, the slogan is "Women and children first". When this Government's ship is sinking, they go after the programmes and funding for women and children first. Okay. That is a shame. What have they done? For children, the allocations were 4.6 per cent of the Budget in 2012-13 and it has now come down to 3.23 per cent. ...(*Interruptions*)...

SHRI AMAR SHANKAR SABLE (Maharashtra): Time is over. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): Who are you? ...(*Interruptions*)... You are not the Vice-Chairman. ...(*Interruptions*)...

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA: Sir, they should learn from Karnataka Government which has a rock solid Karnataka State Child Protection Policy. ...(*Interruptions*)... Sir, Budgetary allocation for the National Commission for Protection of Child Rights has come down; it is 30 per cent lower than the Revised Budget Estimates for FY 2017-18. ...(*Interruptions*)... Sir, Economic Survey had a pink cover. That is it. There is nothing in the Budget to match the symbolism of the cover of the Economic Survey and the Government's commitment to women. Sir, allocateions to the maternity benefit scheme has come down by ₹ 300 crore; allocateions to the National Commission for Women has seen a decline; their Nirbhaya Funds Scheme has come down and girls' education has seen 20 per cent reduction. सर, "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" क्या है? Why 20 per cent reduction for that? Finally I come to disabled people. I know your own concerns for people who are minorities of various kinds and the disabled is generally rejected. And here, you will see that the increase in Budgetary support is inadequate and there is a variety of failed promises in terms of escalators in the Railways, etc. Sir, I just want to end now. ...(*Interruptions*)...

SHRI AMAR SHANKAR SABLE: Time is over. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: What is this? ...(*Interruptions*)... Who is he? ...(*Interruptions*)...

SHRI AMAR SHANKAR SABLE: Who are you? ...(*Interruptions*)... I am speaking to the Chair. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please sit down. ...(*Interruptions*)... I will take care. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA: Sir, I want to conclude. ...(*Interruptions*)... May I conclude? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): By this time, you would have concluded. ...(*Interruptions*)... By this time, you would have concluded. ...(*Interruptions*)... Don't waste the time. ...(*Interruptions*)..., Please sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री नीरज शेखरः बीजेपी के लोगो, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। वे इस सदन की सब से वरिष्ठतम महिला हैं।

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA: I want to point out one thing. In the other House the Prime Minister quoted Basavanna, our great social reformer from Karnataka. Sir, in one of his famous Vachanas, Basavanna says:

kalabeda kolabeda

husiya nudiyalu beda

'Husiya nudiyalu beda' means 'do not utter falsehoods'. Sir, this Government's promises during their election campaigns, their actual practice during the Budget, their statement outside and their statement inside, are all falsehoods. They will come face to face with the truth in the coming elections starting from Karnataka. ...(*Interruptions*)... Sir, we will show them. ...(*Interruptions*)... Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Rajeev Gowdaji; now, Shri Joy Abraham; not present. Dr. Sushil Gupta; this is your maiden speech. You will be given fifteen minutes. Kindly conclude within time.

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)ः आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय और सदन में उपस्थित सभासदो, मैं इस सदन में पहली बार बोल रहा हूं और संसदीय जीवन के हिसाब से मेरी सब से कम उम्र है, इसलिए मैं कुछ गलत कह जाऊं, तो आप सब मुझे excuse करें।

महोदय, मैं मानता हूं, मुझे मालूम नहीं कि मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर और गुरुद्वारे में परमात्मा, अल्लाह, वाहे गुरु हैं या नहीं, परंतु मुझे मालूम है कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, उन के अंदर परमात्मा का अंश है। अब अगर वह अंश निकल जाए तो मानव का शरीर

[श्री सुशील कुमार गुप्ता]

6.00 P.M.

biological degradable body बनकर रह जाता है, जिसे हम घर के अंदर दो घंटे से अधिक नहीं रख सकते। इसलिए इंसान का शरीर चलता-फिरता मंदिर है और इस मंदिर की सेवा जिस तरीके से हो सकती है, उस में सब से पहले health sector आता है।

मैं सब से पहले health के विषय पर बात करूंगा। भारत सरकार का health के ऊपर टोटल बजट का 2.24 परसेंट बैठता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल ने health के ऊपर बजट का 12 परसेंट लगाया है ताकि हम मानव जीवन को सब से अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकें, मानव जीवन की सब से better care कर सकें। महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि भारत सरकार 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी ला रही है परन्तु उस बीमा पॉलिसी के लिए हेल्थ केयर सेन्टर्स कहां हैं? दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक खोले, लेकिन वह केवल 158 मोहल्ला क्लिनिक ही खोल पाई, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने permission न देकर, उसको अटका दिया। मैं यूएनओ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने मोहल्ला क्लिनिक योजना को एप्रिशिएट किया। मैं आज वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वेलनेस सेन्टर के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक की नकल की और मोहल्ला सेन्टर के नाम से पूरे हिन्दुस्तान में मोहल्ला क्लिनिक खोलना तय किया। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो यह बीमा योजना ला रहे हैं, इसकी बजाय दिल्ली सरकार ने जो नियम अपनाया है कि गरीब रोगी, जो महीनों तक व सालों तक सरकारी हॉस्पिटलों में नम्बर न आने की वजह से अपना ऑपरेशन नहीं करा पाता, तो दिल्ली सरकार एक महीने के बाद उनके ऑपरेशन के पैसे स्वयं देती है। भारत सरकार भी ऐसे गरीब रोगियों के इलाज के लिए स्वयं पैसे दे और उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाए। यानी बीमा कम्पनियों को पैसा देने के बजाय गरीब व्यक्ति का सीधा इलाज हो और वह प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाए। मैं कहना चाहता हूं कि अरविन्द केजरीवाल जी ने जो हार्ट केयर सिस्टम दिल्ली के अंदर चलाया है, उसके तहत मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 100 से अधिक किस्म की दवाइयां, दो सौ से अधिक किस्म के टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। मैं आप से भी निवेदन करता हूं कि जो आप वेलनेस सेन्टर्स बना रहे हैं, उनके अंदर भी इसी प्रकार की योजनाएं लाएं, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति अपने घर के नजदीक, जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स आपको बनाने चाहिए थे, उनको नहीं बनाया तो, उनके अंदर जाकर अपना इलाज करा सके।

मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि देश की आजादी को 70 वर्ष हो चुके हैं। हिन्दुस्तान के संविधान को लागू हुए 68 वर्ष हो सकते हैं, हमारे संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा है कि हिन्दुस्तान संप्रभुता सम्पन्न देश, जिसमें पंथनिरपेक्ष समाज को धार्मिक समानता होगी। मैं कहता हूं कि आज भी देश की महिलाओं को साढ़े छः बजे के बाद घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि घर से निकलूं या न निकलूं, तो इस देश की सरकार ने कैसी समानता दी है? आज भी सदन के अंदर और सदन के बाहर महिलाओं का उपहास किया जाता है, तो फिर कैसी समानता देश के संविधान निर्माताओं ने दी है? मैं कहना चाहता हूं कि आज भी देश के बॉर्डर पर सैनिक मरता है, हम चुनाव के समय कहते हैं कि हम एक के बदले दस सिर लेकर आएंगे, जबकि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत होती है, हमने उनकी रक्षा के लिए क्या कुछ किया है? क्या हमने उनके लिए कोई ठोस नीति बनाई है? मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका

एक सुगम तरीका है कि आप हिन्दुस्तान को शिक्षित करें और शिक्षा के ऊपर अधिक से अधिक बजट लगाएं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान सरकार का जो शिक्षा के ऊपर बजट है, उसमें वह 2013-14 में साढ़े चार प्रतिशत था, जो 2016-17 में घटकर 3.65 प्रतिशत रह गया। 2017-18 में यह 3.71 परसेंट हो गया और इस बजट में आपने साढ़े तीन परसेंट का प्रोविज़न रखा है। इसके विपरीत दिल्ली सरकार ने अपना बजट 24 परसेंट शिक्षा के ऊपर रखा है।

मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा और चिकित्सा एक ऐसा माध्यम है, जो हिन्दुस्तान के सौ परसेंट लोगों के काम आता है। हिन्दुस्तान का बजट ऐसा नहीं बनना चाहिए कि पांच या दस परसेंट चन्द अमीर लोग उसके ऊपर निर्भर होकर देश की सारी सम्पत्ति को खा जाएं। आज 68 वर्ष बाद भी कैसी समानता सरकारें दे रही हैं? 2016-17 के अंदर देश का 53 परसेंट पैसा कुल मिलाकर एक प्रतिशत से कम लोगों के पास था, लेकिन जो 2017- 2018 के अंदर बढ़कर 73 परसेंट पैसा एक परसेंट लोगों के पास चला गया। आप लोग संविधान के दायरे में यह कैसी समानता लाना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे कोई भी आए, पार्टी चाहे कोई भी आए, परन्तु देशहित सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर आपको देशहित सबसे ऊपर लाना है, तो शिक्षा को ऊपर लाना पड़ेगा और हिन्दुस्तान को शिक्षित करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का शिक्षा के ऊपर साढ़े तीन परसेंट बजट है, आप उसको बढ़ाकर दिल्ली सरकार की तरह 24 परसेंट कीजिए। पूरे हिन्दुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की ये शिक्षित हिन्दुस्तान के नौजवान अपने आप तकदीर बदल देंगे और, हम अपने आप दुनिया के पहले नम्बर पर जाएंगे, फिर हिन्दुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी आप हिन्दुस्तान सरकार के राइट टू एजुकेशन एक्ट को देखिए, हर एक किलोमीटर के ऊपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और हर तीन किलोमीटर के ऊपर एक मिडिल स्कूल होना चाहिए। आज भी बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस किलोमीटर पर स्कूल नहीं है। क्या हम इस देश के अंदर ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं? अगर यह आर्थिक असमानता रही, शिक्षा का अभाव रहा, तो वह दिन दूर नहीं, जब इस देश के अंदर अपराध बढ़ेंगे, इस देश के अंदर गरीब लोग अमीर लोगों को लूटकर खाएंगे और यही कारण है कि असंतोष है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हज़ारों अमीर लोग, जो करोड़पति और अरबपति थे, वे हिन्दुस्तान छोड़कर जा रहे हैं। हिन्दुस्तान का पैसा – क्या सरकार ने कभी यह सोचा है कि ये लोग क्यों जा रहे हैं? हिन्दुस्तान का यह पैसा कहां जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है? क्या आपने कभी उसको रोकने का प्रयत्न किया? मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा के नाम पर आज भी सब कुछ ठीक नहीं है। अगर आप पड़ोसी राज्यों की बात करें, तो हरियाणा में 25-25 किलोमीटर दूर तक स्कूल और colleges नहीं हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दो साल के अंदर 25 हज़ार सरकारी स्कूल बंद किए हैं और 40 प्रतिशत बच्चे आज भी कुपोषण से ग्रस्त हैं। क्या इस हिन्दुस्तान को देखने के लिए इन शहीदों ने शहादतें दी थीं? क्या इस हिन्दुस्तान को देखने के लिए भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था कि हम हिन्दुस्तान के लोगों को बराबरी का यह दर्जा देंगे?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Gupta, because of the time constraint, hon. Chairman has instructed to restrict the time. Kindly take two more minutes.

श्री सुशील कुमार गुप्ताः उपसभाध्यक्ष जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, मैंने निवेदन किया है, मेरी मेडन स्पीच है। मैं पहली बार बोल रहा हूं। देश की कानून व्यवस्था को बनाने के लिए एक ऐसा स्तर होना चाहिए, जहां सब ठीक चले। दिल्ली की व्यवस्था को देखिए, यहां चुने हुए लोगों के हाथ में सत्ता न देकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के हिसाब से दिल्ली पुलिस चलाई जा रही है। दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ते हैं, दिल्ली के अंदर सरेआम कत्ल हो जाता है और दिल्ली पुलिस नागंवारा। अगर लेफ्टिनेंट महोदय के पास न विधायकों से, न मुख्य मंत्री से मिलने का समय होता है। अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था को चलाना है, तो चुनी हुई सरकार को अधिकार मिलने चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार इसको चलाएगी तो बेहतर रहेगा। मैं माननीय श्री अरविंद केजरीवाल को फिर भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे हर घर के अंदर जाकर बहुत कोशिश करते हैं। इस तरीके से नहीं – जिस प्रकार दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा लगा है – आपने थोड़े दिन पहले की कानून व्यवस्था देखी, आपने रामपाल जी का केस देखा, राम रहीम जी का केस देखा, एक आंदोलन देखा। इस आंदोलन के तहत लोगों की संपत्तियां जलीं। कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं था, सरकार अपना राज धर्म निभाने में इसको भूल गई, सरकार कानून व्यवस्था को एक उचित दायरे के अंदर लाना भूल गई। अभी मैंने पिछलें दिनों अखबारों में पढ़ा कि हरियाणा के अंदर 13 जिलों के अंदर लगातार रेप cases हुए। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और मुख्य मंत्री महोदय उस पर कुछ बोलने में लाचार थे। यदि आज मध्य प्रदेश की बात करें तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर 13 रेप cases प्रतिदिन होते हैं, जो हिन्दुस्तान का सबसे भयंकर गंदा रिकॉर्ड है, जो कि अनुचित रिकॉर्ड भी है। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार को कहीं न कहीं इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि देश की कानून व्यवस्था मजबूत बने, देश के लोगों को बेहतरीन तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मिले। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों से यह growth-oriented Budget नहीं है। हमेशा deficit के अंदर Budget जाता है।

महोदय, इस देश के अंदर नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब दिल्ली के अंदर सीलिंग। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इन व्यापारियों से क्या दुश्मनी है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग कहते हैं कि हमारे इधर मंदा है, व्यापार है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार और अखबार कहते हैं कि हिन्दुस्तान तरक्की कर रहा है। हिन्दुस्तान तो तरक्की कर ही रहा है, लेकिन देश का 73 प्रतिशत पैसा, इन सब लोगों की जेब से निकलकर 1 प्रतिशत से कम लोगों के पास चला गया है, चंद घरानों के पास चला गया। क्या हम हिन्दुस्तान को यह सामाजिक और आर्थिक समानता देना चाहते हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you very much, Guptaji.

श्री सुशील कुमार गुप्ताः मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को अपना सारा धन समेटकर अरबपतियों को देने की बजाय... जिस दिन आपने बजट पेश किया, उस दिन देश का जो इंडेक्स था, देश का जो शेयर बाजार था, उसमें लोगों के अरबों रुपये, करोड़ों रुपये तबाह हो गए, क्योंकि देश के मध्यमवर्गीय लोगों ने जिंदगी भर पैसा कमाकर अपनी कैपिटल शेयर बाजार में लगाई थी। आपने एक राहत कही कि हम इसके ऊपर लांग टर्म कैपिटल गेन्स लगाएंगे और शेयर बाजार धड़ाधड़ गिरता चला गया। आपने इस सदन के अंदर कहा कि हम एक्साइज़ ड्यूटी घटाकर, देश के अंदर न्यूनतम पेट्रोल की कीमत घटाएंगे, लेकिन उसी दिन, उसी रात में बाजार

के अंदर पेट्रोल महंगा हो गया, आपने उसका बाजार भाव बढ़ा दिया। हम देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, आप एक ऐसी योजना लेकर आएं, जिससे देश का व्यापारी शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, एक अतिरिक्त टैक्स के माध्यम से अपने आपको इस देश के अंदर सुरक्षित महसूस करे। उसका व्यापार बढ़े और दिल्ली में सीलिंग से मुक्ति मिले। व्यापारियों के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो नौकरी पेशा हैं, हमारे जो सर्विस क्लास के लोग हैं, उनके लिए आपने 2014-15 से टैक्स फ्री इनकम ढाई लाख रुपए रखी है। जब आप विपक्ष में रहकर प्रतिपक्ष के नेता थे, इसी सदन में आपने कहा था कि टैक्स फ्री इनकम पांच लाख रुपए होनी चाहिए और आपने यही बात अपने अमृतसर के चुनाव के दौरान भी कही थी। महोदय, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस देश के सर्विस क्लास लोगों के लिए आप इस टैक्स फ्री इनकम की सीमा को बढ़ाइए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): One moment, please. I do not want to interrupt your maiden speech but considering the situation and time constraint, please take one more minute and conclude.

श्री सुशील कुमार गुप्ताः ठीक है, महोदय। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने 40,000/-रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दी, लेकिन उसके विपरीत आपने घुमाकर उसे वापस भी ले लिया, क्योंकि आपने मेडिकल, ट्रांसपोर्ट चार्जेज की डिडक्शन की छूट वापस ले ली और साथ ही 4 परसेंट का सेस भी लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि इस 40,000/-रुपए की छूट को बढ़ा कर 75,000/- रुपए करें। माननीय महोदय के माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ढाई लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम को आप पांच लाख रुपए करें, ताकि देश के नौकरी पेशा लोग अपनी मेहनत की कमाई से यह फील कर सकें कि हम इस देश के अंदर आराम से रह रहे हैं।

महोदय, मैं रोजगार की बात करना चाहता हूं। हमें नए रोजगार के लिए साधन खोजने चाहिए। बजट के अंदर ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि देश का पढ़ा-लिखा नौजवान, युवा बेहतरीन नौकरी पा सके। आज जो यहां पर जुमला बना – पकौड़ा रोजगार योजना या और कोई योजना, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, मैं सीधे-सीधे सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसे संसाधन उत्पन्न करें, जिनसे देश के लोगों को रोजगार मिले। रोजगार न मिलने से युवक गुनाह के रास्ते पर चल पड़ते हैं और जब युवक गुनाह के रास्ते पर चलेंगे, तो उसका खामियाज़ा आज के पूरे हिन्दुस्तान को ही नहीं, आने वाली जेनरेशंस को भी भुगतना पड़ेगा और फिर उनको उस रास्ते से वापस लाना मुश्किल होगा। अंत में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस देश के किसान को यूरिया, खाद्यान्न के समर्थन मूल्य की बात करते हैं, बीमा फसल की बात करते हैं, लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं मिलता। आप उसको यथार्थ में लाइए, ताकि देश का किसान, जो हमारा अन्नदाता है, उसको हौसला मिले।

महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव के दौरान यह कहा गया था कि पाकिस्तान अगर हिन्दुस्तान के जवान का एक सिर काटेगा, तो उसके बदले में हम दस सिर काट कर लाएंगे। आज उसके विपरीत माहौल दिख रहा है। देश की सेना का मनोबल ऊंचा करने के लिए अगर कोई जवान शहीद होता है, तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपए मिलने चाहिए और बजट में यह प्रोविजन भी होना चाहिए कि उसके बच्चे को भी नौकरी मिलेगी, ताकि देश के जवान सीना चौड़ा करके अपनी ड्यूटी निभाएं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Kindly understand the situation and conclude in one minute. Please wind up.

श्री सुशील कुमार गुप्ताः महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के विकास की बात होती है और आए दिन धमकी दी जाती है, कभी दिल्ली का पानी पड़ोसी राज्य रोक देता है, दिल्ली के डीडीए में एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, जो बीस साल का मास्टर प्लान अंतिम साल में पूरा करती है और अंतिम साल के अंदर कहते हैं कि यह समय पूरा हो गया, नया मास्टर प्लान बनेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You are speaking well but there is no time. I have to call the next speaker.

श्री सुशील कुमार गुप्ताः महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर लाखों लोग मलिन बस्तियों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। देश की राजधानी का चेहरा हम क्या बनाना चाहते हैं? उनको पक्के मकान बना कर देने होंगे।...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Shrimati Viplove Thakur.

श्री सुशील कुमार गुप्ताः यह काम भारत सरकार करे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): It is enough.

श्री सुशील कुमार गुप्ताः महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि उनको आप चार मंजिले पक्के मकान बना कर दें। इससे आपको 75 परसेंट जमीन खाली मिलेगी। उसके बाद उनकी शिक्षा के, चिकित्सा के लिए काम हों।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You have conveyed enough. Thank you, Mr. Gupta. Please conclude.

श्री सुशील कुमार गुप्ताः महोदय, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे पास दिल्ली के विषय में, देश के विषय में बोलने के लिए काफी था, मैं माननीय वित्त मंत्री जी विनती करूंगा कि इन विषयों पर गौर करें, ताकि देश का भला हो सके, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you. Now, Shrimati Viplove Thakur.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः उपसभाध्यक्ष जी, जब देश का बजट आने वाला होता है, तो लोगों में बहुत उत्सुकता होती है। लोग बड़े ध्यान से और दिल लगा कर टीवी के सामने इसलिए बैठे होते हैं कि पता नहीं, हमें क्या मिलने वाला है, हमारी क्या भलाई होने वाली है, हमें क्या फायदा होने वाला है, हमें क्या उन्नति मिलने वाली है। यह जो बजट है, यह हर मोर्चे पर विफल रहा है, कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं है। न तो किसान खुश हैं, जिनके लिए इन्होंने इतना बड़ा कहा है - farmers, farmers, farmers. आज farmers भी खुश नहीं हैं, महिलाएं भी खुश नहीं हैं, बच्चे भी खुश नहीं हैं, व्यापारी भी खुश नहीं हैं, कोई भी वर्ग इस बजट से खुश नहीं है, क्योंकि इस बजट में है ही कुछ नहीं।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से एक बात जानना चाहती हूं

कि इन्होंने किसान की परिभाषा क्या रखी है? क्या किसान सिर्फ वही है, जो गेहूं, ज्वार, मक्की, धान बोता है या किसान वह भी है, जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रहता है, जो वहां पर सेब की फसल करता है, fruit की फसल करता है, उसे उगाता है? उसको जो नुकसान होता है, क्या उसकी भरपाई के लिए भी इन्होंने कुछ रखा है? कुछ नहीं रखा है। जितने hill areas हैं, उनके लिए स्पेशल बजट चाहिए, चाहे वह नॉर्थ-ईस्ट है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे जम्मू-कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है, क्योंकि अगर यहां पर एक सड़क बनानी है, तो अगर मैदानों में इसके लिए एक करोड़ लगता है, तो पहाड़ों में इसके लिए 5 करोड़ लगता है। लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश का जो सेब है, fruits हैं, सब्जियां हैं और जो वहां off season सब्जियां उगाई जाती हैं, उनके लिए भी किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इस बजट से कोई खुश नहीं है।

महिलाओं की तो बात ही क्या करनी है! ये बहुत महिला-महिला करते हैं, उसके सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने उसका बजट भी कम कर दिया है। महिला के हेड में 2,700 करोड़ से 2,400 करोड़ कर दिया गया है। कुपोषण के लिए जो बात होती है, तो 1.2 करोड़ बच्चे हैं, जिनके लिए 8 हजार करोड़ चाहिए, अगर हम उनको सेहत देना चाहते हैं। इसके लिए भी कहीं प्रावधान नहीं है।

बड़ी बातें की जाती हैं। अभी गुप्ता जी ने कहा, मैं भी पिछले पेपर्स देख रही थी, जब पाकिस्तान से कहा जाता था कि एक सिर आएगा, तो हम 10 सिर देंगे। आज यहां मेरी बहन स्मृति इरानी जी नहीं बैठी हुई हैं, इन्होंने कहा था कि चूड़ियां भेजी जाएंगी। स्मृति जी, अब तो आप इस कैबिनेट में हैं, भेजने की जरूरत भी नहीं है, इनको चूड़ियां पहना ही दीजिए, जो अभी इस तरह से काम कर रहे हैं। कहां हैं वे? मैं बात नहीं करना चाहती हूं। आज रोज हमारे यहां किसी न किसी शहर में हमारे फौजी के शव आते हैं, ताबूत में डले हुए आते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते।

जम्मू-कश्मीर के हालात देखिए। अभी मेरे भाई जम्मू-कश्मीर के लिए बोल रहे थे कि क्या हुआ, क्या किया, लेकिन मेरे भाई, 2000 से लेकर 2009 तक इतनी बुरी हालत नहीं थी, जो आज हो रही है। कहां हैं वे? कहां हैं वे बातें? क्या वे केवल जुमले ही थे? आज इतना कुछ दिया गया है, ये सिर्फ बातें हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं है।

हमारी कौन सी विदेश नीति है? हमारा कौन सा neighbour है, पड़ोसी देश है, जो हमसे खुश है? नेपाल था, हमने उसको भी गंवा दिया। श्रीलंका हमसे नाराज है, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बंगलादेश को देख लीजिए, चीन हमें डरा रहा है, पाकिस्तान रोज हमसे कहता है और हम विदेश घूम रहे हैं। खूब विदेश जा रहे हैं। कौन सी FDI आ गई है विदेश से, मुझे बताएं? जितना खर्च विदेशों में जाने में हुआ है, उसी से हम अपने देश का और भी भला कर सकते थे, उसको और भी उन्नत कर सकते थे। हमारी कोई नीति नहीं है।

मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। नड्डा जी यहां बैठे हैं, एक मिनट, हमारे यहां जो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, चाहे वह नाहन में है, चाहे हमीरपुर में है, चाहे मंडी में, जब MCI की टीम आती है, तो कहां से faculty के प्रोफेसर्स लाए जाते हैं? कभी इंदिरा मेडिकल कॉलेज से जाते हैं, कभी टांडा से जाते हैं। नड्डा जी, हमें ऐसे मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, जहां पर faculty के लिए प्रोफेसर्स ही न हों। आप कौन से बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जहां सुविधाएं ही नहीं हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Viplove*ji*.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बोल रही हूं और हमेशा मेरे साथ ऐसा किया जाता है। मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): One more minute, please.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः हर प्रदेश में insurance की सुविधा है। एक साल के लिए 5 लाख तक के लिए कहा गया है।

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इन्होंने कहा कि अगर बैंक में minimum पैसा नहीं होगा, बड़े-बड़े शहरों में यह सीमा 3 हजार है, कहीं एक हजार है, तो उसके ऊपर penalty लगेगी। वित्त मंत्री जी, penalty के ऊपर भी GST लगा दिया गया है। अगर penalty भी लेनी है, तो एक गरीब का क्या कसूर है कि वह बैंक में एक हजार रुपए भी नहीं रख सकता और उसकी penalty के ऊपर भी आपका GST है। महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना की बातें हो रही हैं। जो फ्लैट लेगा, उस पर भी वह जीएसटी देगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thakur ji, please conclude.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः आप मुझे बताइए कि यह कहां का न्याय है? इस तरह से सरकारें नहीं चलती हैं। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर हमने गलतियां की थीं, तो हमने भुगत लीं, अब आप भी भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे भी आपका यह बजट चार महीने का है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः आप इस फसल का इंतजार कर रहे हैं कि यह फसल आए और हम किसानों को पैसा दें, फिर अगली फसल के लिए कुछ नहीं हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः आप इलेक्शन जीत जाएं, यह होने वाला नहीं है। आप इस भुलावे में मत रहिएगा, क्योंकि आपको जाना ही होगा और आप जाएंगे। जनता आपसे नाराज़ है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mrs. Thakur. Please.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः आपने राजस्थान में देख लिया, गुजरात में देख लिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you very much, Mrs. Thakur. Now Mr. Ashok Siddharth. Strictly you have three minutes.

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश)**:** सर, मुझे पांच मिनट दीजिए। दलितों के साथ ही यह अन्याय क्यों हो रहा है?

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे केंद्रीय बजट पर बोलने का मौका प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। श्रीमन्, जैसे ही बजट सत्र आता है, वैसे ही देश के आम नागरिकों में चर्चा होने लगती है कि आने वाले बजट में उनके लिए क्या होगा? इसका कारण भारत में वित्त मंत्री के द्वारा

पढ़ा जाने वाला बजट भाषण है, जो देश के नाम एक संदेश होता है। इस संदेश से जनता को यह भी पता चलता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में आम जनता के प्रति सरकार की सोच क्या है?

महोदय, जहां तक वर्ष 2018-19 के बजट की बात है, भले ही सरकार की चाटुकारिता करने वाले आर्थिक विशेषज्ञ इस असंतुलित बजट को संतुलित बता रहे हों, लेकिन वास्तव में यह बजट गरीबों, मज़दूरों, छात्रों, नौजवानों, बेरोज़गारों के हित में नहीं है और खासकर दलितों और आदिवासियों के लिए इस बजट में कोई खास प्रावधान करने का काम नहीं किया गया है। किसानों से लेकर महिलाओं की स्थिति भी वैसी ही है। इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने सरकार को चेताने का काम किया है, इसलिए मैं उन बातों को दोबारा दोहरा कर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं। इस बजट में अपने अल्प समय में ही मैं अपनी बात रखूंगा। चूंकि मैं दलित समाज से ताल्लुक रखता हूं और एक साधारण से दलित परिवार में पैदा हुआ हूं, फिर भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, आदरणीया बहन जी की वजह से मुझे देश के इस सर्वोच्च सदन में आने का मौका मिला है। इस बजट में दलितों और आदिवासियों के उत्थान की बात कहीं भी दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसके संबंध में मैं सरकार से कुछ बातें जानना चाहता हूं। जब सरकार ने 2014-15 में अपना पहला आम बजट पेश किया था, तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने उस बजट में दलितों के लिए, SCs/STs के लिए 2.8% का प्रावधान रखा था, जो चार साल गुज़रने के बाद, आपके इस आखिरी बजट में घट करके 2.32% रह गया। क्या चार साल में दलितों की तरक्की हो गई या फिर उनकी आबादी कम हो गई? बजट प्रस्तुत होने के बाद से लेकर अब तक यह प्रश्न हमारे दिमाग में है, जो अभी तक अनुत्तरित है कि सरकार ने इस संबंध में क्या किया है?

मान्यवर, भोजन, पानी और ऑक्सीजन की तरह मानव जीवन के लिए गरिमा और सम्मान भी जरूरी होता है, लेकिन अगर हम इस बजट के पूरे प्रावधानों को देखें, तो कहीं भी दलितों के लिए सम्मान से जीने लायक व्यवस्था करने का काम नहीं किया गया है। ...(**समय की घंटी**)... सिर्फ दो बातें कह कर मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि आपने स्ट्रिक्ट्ली तीन मिनट के समय के लिए कहा है। चूंकि मैं एक अनुशासित पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए सिर्फ आधे मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Three minutes are over.

श्री अशोक सिद्धार्थः माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कम से कम यह अवश्य चाहूंगा कि दलितों और आदिवासियों के लिए जो फंड का आवंटन हो, उसके लिए ऐसी नीति बनाई जाए, ताकि आज जो प्लान या नॉन-प्लान के विलय में झूल रही है, उसे वहां से हटा करके आवश्यक कानूनी रूप दिया जा सके।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): That is fine.

श्री अशोक सिद्धार्थः मान्यवर, एक मिनट और दीजिए। प्लान और नॉन-प्लान के चक्कर में दलितों और आदिवासियों के लिए जो बजट दिया जाता है, वह एक तरह से सरकार की दया पर निर्भर है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You have made your point. Thank you.

श्री अशोक सिद्धार्थः वह सरकार की दया पर निर्भर न हो करके दलितों और आदिवासियों के लिए इस बजट में उचित व्यवस्था प्रदान करने का काम किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you Mr. Siddharth. You have conveyed your point.

श्री अशोक सिद्धार्थः सरकार में दलित समाज के लोग भी मंत्री हैं और वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You have made your point. Thank you.

श्री अशोक सिद्धार्थः वे सोचें कि आज दलित समाज के साथ जो हो रहा है, तो उनमें जो लोग बैठे हैं, उनके साथ और पूरे दलित समाज के साथ यह सरकार क्या करने जा रही है? इसके लिए उनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Brevity is the soul of wit, Mr. Siddharth.

श्री अशोक सिद्धार्थः मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Now, Shri Ananda Bhaskar Rapolu. You have four minutes.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Respected Vice-Chairman, Sir, being the son of the weaving community, I express my anguish for reducing the Budgetary support to the handloom weaving sector from ₹ 600 plus crore to ₹ 300 crore. Being the son of the Other Backward Classes, I express my anguish about your insensitivity to our demand to have the OBC Sub-Plan. As you have done away with Plan and non-Plan Budgetary approaches, you have safely shelved the Scheduled Castes Sub-Plan and the Scheduled Tribes Sub-Plan. Hence, the demand for Other Backward Classes Sub-Plan is not being taken up seriously. This is the grave concern of more than 50 per cent of the population of India which needs to be addressed by the Union Government immediately. Being the son of Telangana, I would like to flag before you that Telangana is being deprived of the provisions that are supposed to be provided through the enactment and you are also not showing necessary concern towards the provision of schemes and programmes and providing institutes to the Telangana State. At this juncture, my brothers and sisters of Andhra Pradesh are in agitation. Yesterday, they observed total bandh throughout the residuary State of Andhra Pradesh. My colleagues in both the Houses are standing in the Well and agitating and expressing their anguish. Even earlier, I had pleaded with you to have two types of special status programmes for the States – one for the very sensitive hilly areas and another for such States which have real fiscal complications to cater to their necessities.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA) *in the Chair*]

Sir, Andhra Pradesh is one such State which needs to be addressed by you with a special provision of funding and you have to assuage them by giving a new type of special status to Andhra Pradesh State. Then only, the anguish and agitation will subside. Otherwise, it will take the shape of a movement which will become a bigger problem in times to come. आपके शासन काल का अब सिर्फ एक साल बाकी है और चार साल गुजर गए हैं। "कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे" इन चारों सालों की आपकी सत्ता देखने के बाद लोग यह भी सोच सकते हैं कि अगर वर्ष 2014 में वर्तमान प्रधान मंत्री के बदले, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी यदि प्रधान मंत्री बन गए होते, तो बहुत अच्छा होता। यह सोच अभी भी लोगों के दिलों में है, लेकिन बाहर निकलने का साहस नहीं हो रहा है। आपको यह बात समझनी चाहिए। अगर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, प्रधान मंत्री बन कर इस देश की सत्ता को चलाते, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के असली राजधर्म का पालन होता। उसके साथ ही साथ मैं आर्य समाज पद्धति के, ब्रह्मऋषि दयानंद सरस्वती से लेकर पं. दीन दयाल उपाध्याय तक की जो-जो विचारधाराएं हैं, उन्हें मैंने पूरा पढ़ा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप पं. दीन दयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर भी चलने को तैयार नहीं हैं। आपका असली चेहरा अब सामने आ रहा है। इसलिए पूरे देश की जनता आपसे व्यथित है। वह आपके सामने है। You know that. You understand the gravity of the turmoil that is brewing all across the country. Your GDP is not being believed. Your arithmetic is not being believed. And you have the phobia for Pandit Jawaharlal Nehru. Thanks to your memory, *ninda* is also a great *stuti* before the spiritual authority. If you respectfully blame somebody in the form of *ninda stuti*, it will also become a prayer. You are obsessed with Pandit Jawaharlal Nehru. He brought in the mixed economy. He ensured what is there today before you and what you are administering now. Have you ever bothered to look at the necessities of the Indian population? Your GDP cannot cater and it is an established fact by the well-known international economist that GDP calculation is not going to give you the necessary assessment and it will not indicate the progress and development, that is, having what you have mentioned as ease of living. It is not even ease of doing business and it is not even ease of living. In such conditions, what is supposed to be done? Recently, under the parameters of the Inclusive Development Index, seventy-four countries' emerging economies have been considered. In those seventy-four emerging economies, where is India standing?

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आनंद भास्कर जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Please look at it. India is standing at number 62 in the ranking as we are not inclusive economically, as we are not inclusive socially and we are not at all inclusive administratively.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude. ...(*Interruptions*)... Anandaji, your allotted time is over. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: This has become a bigger complication as the doubts are looming large about the calculations of the GDP. I urge upon the Union Finance Minister to look into the possibility of inclusion and assessment of the model under way in the Inclusive Development Index which will show what exact inclusive nature we could attain with our people.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Thank you. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Besides that, I would like to urge upon the Union Government to have federalism in a proper form. You have mentioned about the cooperative federalism but there is nothing in practice before you as the federalism. You are not taking the State Governments on board while considering the requirements and the expectations of the State.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude. ...(*Interruptions*)... Now, Shri Ripun Bora. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Take the case of Telangana as well. This is reflecting your attitude towards the treatment towards a State. Economic federalism is required, cultural federalism is required, social federalism is required and then only the fusion of the political federalism is possible for which your Budget has now reflected which you could not convey.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आनंद भास्कर जी, अब आप कन्क्लूड करिए। Shri Ripun Bora. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: This has taken away the great opportunity before you as only one year is before you. I plead, I suggest, सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु...। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति। जय हिन्द।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Thank you. Shri Ripun Bora.

SHRI RIPUN BORA: Thank you, Sir. You have given me the opportunity at the end.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Five minutes only. ...(*Interruptions*)... Please conclude in five minutes. ...(*Interruptions*)...

SHRI RIPUN BORA: Sir, my humble submission to you is that I am the last speaker of my party and I am the only speaker from the North-Eastern Region, the vast and neglected region. Kindly do not interrupt me. I will speak very briefly and I will not take much time. ...(*Interruptions*)... महोदय, मैं अपनी बात की शुरूआत हमारे

वित्त मंत्री के एक quotation से करता हूं। उन्होंने जब air connectivity के ऊपर बजट दाखिल किया था, तो एयर पोर्ट बढ़ाने के लिए बोला था। उसमें उन्होंने बोला था कि हम लोग इस बजट में हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए हवाई जहाज उपलब्ध करायेंगे। सर, सिर्फ एयरपोर्ट बढ़ा देने से हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए हवाई जहाज उपलब्ध नहीं होगा, जब तक उनके fares कम नहीं होंगे। सर, हवाई चप्पल कौन पहनता है? जो poorest of the poor है, वह इसे पहनता है। वे लोग तीन-चार महीने पहले कभी टिकट बुक नहीं करते हैं। तीन-चार महीने पहले टिकट बुक करने से उनको 3,000 या 4,000 में दिल्ली तक का टिकट मिलता है, लेकिन उन लोगों की मजबूरी है कि उन्हें बीमारी के इलाज के लिए चेन्नई जाने के लिए, मुम्बई जाने के लिए और दिल्ली आने के लिए 24 hours-48 hours के अन्दर टिकट बुक करना होता है। हमारे गुवाहाटी से तो 48 hours में टिकट बुक करने से टिकट का दाम कम से कम 10,000 से 25,000 तक होता है। अभी हकीकत यही है कि यह जो हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी है, उसकी एक साल की कमाई लगभग 20,000 रुपये होती है। इसके बावजूद भी हवाई जहाज में यह जो package है, baggage है, उसमें extra baggage के लिए, 1 Kg के extra baggage के लिए extra 300 रुपये देने पड़ते हैं। इसलिए यह कोई दूसरा कुछ नहीं है, बल्कि यह भी एक सपना है। जैसे मोदी जी का 15 लाख रुपये का सपना था, वैसे ही यह भी हमारे गरीब लोगों के लिए एक स्वप्न के अलावा कुछ नहीं है। Sir, my second point is, the hon. Finance Minister in the Budget...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): You please conclude. आप नियत समय में, दो मिनट आपके पास हैं, उसमें अपनी बात पूरी करिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RIPUN BORA: No, Sir, you have given everybody more time. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपकी पार्टी के 25 मिनट ज्यादा हो गए हैं। अब खत्म करिए। ..(**व्यवधान**)..

SHRI RIPUN BORA: Sir, my second point is that in the Budget, the Finance Minister has very loudly and very proudly said that this is a Budget for the poor and this is a road map for the poor people; this is a road map for the farmers, he said these things. Now, Sir, my questions are: what steps has the Budget taken for increasing the purchasing power of the people? What steps has the Budget taken to control the sky-rocketing prices of all commodities. What steps has the Budget taken to fulfil the promises of the BJP Government to make the prices half if they come to power as what was at the time of the UPA Government. Sir, as a student of economics, I know that higher the circulation of money in the market, the higher the purchasing power of the people. Now, what has the Government done for increasing the purchasing power? They have cut the circulation of money by demonetization; by cashless economy; by digital economy, by imposing restrictions on bank withdrawals and by imposing service taxes in case of withdrawals from the ATMs. So, now, how will this purchasing power increase? On the one hand, we are curtailing the

[Shri Ripun Bora]

purchasing power and on the other hand, we have these sky rocketing prices. So far as the price rise is concerned, I do not want to talk about the other prices but I will only mention about the petrol prices.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude.

SHRI RIPUN BORA: Sir, just two minutes. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): No; only one sentence, the final sentence. ...(*Interruptions*)...

SHRI RIPUN BORA: Sir, you have given everybody five minutes. In 2004, in the international market, when the crude oil price per barrel was 30$, at that time, the petrol price was ₹ 33 to ₹ 38 and the diesel price was ₹ 21 to ₹ 27 and in 2016, when the crude oil price per barrel was 30.53$, the petrol price had gone from ₹ 59 to ₹ 66 per litre and the diesel price had gone from ₹ 44 to ₹ 52 per litre. And, now, the most unfortunate part is that, in this current year, the crude oil price has come down to the level of 2004 but in spite of that the petrol price is here approximately ₹ 73 to ₹ 75 per litre and the diesel price is ₹ 64 to ₹ 65 per litre. Now, Sir, from April, 2014 to March, 2016, prices of crude oil in the international market have fallen by 64 per cent and during this period the excise duty on petrol went up by 126 per cent. Sir, this BJP led NDA Government during their three-and-a-half years of tenure raised the excise duty by nine times and as a result, we the common people are suffering because of the sky rocketing prices. Now, Sir, the hon. Finance Minister is here; Shri Ravi Shankar Prasad is here but Shrimati Sushma Swaraj is not here and the Home Minister is not here. I want to show when during our UPA Government, there was high price, what they have done...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): All the Ministers are here. ...(*Interruptions*)... Please don't show it. ...(*Interruptions*)... Please don’t show it. ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI RIPUN BORA: No, no, Sir, Shri Arun Jaitley is here. He had started agitation all over India by showing gas cylinder...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, I am calling the Finance Minister.

SHRI RIPUN BORA: And, Sushma Swarajji by taking up garland of onion...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): No, not allowed. Nothing will go on record.

SHRI RIPUN BORA: *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Thank you. Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI RIPUN BORA: *

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*)

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Nothing is going on record. Why are you unnecessarily wasting your energy? ...(*Interruptions*)...

SHRI RIPUN BORA: *

OBSERVATIONS BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Nothing shall go on record, both print and electronic. ...(*Interruptions*)... वित्त मंत्री जी, एक मिनट। One minute. ...(*Interruptions*)... Mr. Ramesh, Mr. Venkatesh, Mr. Mohan Rao and Madam, please go to your seats. Please hear my advice. Please go to your seats. Just hear what I am going to say. ...(*Interruptions*)... वित्त मंत्री जी, एक मिनट। Hon. Members, I have something to say to the House and then, the Finance Minister will reply to the Budget and he has some Resolution also to move.

I am saying this with a heavy heart. I hope everybody understands it.

We are coming to the end of the first part of the 245th Session of the Rajya Sabha today and we shall be meeting again after about a month to continue our discussions on the Budget. I must confess that I am deeply pained at the way this Session has progressed. As the Chairman, it is my responsibility because at the end of the day, I am accountable to the people. They will see how the House is conducted, how discussions have gone on. What I am deeply disturbed with is the utter disregard for the parliamentary procedure and the unruly behavior so unbecoming of the high position we occupy in the society as parliamentarians. Dear Members, the question I have been asking myself, and probably many Indians watching us on the television screens would be thinking of, is this: Can we ever make our Parliament an effective instrument of change through informed debates, constructive criticisms and orderly proceedings? I was hoping that we shall collectively strive to uphold and maintain the dignity, sanctity and supremacy of Parliament as we had pledged in 2012 to commemorate the 60th Anniversary of the sitting of the Parliament. I shall still keep hoping that we shall exercise the necessary restraint and behave

* Not Recorded.